रिपोर्ट संख्या 177235–आईएन

निरीक्षण पैनल

निरीक्षण के अनुरोध पर रिपोर्ट और सिफारिश

भारत

विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

(पी096124)

निरीक्षण के लिए तीसरा अनुरोध

21 अक्टूबर, 2022

The Inspection Panel | THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

निरीक्षण पैनल
निरीक्षण के लिए अनुरोध पर
रिपोर्ट और सिफारिश

भारतः विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (पी **096124**)
- निरीक्षण के लिए तीसरा अनुरोध

A. परिचय

1. 12 जुलाई, 2022 को, निरीक्षण पैनल (''पैनल'') को) भारत में विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (पी096124 – ''वीपीएचईपी'' या ''परियोजना'') से संबंधित निरीक्षण के लिए अनुरोध (''अनुरोध'' या ''तीसरा अनुरोध'') प्राप्त हुआ। अनुरोध उत्तराखंड के चमोली जिले के हाट गांव के 83 ग्राम समुदाय सदस्यों (''अनुरोधकर्ताओं'') द्वारा किया गया था। अनुरोधकर्ताओं ने पैनल से अपनी पहचान गोपनीय रखने को कहा और तीन व्यक्तियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया।

2. अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि वीपीएचईपी से उन्हें नुकसान हुआ है – और अभी और होने की आशंका है। उनका दावा है कि परियोजना से संबंधित मलबा डंपिंग उनके भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है। उनकी शिकायत है कि परियोजना ने वैकल्पिक डंपिंग स्थलों की तलाश नहीं की। अनुरोधकर्ताओं ने हाट गांव के परिवारों के पुनर्वास और परिणामस्वरूप आजीविका के नुकसान के बारे में भी चिंता जताई। उनका दावा है कि प्रभावित समुदाय के सदस्यों की शिकायतों को नहीं सुना जाता है। इसके अलावा, उन्हें अपने ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति के नुकसान का डर है और बांध बन जाने पर उसकी सुरक्षा पर सवाल उठाया।

3. पैनल ने पहले इस परियोजना पर निरीक्षण के लिए दो अनुरोधों की समीक्षा की थी। पहला अनुरोध 23 जुलाई, 2012 को प्राप्त हुआ था जिसके बाद पैनल ने जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट 1 जुलाई 2014 को कार्यकारी निदेशक मंडल को सौंपी[1]। 30 सितंबर 2014 को बोर्ड ने पैनल की जांच रिपोर्ट के जवाब में प्रस्तुत प्रबंधन रिपोर्ट और सिफारिश में शामिल कार्य योजना को मंजूरी दी[2]। दूसरा अनुरोध 1 मार्च, 2022 को प्राप्त हुआ। पैनल ने इस अनुरोध को पंजीकृत नहीं किया क्योंकि यह पाया गया कि उसमें उठाई गई चिंताएं 2014 में पहले से ही जांचे गए मुद्दों से संबंधित थीं, और इसने कोई नया सबूत पेश नहीं किया जैसा कि पैनल संकल्प के तहत आवश्यक था। इसलिए पैनल ने 20 अप्रैल, 2022 को दूसरे अनुरोध के संबंध में गैर–पंजीकरण का नोटिस जारी किया[3]।

4. पैनल ने 19 अगस्त, 2022 को तीसरा अनुरोध दर्ज किया, और प्रबंधन ने 21 सितंबर, 2022 को इस अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया (''प्रबंधन की प्रतिक्रिया'' या ''प्रतिक्रिया'') प्रस्तुत की। एक पैनल टीम (''टीम'') ने इसकी पात्रता रिपोर्ट और सिफारिश को सूचित करने के लिए 4–11 अक्टूबर, 2022 के दौरान भारत का दौरा किया।

---

[1] निरीक्षण पैनल, निरीक्षण पैनल, भारत विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जांच रिपोर्ट, 1 जुलाई 2014।

2 विश्व बैंक, विष्णुगाड पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना भारत, ऋण सं. 8078–आईएन), पर निरीक्षण पैनल के जांच के जवाब में प्रबंधन रिपोर्ट और सिफारिश, अगस्त 13, 2014।

3 निरीक्षण पैनल, भारतः विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वीपीएचईपी) (ऋ096124) के निरीक्षण के लिए अनुरोध, निरीक्षण के लिए दूसरा अनुरोध) गैर पंजीकरण की सूचना, अप्रैल 20, 2022।

5. पैनल की स्थापना करने वाले संकल्प के अनुसार[4], इस रिपोर्ट का उद्देश्य बोर्ड को यह सिफारिश करना है कि क्या अनुरोध में आरोपित मामलों की जांच आवश्यक है? पैनल ने निर्धारित किया कि अनुरोधकर्ता और अनुरोध तकनीकी योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि, पैनल का विचार है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो कि परियोजना के परिणामस्वरूप भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को नुकसान के संबंध में लगाया गया मुख्य आरोप है, और यह कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''टीएचडीसी'') और प्रबंधन, दोनों इसे संरक्षित करने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध हैं। पैनल का यह भी विचार है कि परियोजना को किसी भी घरेलू स्तर के आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पैनल ने गौर किया है कि टीएचडीसी और प्रबंधन स्वीकार करते हैं कि पानी की आपूर्ति और वर्तमान जीआरएम में कमियां हैं और वे उन्हें सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए, पैनल इस अनुरोध में लगाए गए आरोपों की जांच की अनुशंसा नहीं करता है।

B. परियोजना का विवरण

6. वीपीएचईपी को 30 जून, 2011 को 92ण्2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी गई थी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ("बैंक") उधारकर्ता – टीएचडीसी को 64.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी भी है और वह शेष 27.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान कर रही है। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।[5] 10–10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के दो रद्दीकरणों[6] के बाद, बैंक द्वारा वित्त पोषण घटकर 44.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया। परियोजना की वर्तमान समापन तिथि 30 जून, 2023 है।

7. परियोजना के विकास के उद्देश्य "(ए) नवीकरणीय, निम्न–कार्बन ऊर्जा को बढ़ाकर भारत की राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि; और (बी) आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से टिकाऊ जलविद्युत परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में उधारकर्ता की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है।"[7]

8. परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (पीएडी) के अनुसार, परियोजना के दो घटक हैं: 1) चमोली जिले, उत्तराखंड, भारत में 444 मेगावाट के जलविद्युत परियोजना का निर्माण, और 2) टीएचडीसी में क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती का समर्थन करना। पहले घटक के तहत बैंक ऋण वीपीएचईपी के निर्माण के लिए विशेष रूप से दो मुख्य अनुबंधों – सिविल कार्यों और हाइड्रो–मैकेनिकल उपकरणों के लिए इंजीनियरिंग–खरीद–निर्माण अनुबंध, और इलेक्ट्रो–मैकेनिकल अनुबंध को वित्तपोषित करता है। यह डिजाइन की डेस्क समीक्षा करने, टीएचडीसी को उसके परियोजना प्रबंधन कार्यों के निष्पादन में सहायता करने और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान टीएचडीसी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सलाहकार को भी वित्तपोषित करता है।[8] पीएडी के अनुसार, टीएचडीसी परियोजना के पहले घटक में "भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण प्रबंधन, लघु–स्तरीय अवसंरचना कार्यों आदि"[9] का वित्तपोषण करता है। दूसरा घटक टीएचडीसी के चल रहे मानव संसाधन विकास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण पहलों पर आधारित है। अनुरोध में उठाए गए मुद्दे पहले घटक से संबंधित हैं।

---

[4] विश्व बैंक निरीक्षण पैनल संकल्प संख्या आईबीआरडी 2020–0004 ("संकल्प"), सितंबर 2020।

5 टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम है जिस पर बहुसंख्य हिस्सेदारी भारत सरकार (जीओआई) और उत्तर प्रदेश राज्य की है। 25 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने अपने शेयर एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी) को बेच दिए। एनटीपीसी भारत सरकार के बहुसंख्यक स्वामित्व वाली कंपनी है। देखें https://www-thdc-co-in/en/content/company&thdcil-

6 ये रद्दीकरण जून 2019 और जून 2021 में हुए थे।

7 विश्व बैंक, विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना (पीएडी) के लिए भारत गणराज्य की गारंटी के साथ टीएचडीसी लिमिटेड इंडिया को 64.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के प्रस्तावित ऋण पर परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, 10 जून, 2011, पेज vi-

8 पैड, पेज 8.

9 पैड, पेज 8.

9. यह एक श्रेणी ए परियोजना है, और निम्नलिखित सुरक्षा नीतियों को ट्रिगर किया गया है: पर्यावरण मूल्यांकन (ओपी/बीपी 4-01), प्राकृतिक आवास (ओपी/बीपी 4-04), भौतिक सांस्कृतिक संसाधन (ओपी/बीपी 4-11), अनैच्छिक पुनर्वास (ओपी/बीपी 4-12)), वन (ओपी/बीपी 4-36), बांधों की सुरक्षा (ओपी/बीपी 4-37), और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर परियोजनाएं (ओपी/बीपी 7-50)। नवंबर 2009 में एक ईआईए तैयार किया गया और इसका खुलासा किया गया।[10] प्रबंधन के प्रत्युत्तर के अनुसार, परियोजना ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की सलाह के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के विस्तार के दौरान 2021 में एक त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (आरईआईए) विकसित किया।[11]

C. अनुरोध का सारांश

10. नीचे दिया गया खंड अनुरोध में उठाए गए मुद्दों का सार प्रस्तुत करता है। अनुरोधकर्ताओं ने नौ सहायक दस्तावेज प्रदान किए,[12] और पूरा अनुरोध इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

11. **कूड़ा डंपिंग और लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर।**[13] अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि हाट गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर ("मंदिर") की स्थापना आदि शंकराचार्य ने नौवीं शताब्दी में की थी। वे कहते हैं कि आदि शंकराचार्य गौड़ ब्राह्मणों को बंगाल से उनके समुदाय के लिए लाए थे[14]। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, मंदिर उनके लिए "एक पवित्र बंधन और विरासत" का प्रतिनिधित्व करता है। वे कहते हैं कि मंदिर के पास अन्य देवताओं – अर्थात् शिव, चंडिका, गणेश और सूर्य कुंड मंदिर भी हैं। इसके अलावा, वे दावा करते हैं कि स्थानीय देवताओं बगडवाल, भीम्याल, हनुमान और बिल्वेश्वर के मंदिर "[उनके] पूर्वजों द्वारा सदियों पहले स्थापित किए गए थे और [उनकी] समृद्ध संस्कृति और संपन्न परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।" अनुरोधकर्ताओं का तर्क है कि प्राचीन काल में, हाट श्री बद्रीनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के मुख्य पड़ाव (मुख्य शिविर) के रूप में था, जिससे यह एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल बन गया। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि "8–9वीं सदी का एक ताम्रपत्र" (तांबे का एक प्राचीन शिलालेख) मौजूद है, जो हाट की प्राचीन ऐतिहासिकता को साबित करता है। अनुरोध में कहा गया है कि हाट ग्राम ग्राम सभा[15] ने 28 मार्च, 2022 को लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य मंदिरों को संरक्षित स्थल घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

---

[10] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पेज. 20.

[1 1] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पेज 26

[12] सहायक दस्तावेजों में शामिल हैं: i) अनुरोधकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में तीन व्यक्तियों को नियुक्त करने वाला हाट ग्राम सभा का संकल्प; ii) हाटगाँव (ग्राम हाट), पीपल कोटि, जिला चमोली में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निरीक्षण नोट शीर्षक से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट; iii) इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) का एक पत्र जिसका शीर्षक है, जलविद्युत परियोजना से तत्काल जोखिम वाले महत्वपूर्ण प्राचीन गाँव और मंदिर स्थल; iv) परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ किए गए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण की 92 व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं; v) सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्नों का अंग्रेजी अनुवाद; vi) तांबे के एक प्राचीन शिलालेख की तस्वीर; vii) लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य मंदिरों को ग्राम सभा द्वारा संरक्षित घोषित करने के लिए हाट ग्राम सभा का एक संकल्प, viii) दो विशेषज्ञों द्वारा एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक है,उत्तराखंड में जलविद्युत के संबंध में दिनांक 25.02.2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक का कार्यवृत्त। गोपनीयता के लिए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का खुलासा नहीं किया गया है।

[13] इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्वयं लक्ष्मी नारायण मंदिर (मंदिर) और मंदिर के आसपास के अन्य छोटे मंदिर शामिल हैं।

[14] गौड़ ब्राह्मण (या गौर ब्राह्मण) बंगाल से और कुछ भारत के उत्तरी क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण हिंदुओं में सर्वोच्च सामाजिक वर्ग हैं।

[15] ग्राम सभा एक ग्रामीण सभा है, जो गांव के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों को अपने निर्णयों पर मतदान करने की अनुमति देती है।

12. अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि 2007 में उनके गांव को परियोजना की गंदगी के लिए डंप साइट के रूप में नामित किया गया था और इसे टीएचडीसी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। समुदाय के सदस्यों का आरोप है कि तब से, वे मंदिर में अपने अनुष्ठान नहीं कर सकते। अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि 2016 के बाद से टनल बोरर मशीन (टीबीएम) द्वारा उत्पन्न टनों मलबे को उनकी विरासत और सांस्कृतिक प्रथाओं पर विचार किए बिना लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे "बमुश्किल 10 मीटर" पर फेंक दिया गया है। उनका दावा है कि मंदिर के पीछे मलबे को सहारा देने वाली दीवार "एक कमजोर पीपे की दीवार है, और गिरने के कगार पर है।" उनका यह भी दावा है कि गांव में मलबा डंपिंग जारी है, और "मलबे की ऊंचाई चंडिका मंदिर और मंदिरों के दूसरे समूह की ऊंचाई को पार कर गई है।" वे चिंता जताते हैं कि 13 किलोमीटर (किमी) दूर हेडरेस टनल (एचआरटी) पर काम शुरू होने के बाद मलबे की ऊंचाई मंदिर से अधिक हो जाएगी। अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि गांव में मलबा डंप करने से लक्ष्मी नारायण मंदिर को "अपरिवर्तनीय विनाश" हो सकता है। अनुरोध मलवा डंपिंग को रोकने और डंपिंग क्षेत्र को मंदिर से दूर स्थानांतरित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक नई रिपोर्ट का हवाला देता है,[16] जो मंदिर से संबंधित संरक्षण उपायों की सिफारिश करता है। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार,टीएचडीसी ने "हाट के गांव और समग्र रूप से राष्ट्र के लिए एक गंभीर अपकार" किया है।

13. अनुरोध का दावा है कि प्राचीन मंदिर की उपस्थिति के कारण गांव को कभी भी "उजाड़ा" नहीं जाना चाहिए था। इसका आरोप है कि टीएचडीसी वैकल्पिक डमप साइटों का पता लगाने में विफल रहा। अनुरोध 2022 के एक अध्ययन का हवाला देता है जिसने एक वैकल्पिक साइट की पहचान की है जो कथित रूप से "न केवल बहुत स्थिर है, 10,000 साल पुरानी चट्टान संरचना पर टिकी हुई है, बल्कि ग़ैर.आबाद और अनुपजाऊ [...] भी है जो नदी के विपरीत बाएं किनारे पर है।"

14. **आजीविका और आर्थिक स्थिति।** अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि टीएचडीसी और हाट गांव के मुखिया और कुछ ग्रामीणों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर "अपने अधिकारों की अज्ञानता में और कानूनी सहायता के बिना" और दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। अनुरोध में कहा गया है कि 2014 की जांच के बाद से उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

15. अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि जिन समुदाय के सदस्यों ने मुआवजा लेने और स्वेच्छा से स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, उन्हें बेदखल कर दिया गया। उनका दावा है कि 22 सितंबर, 2021 को, टीएचडीसी ने "200 से अधिक पुलिस कर्मियों [एसआईसी], 2 पोकलेन एक्सकेवेटर और 1 बुलडोजर के साथ, जबरदस्ती ग्रामीणों के घरों में प्रवेश किया, सामान/घरेलू चीजें बाहर फेंक दीं और उनके घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।" अनुरोध में कहा गया है कि बेदखल किए गए समुदाय के सदस्यों में एक विधवा और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं, और कुछ घरों के मालिक बेदखली के दौरान अनुपस्थित थे। अनुरोध में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को "पुलिस थाने में बंद कर दिया गया था।"

16. फरियादियों का आरोप है कि हाट गांव के पुनर्वास के बाद से 99 फीसदी हाट परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अनुरोध में परियोजना से प्रभावित 92 परिवारों पर अनुरोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किया गया एक सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण शामिल है। अनुरोध सर्वेक्षण के परिणामों का सारांश प्रदान करता है। अनुरोध के अनुसार, 50 परिवारों ने मुआवजा पैकेज को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए अपर्याप्त माना, और 10 परिवारों ने कहा कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला।[17] अनुरोध में आरोप लगाया गया है कि 91 परिवारों – जिसमें एक अनुसूचित जनजाति का प्रतिवादी भी शामिल है. ने

---

[16] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार भारत में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एएसआई पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है। देखेंhttps://asi-nic-in-

[17] अनुरोध में कहा गया है कि चार परिवारों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

– "बहुत दृढ़ता से दोहराया" कि उनका सामाजिक कल्याण, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पुनर्वास से पहले से भी बदतर है। यह यह भी आरोप लगाता है कि समुदाय "अत्यधिक असुरक्षित है, स्थिर आजीविका से वंचित है," और " न केवल आर्थिक नुकसान उन्हें कम आर्थिक स्थिति में लाते रहे लेकिन भूमिए पानीए खेतए बागए चारे और ईंधन तक पहुंच के नुकसान के माध्यम से स्थायी नुकसान हुआ जो भविष्य के विकास की किसी भी संभावना को प्रभावी रूप से रोकता है। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, चूँकि वे पूरी तरह से टीएचडीसी पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं इसलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता खो दी है। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि पुनर्वास से पहले, उनके पास आजीविका के कई अन्य स्रोत थे जो अब उपलब्ध नहीं हैं, और यह कि " पहले हम कम पैसे में बेहतर जीवन जी रहे थे।"

17. अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि पुनर्वास से उनके "सामाजिक ताने–बाने और सामुदायिक जीवन" को नुकसान पहुंचा है। वे "गाँव के सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने" को नष्ट करने का भी आरोप लगाते हैं और "[अपनी, पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" अनुरोध में कहा गया है कि "[---] अब हम बिखरे हुए हैं और बाकी ग्रामीण समुदाय से कटे हुए हैं।"

18. **जल आपूर्ति और वितरण।** अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि पुनर्वासित स्थानों में पानी सीमित है। अनुरोध में कहा गया है कि उपरोक्त सर्वेक्षण का जवाब देने वाले 70 व्यक्तियों को प्रतिदिन केवल दो घंटे तक पानी मिलता है और अतिरिक्त 12 लोगों को प्रतिदिन दो से पांच घंटे पानी मिलता है, जबकि स्थानांतरण से पहले उनके पास पानी की आपूर्ति अविरल थी। अनुरोध पूछता है कि पुनर्वासित स्थानों पर समुदाय के सदस्य "उन सभी आवश्यक चीजों को पुनः प्राप्त करते हैं जो [उनसे, ताजे पानी की तरह ली जाती हैं [---]।"

19. **शिकायत निवारण तंत्र।** उसी सर्वेक्षण में, प्रभावित समुदाय के सदस्यों का तर्क है कि उनकी शिकायतों को नहीं सुना जाता है। वे "असहाय" होने का दावा करते हैं और यह कि "कोई नहीं सुन रहा है"। अनुरोधकर्ताओं ने पैनल टीम को मौखिक रूप से सूचित किया कि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जा रहा है।

20. **बांध सुरक्षा और परियोजना की भौतिक प्रगति।** अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि उत्तराखंड में केदारनाथ (2013) और चमोली (2021) में बाढ़ के उदाहरणों का हवाला देते हुए परियोजना ने जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ते खतरों का हिसाब नहीं दिया है।

21. अनुरोध का दावा है कि एमओईएफसीसी (मार्च 18] 2021] अधिसूचना) के अनुसार यदि किसी परियोजना की भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत से कम है और इसके लिए एक नई पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है, तो संबंधित जन सुनवाई या परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता है। अनुरोध में आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2020 में पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने भौतिक प्रगति को 30 प्रतिशत से कम बताया। अनुरोध में यह भी आरोप लगाया गया है कि टीएचडीसी ने मई 2021 में एमओईएफसीसी को "झूठा दावा" किया कि उसने 51 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल कर ली है।

D. प्रबंधन प्रतिक्रिया का सारांश

22. प्रबंधन की प्रतिक्रिया का सारांश नीचे दिया गया है और पूरी प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

23. प्रबंधन बताता है पैनल की स्थापना करने वाले संकल्प के अनुसार अनुरोध अपात्र है। इसमें कहा गया है कि जांच के लिए अपात्र माने जाने वाले अनुरोधों में एसे संबंधित अनुरोध शामिल हैं जैसे वो
विशेष मामला या मामले जिस पर पैनल ने पूर्व अनुरोध प्राप्त करने पर अपनी सिफारिश पहले ही कर दी है, जब तक कि नए साक्ष्य या पूर्व अनुरोध के समय अज्ञात परिस्थितियों से न्यायोचित न हो।[18] प्रबंधन का मानना है कि बैंक ने अनुरोध द्वारा उठाए गए मामलों पर लागू नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। प्रबंधन का निष्कर्ष है कि बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में विफलता से अनुरोधकर्ताओं के अधिकार या हित न तो सीधे और न ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।[19]

24. **कूड़ा डंपिंग और लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर।** प्रबंधन का कहना है कि परियोजना ने ओपी 4-12 (अनैच्छिक पुनर्वास) का अनुपालन किया है और ओपी 4-11 (भौतिक सांस्कृतिक संसाधन) के अनुरूप है।[20] प्रबंधन की रिपोर्ट है कि 2011 में, हाट गांव को ओपी 4-12 लागू करने वाले प्रतिष्ठित डोमेन के तहत मलवा निपटान स्थल के रूप में अधिग्रहित किया गया था।

रिस्पांस के अनुसार, पूरे गांव को समुदाय के सदस्यों के अनुरोध पर अधिग्रहित किया गया था क्योंकि वे उस भूमि को स्थानांतरित करना चाहते थे जिसका वे नदी के पार स्वामित्व रखते थे। प्रबंधन का कहना है कि गांव के सभी रिहायशी मकान तोड़ दिए गए हैं।[21]

25. प्रतिक्रिया के अनुसार, भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों – लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित – का आकलन परियोजना की तैयारी के हिस्से के रूप में ओपी 4-11 के अनुरूप किया गया था। परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन ने मंदिर को संरक्षित करने की आवश्यकता को पहचाना और परियोजना ने मंदिर परिसर के संरक्षण और उन्नयन के लिए एक विशिष्ट योजना विकसित की।[22]

26. प्रबंधन का कहना है कि 2006 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और 2009 की पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के आधार पर, परियोजना द्वारा उत्पन्न होने वाली मलवा की अनुमानित कुल मात्रा 1-5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम3) थी, और इसकी अनुमानित क्षमता हाट गांव में मलवा निपटान क्षेत्र 282]100 घन मीटर था।[23] प्रबंधन एचआरटी की खुदाई के लिए टीबीएम के उपयोग को बताता है[24] उस समय नहीं माना जाता था। प्रतिक्रिया के अनुसार, 2021 आरईआईए में टीबीएम द्वारा उत्पन्न की जाने वाली मलवा की अतिरिक्त मात्रा के लिए लेखांकन, मलवा डंपिंग आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन शामिल है। आरईआईए ने परियोजना द्वारा लगभग चार मिलियन एम3 पर उत्पन्न होने वाली कुल गंदगी का पुनः अनुमान लगाया, और हाट निपटान स्थल की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन 1-27 मिलियन एम3 पर किया।[25]

27. प्रबंधन का दावा है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर साइट पर किए गए कार्यों से प्रभावित नहीं हुआ है, और भविष्य के कार्यों से प्रभावित होने का कोई खतरा नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि "मंदिर से काफी दूर" हाट में कहीं और मलबा निस्तारण हो रहा है।[26] और राष्ट्रीय नियमों के अनुसार और आवश्यक पर्यावरणीय परमिट के तहत किया जाता है। प्रबंधन का दावा है कि मंदिर के पीछे की गतिविधि मलबा डंपिंग नहीं है, बल्कि पहुंच मार्ग का समर्थन करने वाली ढलान को मजबूत करने के लिए बजरी भरना है। प्रबंधन का कहना है कि एचआरटी के लिए खंडों को डालने वाले कंक्रीट संयंत्र के लिए एक मंच बनाने के लिए मंदिर के दाईं ओर बजरी भी जमा की गई थी। प्रतिक्रिया के अनुसार,

---

[18] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 4, पैरा। 10.

[19] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 19] पैरा। 62-

[20] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 30 और प. 9] पैरा। 29-

[21] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पीपी. 8 और 9, पैरा। 26.

[22] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 9, पैरा। 29.

[23] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 26.

[24] जलविद्युत उत्पादन के लिए एक हेडरेस टनल बांध स्थल पर पानी के सेवन को बिजली घर से जोड़ती है।

[25] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 26.

[26] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 12, पैरा। 34.

इन खंडों को निर्माण में उनके उपयोग तक संयंत्र के चारों ओर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है, और कंक्रीट संयंत्र न तो विस्तार करेगा और न ही मंदिर परिसर से टकराएगा।[27]

28. प्रबंधन का दावा है कि मंदिर के पीछे गेबियन दीवार (100 मीटर लंबी, आधार पर नौ मीटर चौड़ी, कुल मिलाकर 100 मिलीमीटर की परत के साथ मजबूत) न हं रिटेनिंग वॉल का काम कर रही है – और न ही इसे रिटेनिंग वॉल के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था–ं।[28] यह भी दावा किया है कि गेबियन दीवार का निर्माण मंदिर के पीछे की ढलान के किसी भी फिसलन से बचाने के लिए किया गया है।[29]

29. प्रबंधन का कहना है कि टीएचडीसी परियोजना की शुरुआत से ही मंदिर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और समुदाय को इन आश्वासनों को दोहराया है। इसके अलावा, मंदिर क्षेत्र में पहुंच और सौन्दर्य संबंधी चिंताओं के जवाब में, टीएचडीसी परियोजना सुविधाओं को उद्ध्वस्त करने के बाद भूमि और भूनिर्माण को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।[30] प्रतिक्रिया भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के अन्य संरक्षण प्रयासों का वर्णन करती है – जिसमें समुदाय के परामर्श से बिल्व के पेड़ लगाना शामिल है[31], गाँव में छोटे सामुदायिक मंदिरों की रक्षा करना, और छोटे मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निवासियों के निजी घरों में स्थानांतरित करना।[32]

अ

30. **आजीविका और आर्थिक स्थिति।** प्रबंधन अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों को यह कहते हुए स्वीकार नहीं करता है कि इसमें "पद्धति संबंधी कठोरता का अभाव है क्योंकि यह पूरी तरह से स्व–घोषणा पर आधारित है"[33]और यह "लाभ साझा करने, सामुदायिक विकास निधि और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना द्वारा प्रदान किए गए व्यापक समर्थन पर ध्यान नहीं देता है "[34]

31. प्रबंधन का दावा है कि पंचवर्षीय पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) कार्यान्वयन के 2019 के अंत–अवधि के मूल्यांकन में बताया गया है कि समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि प्रति व्यक्ति आय में कृषि से 81 प्रतिशत से अधिक, व्यवसायों से 50 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के रोजगार से 34 प्रतिशत, और दो पुनर्वास स्थान – एलदाना और दासवाना में श्रम गतिविधियों से 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रबंधन का कहना है कि कृषि से प्राप्त आय में पर्याप्त वृद्धि बेहतर कृषि तकनीकों को शुरू करने, और आरएपी कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किए गए गैर–सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारियों से समर्थन के परिणामस्वरूप हुई।[35] जवाब में कहा गया है कि छह हाट परिवारों को छोड़कर, जिन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया था, सभी हाट परिवारों को अवधि के अंत में मूल्यांकन किए जाने तक पुनर्वास स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था, और यह कि 77 घरों में से 94 प्रतिशत, 2017-[36] तक पुनर्वास स्थानों पर चले गए थे। प्रबंधन का कहना है कि "[i] *परियोजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में,* भविष्य में किसी भी बदलाव*ं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब ऐसे परिवर्तनों के स्रोत स्थानांतरण समय सीमा से काफी आगे हो सकते हैं, के लिए परियोजना को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, न ही बैंक नीति के अनुरूप हैं।*"[37]

---

[27] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 12, पैरा। 35.

[28] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 12, पैरा। 36.

[29] एमप्रबंधन प्रतिक्रिया, पी। 10, पैरा। 33.

[30] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 9, पैरा। 27.

[31] बिल्वापेड़ (या सख्त सेब के पेड़) धार्मिक माने जाते हैं। उनके तीन नुकीले पत्ते भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं और धार्मिक समारोहों के दौरान उपयोग किए जाते हैं।

[32] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 9, पैरा। 28.

[33] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 14, पैरा। 39.

[34] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 14, पैरा। 40.

[35] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 15, पैरा। 41 और 42।

[36] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 15, पैरा। 41.

32. प्रतिक्रिया आजीविका बहाली योजना के कार्यान्वयन के अलावा इंगित करती है, कि परियोजना लाभ–साझाकरण तंत्र, प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, आजीविका प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास सहायता, सामुदायिक वनों में ईंधन और चारे की संभावित हानि के लिए शमन उपायों जैसी गतिविधियों, और विधवाओं की पेंशन का समर्थन करती है।[38] प्रबंधन का कहना है कि परियोजना निर्माण अवधि के दौरान ईंधन और चारा इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक वन तक पहुंच के अस्थायी नुकसान की भरपाई के लिए सभी परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को नकद वार्षिकी के रूप में 100 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर भुगतान कर रही है।

33. प्रबंधन का कहना है कि 2011 में, हाट गांव को ओपी 4-12 को लागू करने वाले प्रतिष्ठित डोमेन के तहत अधिग्रहित किया गया था, और समुदाय ने नदी के उस पार के आस–पास के गाँवों में स्वयं को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जहाँ जहां उनके पास स्वंय के भूखंड थे, जिसका अर्थ था कि इससे उन्हें अपने सामाजिक ताने–बाने को बनाए रखने में मदद मिलेगी। "[39]प्रबंधन का दावा है कि टीएचडीसी ने आम संपत्ति संसाधनों का निर्माण किया – जैसे ग्राम पंचायत[40] भवन, एक प्राथमिक स्कूल भवन, और रास्ते – और यह सुनिश्चित करने के लिए घरों को बिजली और पानी की आपूर्ति प्रदान की गई कि समुदाय के पास पुनर्वासित स्थान में सांप्रदायिक संपत्ति बनी रहे और उनके सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखा जाए।[41]

34. बेदखली के संबंध में, प्रबंधन के अनुसार, छह हाट परिवारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए और मुआवजे की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रबंधन का दावा है, "[क] भवनों को खाली करने औरसमर्पण करने के लिए दस वर्षों की अवधि में पर्याप्त नोटिस प्राप्त करने के बाद, अंततः राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, स्थानीय पुलिस के समर्थन से भवनों को अधिग्रहित करना पड़ा "[42] प्रबंधन का कहना है कि सभी घरों का सामान सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और सुरक्षित रखने के लिए टीएचडीसी को सौंप दिया गया था। प्रबंधन के अनुसार, दो को छोड़कर सभी परिवारों ने अपना सामान एकत्र कर लिया है। प्रबंधन का कहना है कि टीएचडीसी ने तीन निवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए थे जिनके पास हाट के बाहर कोई वैकल्पिक आवास नहीं था।[43]

35. **जल आपूर्ति और वितरण।** प्रबंधन का कहना है कि पुनर्वास से पहले हाट समुदाय के पास सीमित पानी था, क्योंकि पानी प्राकृतिक स्रोतों से लाना पड़ता था।[44] प्रबंधन का दावा है कि टीएचडीसी ने दो मुख्य पुनर्वास स्थानों (एलदाना और दसवाना) में सभी घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराया। प्रबंधन की रिपोर्ट है कि उन पुनर्स्थापित स्थानों पर घरेलू जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति वर्तमान में प्रति परिवार 810 लीटर प्रति दिन है, जो राज्य द्वारा निर्धारित कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की न्यूनतम आपूर्ति से अधिक है। प्रबंधन का कहना है कि समुदाय की मांग को पूरा करने के लिए पाइप से पानी की आपूर्ति – प्रारंभिक 20000 लीटर प्रति दिन से बढ़ाकर वर्तमान 64000 लीटर प्रति दिन कर दी गई है।[45] प्रबंधन का कहना है कि टीएचडीसी पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता की निगरानी करता है

---

[37] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 15, पैरा। 41.

[38] प्रबंधन की प्रतिक्रिया, पीपी. 16 और 17, पैरा. 46–53।

[39] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 42.

[40] पंचायत के सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और यह एक स्थानीय स्वशासी संगठन है। पंचायती राज सरकार के निचले स्तरों को शामिल करने वाली शासन की एक प्रणाली है, जिसमें ग्राम पंचायतें (ग्राम सरकारें) प्रशासन की बुनियादी इकाइयों में से हैं।

[41] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 42.

[42] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 32.

[43] प्रबंधन प्रतिक्रिया। पीपी। 33 और 34।

[44] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 17, पैरा। 54.

[45] **प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी.** 17, **पैरा।** 55.

, और छह महीने के अंतराल पर टैंकों को साफ करता है, और यह कि गुणवत्ता जून 2022 में अंतिम निगरानी में स्वीकार्य पाई गई थी।[46]

36. प्रबंधन का मानना है कि पुनर्वासित स्थान पर पानी की कमी समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुचित जल प्रथाओं का परिणाम है।[47] प्रबंधन का दावा है कि कई परिवारों ने अपनी व्यक्तिगत पानी की टंकियों को भरने के लिए सर्विस डिलीवरी लाइन में टैप करने के लिए व्यक्तिगत घरेलू जल पंप स्थापित किए, जो पानी के दबाव और उपलब्ध मात्रा को प्रभावित करता है, जिससे पाइप नेटवर्क के अंत में घर प्रभावित होते हैं। प्रबंधन का कहना है कि टीएचडीसी ने वितरण पाइपों के व्यास को बढ़ाकर टेल एंड हाउसों में पानी की आपूर्ति में वृद्धि की है।[48] प्रबंधन के अनुसार, अनुचित वितरण के मुद्दे को समुदाय द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है, और यह अनुपालन का मामला नहीं है क्योंकि टीएचडीसी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहा है। प्रबंधन का कहना है कि उसने टीएचडीसी को सुझाव दिया था कि वह समुदाय को समान जल वितरण और खपत के लिए एक समाधान खोजने में मदद करे, और समान वितरण और खपत योजना विकसित करने के लिए पुनर्वास स्थानों में जल वितरण और खपत को मापने के साधनों पर विचार करे।[49]

37. **शिकायत निवारण तंत्र।** प्रबंधन रिपोर्ट करता है कि एक वीपीएचईपी जीआरएम 2009 में स्थापित किया गया था। प्रतिक्रिया के अनुसार, जीआरएम कार्यात्मक है, क्योंकि शिकायतें प्राप्त होती हैं और उनका समाधान किया जाता है। टीएचडीसी को अपनी स्थापना के बाद से 330 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 38 फरवरी 2021 और जुलाई 2022 के बीच प्राप्त हुई हैं।[50] व्यथित व्यक्तियों का टीएचडीसी कार्यालयों में जाना जारी रहता है, शिकायतों को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और टीएचडीसी द्वारा प्रबंधित शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। प्रबंधन का दावा है कि टीएचडीसी की टीम में एक प्रधान शामिल है[51]या शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित गांव के एक प्रतिनिधि, और जब शिकायत टीएचडीसी के नियंत्रण या दायरे से बाहर होती है तो जिला प्रशासन से संपर्क किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को पत्र या व्यक्तिगत रूप से संकल्प से अवगत कराया जाता है।[52]

38. प्रबंधन के अनुसार, जीआरएम में एक स्वतंत्र अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) शामिल है और टीएचडीसी के सामाजिक प्रबंधक और भूमि प्रभावित गांवों के प्रधान द्वारा समर्थित है। प्रबंधन का कहना है कि जीआरएम को तीन टीएचडीसी कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया गया है क्योंकि जीआरसी अध्यक्ष ने कोविड–19 महामारी के दौरान इस्तीफा दे दिया था। प्रबंधन का कहना है कि " भूमि प्रभावित गांवों के जीआरसी सदस्यों ने भी मिलना बंद कर दिया क्योंकि कोई भौतिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।"[53]

39. प्रबंधन का कहना है कि टीएचडीसी सात प्रभावित गांवों से ग्राम प्रधानों की नियुक्ति करके जीआरसी को बहाल कर रहा है, और ग्राम प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक सितंबर 2022 के लिए निर्धारित की गई थै। ग्राम प्रतिनिधियों के बोर्ड में शामिल होने के बाद जीआरसी अध्यक्ष की स्थिति को विज्ञापित किया जाएगा।[54]

40. **बांध सुरक्षा और परियोजना की भौतिक प्रगति।** प्रबंधन का कहना है कि वीपीएचईपी बांध की सुरक्षा का आकलन किया गया था और ओपी 4-37 के अनुसार मंजूरी दी गई थी, और टीएचडीसी ने

---

[46] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 18, पैरा। 58.
[47] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 18, पैरा। 59.
[48] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 18, पैरा। 59.
[49] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पीपी. 18 और 19, पैरा। 60.
[50] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 39.
[51] प्रधान ग्राम सभा का मुखिया होता है।
[52] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 39.
[53] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 39.
[54] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 39.

बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति अनुपालन के अतिरिक्त भीउपाय किए हैं।[55] प्रतिक्रिया के अनुसार, वीपीएचईपी से सीधे जुड़े बाढ़ जोखिमों पर विशेष ध्यान देने के साथ कई संचालन प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। प्रबंधन की रिपोर्ट है कि, अलकनंदा नदी की एक अपस्ट्रीम सहायक नदी में दो पनबिजली संयंत्रों के संरचनात्मक नुकसान के बाद, जहां कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई, टीएचडीसी ने वीपीएचईपी के डिजाइन की समीक्षा की और कोफर बांध की ऊंचाई बढ़ा दी।[56] समुद्र तल से 1]246 मीटर की ऊँचाई तक पाँच मीटर। टीएचडीसी ने अधिक मजबूत पूर्व चेतावनी प्रोटोकॉल और एक मानक संचालन प्रक्रिया भी स्थापित की है।[57]

41. प्रबंधन कहता है कि जलविद्युत परियोजनाओं का विकास भारत सरकार के साथ चर्चा और निर्णय का विषय है, और जलविद्युत परियोजनाओं के मूल्य और जोखिम के बारे में चर्चा बैंक नीतियों के अनुपालन के प्रश्न से परे है। प्रबंधन का कहना है कि यह बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं की गई अन्य जलविद्युत परियोजनाओं को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं है।[58]

42. परियोजना की भौतिक प्रगति पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रबंधन की सितंबर 2022 की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि , वीपीएचईपी की भौतिक प्रगति अब 60 प्रतिशत से अधिक है,"[59] जो बैंक ऋण द्वारा कवर किए गए केवल दो परियोजना घटकों पर विचार करने पर "33 प्रतिशत" के अनुरूप है।[60] पर्यावरण मंजूरी पर, प्रबंधन की रिपोर्ट है कि 16 अगस्त, 2022 को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरण मंजूरी में कोई प्रक्रियात्मक अवैधता नहीं थी।[61]

43. **सहमत क्रियाएं।** प्रबंधन का कहना है कि उसने अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए टीएचडीसी के साथ दो कार्रवाइयों पर सहमति जताई है। सबसे पहले, टीएचडीसी सभी डंपिंग साइटों और मंदिर के आस–पास के क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर करने के लिए पौधे लगाने की अपनी योजना को आगे लाएगा, और वर्षा अपवाह के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए टीबीएम प्लेटफॉर्म तक पहुंच मार्ग के साथ अतिरिक्त जल निकासी के लिए नाली का निर्माण करने पर सहमत हुआ है। दूसरा, समुदाय के परामर्श से, टीएचडीसी सभी घरों के लिए पानी की अधिक समान आपूर्ति स्थापित करने के लिए पुनर्वासित स्थानों में पानी के उपयोग की निगरानी ⁄ विनियमन के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने में समुदाय का समर्थन करेगा।[62]

E. पैनल की पात्रता का आकलन, अवलोकन और समीक्षा

44. पैनल की समीक्षा अनुरोध में प्रस्तुत जानकारी, प्रबंधन की प्रतिक्रिया, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से एकत्रित जानकारी और पैनल टीम की भारत यात्रा पर आधारित है।

45. पैनल के सदस्य मार्क गोल्डस्मिथ ने टीम का नेतृत्व किया – जिसमें पैनल की चेयरपर्सन रमानी कुनानायगम, वरिष्ठ संचालन अधिकारी सर्ज सेलवान, जांच अधिकारी अयाको कुबोडेरा और अनुसंधान सहायक रुपेस दलाई शामिल थे – जो 4–11 अक्टूबर, 2022 को पैनल की पात्रता मूल्यांकन को सूचित करने के लिए भारत मेएक मिशन पर थें,।

---

[55] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 42.

[56] एक संदूक बांध पानी के एक शरीर में बनाया गया एक घेरा है ताकि शुष्क कार्य वातावरण बनाने के लिए इसके भीतर के पानी को पंप किया जा सके। कॉफर बांधों का उपयोग आमतौर पर बांधों के निर्माण या मरम्मत के लिए किया जाता है, और आमतौर पर काम पूरा होने के बाद उन्हें तोड़ दिया जाता है।

[57] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पीपी। 42–44।

[58] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पीपी. 45 और 47.

[59] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 47.

[60] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 47.

[61] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 26.

[62] प्रबंधन प्रतिक्रिया, पी. 19, पैरा। 61.

अपनी यात्रा के दौरान, टीम ने नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और बैंक परियोजना कर्मचारियोंतों, परियोजना स्थल पर टीएचडीसी के कर्मचारियों और देहरादून में एएसआई के अधिकारियों से मुलाकात की। टीम ने हाट में अनुरोधकर्ताओं, उनके प्रतिनिधियों और समुदाय के अन्य प्रभावित सदस्यों से भी मुलाकात की। पैनल मूल्यवान जानकारी प्रदान करने और अपने विचार साझा करने के लिए उल्लिखित सभी लोगों की सराहना करता है। पैनल टीम के दौरे के आयोजन में सहायता के लिए, साथ ही साथ COVID–19 रोकथाम और शमन उपायों पर मार्गदर्शन और प्रोटोकॉल साझा करने के लिए नई दिल्ली में विश्व बैंक कंट्री ऑफिस के कर्मचारियों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया जाता है।

46. निम्नलिखित समीक्षा में पैनल संकल्प (उपखंड ई.1), अन्य कारकों पर टिप्पणियों (उपखंड ई.2), और पैनल की समीक्षा (उपखंड ई.) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुरोध की तकनीकी योग्यता के पैनल के निर्धारण को शामिल किया गया है। 3) पैनल की सिफारिश का समर्थन करना।[63]

E.1. तकनीकी योग्यता का निर्धारण

47. पैनल इस बात से संतुष्ट है कि अनुरोध नीचे दिए गए संकल्प के सभी छह तकनीकी योग्यता मानदंडों को पूरा करता है।[64] पैनल नोट करता है कि तकनीकी योग्यता की इसकी पुष्टि, जो अनुरोधकर्ताओं द्वारा व्यक्त किए गए अनुरोध की सामग्री पर काफी हद तक ध्यान केंद्रित करने वाले सत्यापन योग्य तथ्यों का एक सेट है, में अनुरोध में किए गए दावों के पदार्थ का पैनल का मूल्यांकन शामिल नहीं है। -

- मानदंड (ए): "प्रभावित पक्ष में सामान्य हितों या चिंताओं वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और जो उधारकर्ता के क्षेत्र में होते हैं।" अनुरोध भारत में परियोजना क्षेत्र में 83 समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तीन व्यक्तियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया था जिन्होंने अपनी पहचान गोपनीय रखने के लिए कहा था। टीम ने परियोजना स्थल के अपने दौरे के दौरान अनुरोधकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसलिए पैनल इस मानदंड को पूरा मानता है।

- मानदंड (बी): "अनुरोध में यह दावा किया गया है कि बैंक द्वारा अपनी परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के गंभीर उल्लंघन का अनुरोधकर्ता पर एक भौतिकप्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या होने की संभावना है। अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि परियोजना से संबंधित मलवा डंपिंग ने उनके गांव में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों, विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाया है – और नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना वैकल्पिक डंपिंग साइटों का पता लगाने में विफल रही। अनुरोधकर्ता यह कहते हुए अपने पुनर्वास से संबंधित दावा करते हैं, कि पुनर्वास के समझौते पर दबाव के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। वे मुआवजे से इनकार करने वाले समुदाय के सदस्यों को बेदखल करने और उनके ष्सामाजिक ताने–बाने और सामुदायिक जीवनष को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी चिंता जताते हैं। अनुरोध के अनुसार, पुनर्स्थापित समुदाय के सदस्य आर्थिक रूप से भी बदतर हैं। अनुरोध में कहा गया है कि प्रभावित समुदाय के सदस्यों का दावा है कि उनकी शिकायतों को नहीं सुना जाता है। अनुरोधकर्ताओं ने पुनर्वासित स्थानों में पानी की सीमित उपलब्धता का दावा किया है। वे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों और पर्यावरण मंजूरी की नवीनीकरण प्रक्रिया को देखते हुए परियोजना की व्यवहार्यता और बांध की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। पैनल निर्धारित करता है कि यह मानदंड पूरा हो गया है।

[63] संकल्प, पैरा। 13–15 और 29-

[64] संकल्प, पैरा। 13–15 और 29-

- मानदंड (सी): "अनुरोध यह दावा करता है कि इसकी विषय वस्तु प्रबंधन के ध्यान में लाई गई है और अनुरोधकर्ताओं के विचार में, प्रबंधन यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रहा है कि उसने बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओ का पालन किया है या पालन करने के लिए कदम उठा रहा है ं। पैनल को इन मुद्दों के संबंध में अनुरोधकर्ताओं के प्रतिनिधियों और बैंक के बीच पूर्व में पत्राचार प्राप्त हुआ था। अनुरोधकर्ता बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। पैनल मानता है कि यह मानदंड पूरा हो गया है।

- मानदंड (डी): "मामला खरीद से संबंधित नहीं है।" दावे खरीद के मुद्दों को नहीं उठाते हैं और इस प्रकार यह कसौटी पूरी होती है।

- मानदंड (ई): "इस प्रस्ताव [8 सितंबर, 2020] की तारीख से पहले कार्यकारी निदेशकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए, संबंधित ऋण को बंद नहीं किया गया है या पर्याप्त रूप से वितरित नहीं किया गया है या कार्यकारी निदेशकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए या तारीख के बाद अनुमोदित किया गया है। इस संकल्प को संबंधित ऋण को बंद किए जाने की तारीख से पंद्रह महीने अभी तक नहीं हुए हैं। अनुरोध प्राप्त होने के समय, परियोजना सक्रिय थी और 38-54 प्रतिशत वितरित की गई थी। इसलिए यह कसौटी पूरी होती है।

- मानदंड (एफ): "पैनल ने पहले विषय वस्तु पर सिफारिश नहीं की है या, यदि उसके पास है, तो अनुरोध यह दावा करता है कि नए साक्ष्य या परिस्थितियां हैं जो पूर्व अनुरोध के समय ज्ञात नहीं हैं।" पैनल ने पहले परियोजना पर निरीक्षण के लिए दो अनुरोधों की समीक्षा की।[65] पैनल ने नोट किया कि यह तीसरा अनुरोध नए साक्ष्य प्रस्तुत करता है या नई परिस्थितियों का वर्णन करता है जो प) भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों से संबंधित है, और विशेष रूप से यह आरोप है कि मलवा डंपिंग से लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थिरता और अस्तित्व को खतरा है, पप) बिगड़ती आर्थिक स्थिति का आरोप समुदाय के सदस्यों की स्थिति, पपप) समुदाय के सदस्यों द्वारा जल स्रोतों तक सीमित पहुंच का आरोप, और पअ) अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि इन मुद्दों पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। नए सबूतों में एएसआई की एक रिपोर्ट और एक समुदाय द्वारा शुरू किया गया सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण शामिल है। पैनल 2021 में हुई पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से संबंधित दावों को नोट करता है। पैनल ने अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार किया है, और निर्धारित किया है कि जहां तक शेष मुद्दों का संबंध है, अनुरोध ने नए साक्ष्य या परिस्थितियों का दावा नहीं किया जो पूर्व अनुरोध के समय ज्ञात नहीं था। पैनल इस मानदंड को पूरा मानता है।

E.2. इसकी सिफारिश के लिए प्रासंगिक पैनल अवलोकन

48. बोर्ड को अपनी सिफारिश करने और अपनी संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप, पैनल निम्नलिखित पर विचार करता है:

- क्या कथित नुकसान और बैंक की परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं का संभावित गैर–अनुपालन गंभीर प्रकृति का हो सकता है;
- क्या अनुरोध और परियोजना में कथित नुकसान के बीच एक संभाव्य, कारणात्मक संबंध है, और

[65] इस रिपोर्ट का पैरा 3 देखें।

- क्या प्रबंधन ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया के अनुसार मुद्दों से उचित रूप से निपटारा किया है, या गैर–अनुपालन को स्वीकार किया है और अनुरोधकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने वाली उपचारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रस्तुत किया है।

49. पैनल समझता है कि पैनल संकल्प के तहत प्रबंधन की प्रतिक्रिया का उद्देश्य "पैनल को सबूत प्रदान करना है कि उसने बैंक की प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है या उसका पालन करने का इरादा रखता है।"[66] पैनल नोट करता है कि अपनी प्रतिक्रिया में, प्रबंधन अनुरोध की तकनीकी पात्रता मानदंड पर अपनो दृष्टिकोण और विचार प्रदान करता है।[67] पैनल रेखांकित करता है कि पात्रता का मूल्यांकन पैनल का विशेषाधिकार है, और प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी विचार से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। पैनल प्रबंधन के लिए यह विश्लेषण करना अनुपयुक्त मानता है कि पैनल को अपनी प्रतिक्रिया में अनुरोध दर्ज करना चाहिए या नहीं, जो कि उस अनुरोध के लिए सख्ती से जवाब देने का इरादा रखता है।

50. निम्नलिखित खंड में, पैनल कथित नुकसान और अनुपालन पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणियां प्रदान करता है, यह देखते हुए कि ऐसा करने में, यह बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन या इसके कारण होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई निश्चित मूल्यांकन नहीं कर रहा है।

51. भारत की अपनी यात्रा के दौरान, पैनल टीम ने नई दिल्ली और देहरादून में बैंक कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की, और इस अनुरोध के अधीन परियोजना क्षेत्र, हाट और आसपास के गांवों की यात्रा की। पैनल टीम ने हाट में समुदाय और दसवाना, एलदाना, मायापुर और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कॉलोनी में उनके पुनर्वास स्थानों के साथ डेढ़ दिन बिताया।[68] और करीब 100 लोगों से बात की। टीम ने टीएचडीसी के अधिकारियों से भी मुलाकात की और उनके साथ साइट का दौरा किया। पैनल सभी हितधारकों से मिलने और पैनल के साथ खुले तौर पर अपने विचार साझा करने की तत्परता और इच्छा की सराहना करता है।

52. **कूड़ा डंपिंग और लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर।** पैनल टीम ने समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण मंदिर का भ्रमण किया और मंदिर परिसर में अन्य मंदिरों का दौरा किया। समुदाय के सदस्यों ने टीम को बताया कि मंदिर का निर्माण सातवीं और आठवीं शताब्दी के दौरान किया गया था। उनके अनुसार, मंदिर की स्थापना हिंदू धर्म में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। समुदाय के सदस्यों ने कहा कि इस कारण से मंदिर को स्थानांतरित या उठाया नहीं जा सकता है। एक समुदाय के सदस्य ने टीम को बताया कि केवल उनके परिवार के सदस्य ही आंतरिक गर्भगृह में प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और वे कई पीढ़ियों से मंदिर के संरक्षक रहे हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि मंदिर समुदाय के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार का प्रतिनिधित्व करता है।

53. समुदाय के सदस्य ने गर्भगृह में पत्थर और मूर्ति को एक ही डोलोमाइट पत्थर से उकेरा हुआ बताया, जो हाट गांव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और दक्षिण भारत से लाया गया है। इस व्यक्ति ने कहा कि 1800 के दशक में देवता का सिर काट दिया गया था और मंदिर की ऊपरी संरचना टूट गई थी और आंतरिक गर्भगृह के आसपास की इमारत का पुनर्निर्माण किया गया था। समुदाय के सदस्यों ने मंदिर से संबंधित कुछ कहानियों को भी संबंधित किया, जिसमें एक शेर के बारे में भी शामिल है जिसने समुदाय को धमकी दी थी और उसे गर्भगृह के पैर से बांधा हुआ था जहां एक मोटा लोहे का छल्ला बना हुआ है। पैनल को मंदिर के पीछे भी दिखाया गया था जिसे समुदाय के सदस्य मानते हैं कि मूल संरचना के पत्थरो में से एक में दरार है

---

[66] संकल्प, पैरा। 19-

[67] इन विचारों को प्रबंधन प्रतिक्रिया पृष्ठ 4–6] पैराग्राफ 10–15 में विस्तृत किया गया है।

[68] अनुसूचित जनजाति कॉलोनी वह जगह है जहां कुछ अनुसूचित जनजाति के परिवार स्थानांतरित हो गए हैं।

। पैनल नोट करता है कि मंदिर और इसकी परिसर की दीवार के बीच लगभग तीन मीटर है, और इस दीवार और गेबियन दीवार के बीच कुछ और मीटर है (चित्र 1 देखें)।

चित्र 1: गेबियन दीवार और उसके नीचे मंदिर की परिसर की दीवार।

54. पैनल ने जिन अन्य मंदिरों का दौरा किया, वे लक्ष्मी नारायण मंदिर से थोड़ी दूरी पर हैं, और बहुत छोटी संरचनाएं हैं। इनमें भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर और दूसरा भगवान गणेश और सूर्य कुंड शामिल हैं। दोनों अच्छी तरह से संरक्षित थे। पैनल को मंदिर और मंदिरों के बीच पानी के दो स्रोत दिखाए गए थे। समुदाय के सदस्यों के अनुसार, परियोजना की गतिविधियों ने दैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के प्राकृतिक स्रोत को अवरुद्ध कर दिया, और अन्य जल स्रोत को मोड़ दिया, जिसे पवित्र माना जाता है और प्रसाद और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता है, बाद वाला जमीन पर बहता रहता है।

55. समुदाय के साथ बैठकों के दौरान, पैनल को मंदिर तक पहुंच के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में बताया गया। समुदाय के सदस्यों ने कहा कि वे प्रति माह केवल तीन से चार बार या त्योहारों के दौरान मंदिर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कुछ युवकों ने दावा किया कि, रात 8 बजे के बाद मंदिर तक पहुँचने के लिए, उन्हें पुल पार करते समय टीएचडीसी को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। उन्होंने पैनल को यह भी बताया कि जब वे हाट गांव में रहते थे तब मंदिर में पूजा और सामाजिक सभाएं पहले दिन में दो बार होती थीं, अब संभव नहीं हैं क्योंकि वे अब और दूर रहते हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि वे पहले की तरह अकेले मंदिर में पूजा नहीं कर सकतीं, क्योंकि वो टीबीएम प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पुरुष मजदूरों के बारे में अभिज्ञ है। उन्होंने समझाया कि मंदिर को हिलाना या उठाना ष्अपशकुनष् है, और इससे प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी।

उनका मानना है कि 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन हुआ था क्योंकि एक प्राचीन धारी देवी मंदिर को दूसरे बांध के जलाशय को भरने की अनुमति देने के लिए अपने मूल स्थल से उठा लिया गया था।

56. अपनी 2021 की रिपोर्ट में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में हुई थी जबकि आदि शंकराचार्य आठवीं या नौवीं शताब्दी में रहते थे। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य संरचनाएं षकिसी भी पुरातत्व या कलात्मक विशेषताओं से रहित हैं।"[69] टीम के साथ बैठक में एएसआई के अधिकारी ने कहा कि आदि शंकराचार्य मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते थे।[70] एएसआई ने यह भी बताया कि मंदिर को बदल दिया गया था या फिर से बनाया गया था, निचले हिस्से को छोड़कर जिसमें आंतरिक गर्भगृह शामिल था। एएसआई के साथ अपनी बैठक में, टीम को बताया गया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में नामित नहीं किया गया है। एएसआई ने टीम को सूचित किया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे मंदिर भारत के उस हिस्से में आम हैं, यह कहते हुए कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से, मंदिर को ग्रामीणों के वर्तमान स्थान के करीब स्थानांतरित किया जा सकता है।

57. एएसआई ने पैनल टीम को सूचित किया कि मंदिर परिसर के 100 मीटर के भीतर मलवा डंपिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऊपरी तरफ से मलवा फिसलने की संभावना और दृश्य सौंदर्य है। यह पूछे जाने पर कि उसने 100 मीटर की सिफारिश क्यों की, एएसआई ने टीम को बताया कि उसने राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित नियमों को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मंदिर का पुरातात्विक महत्व था।

58. टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में, पैनल टीम को बताया गया कि 2013 2017 और 2022 में तीन एएसआई सर्वेक्षण किए गए थे और सभी ने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मी नारायण मंदिर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि उन्होंने समुदाय को मंदिर के संबंध में तीन विकल्पों की पेशकश कीक) इसे स्थानांतरित करें, ख) इसे ऊपरी सड़क स्तर पर उठाएं, और इसकी रक्षा करें और इसके आस–पास का भूदृश्य बनाएं, या ग) इसकी वर्तमान स्थिति में इसकी रक्षा करें। और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन दिखने के लिए इसके परिवेश को लैंडस्केप करें। प्रबंधन ने पैनल टीम को सूचित किया कि भूनिर्माण डिजाइनों पर समुदाय के साथ एक समझौता किया गया था और टीम को उस बैठक के अप्रैल 2019 के मिनट और डिजाइन दिखाए। कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को बताया कि सितंबर 2022 में उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मलबा डंप करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है और वह इसका सम्मान करेगा और मंदिर की सुरक्षा के लिए एएसआई के निर्देशों का पालन करेगा। टीएचडीसी के अधिकारियों ने कहा कि सभी मामलों में, वे मंदिर की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का सम्मान करेंगे और समुदाय के साथ सहमत लैंडस्केपिंग डिजाइनों को लागू करेंगे।

59 टीएचडीसी के अधिकारियों ने पैनल टीम को सूचित किया कि मंदिर के पीछे गेबियन दीवार एक ब्रेस्ट वॉल है न कि रिटेनिंग वॉल।[71]टीएचडीसी के अधिकारियों के अनुसार एक रिटेनिंग वॉल अपने पीछे डंप की गई सामग्री को सीमित करती है, और इस कारण से ठोस और प्रबलित कंक्रीट से बनी होनी चाहिए। सीढ़ीदार क्षेत्र के नीचे एक ब्रेस्ट वॉल पहुंच मार्ग का समर्थन करती है लेकिन डंप की गई सामग्री को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेस्ट वॉल पानी को इसके माध्यम से रिसने देती है। टीएचडीसी के अधिकारियों ने कहा कि ऐसी दीवारें आम बात हैं। टीम ने देखा कि गेबियन दीवारें आम हैं और परियोजना क्षेत्र में और बाहर उपयोग की जाती हैं। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ;आईआईटीद्ध को परियोजना क्षेत्र में एक और गैबियन दीवार की ताकत की जांच करने के लिए नियुक्त किया था और आईआईटी ने निर्धारित किया कि दीवार अध्ययन में विचार किए गए भार के लिए संतोषजनक थी।

---

[69] एएसआई, लक्ष्मी नारायण मंदिर हाटगाँव (ग्राम हाट), पीपल कोटी, जिला चमोली का निरीक्षण नोट, अप्रैल 2022, पृ. 2 और 3.

[70] एएसआई, लक्ष्मी नारायण मंदिर हाटगाँव (ग्राम हाट), पीपल कोटी, जिला चमोली का निरीक्षण नोट, अप्रैल 2022] पृ. 2 और 4-

[71] पृथ्वी के एक प्राकृतिक बैंक के चेहरे को बनाए रखने के लिए एक छाती की दीवार बनाई गई है। जमीन को फिसलने से बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है।

। पैनल मानता है कि आईआईटी अध्ययन ने विशेष रूप से मंदिर के पीछे गेबियन दीवार की जांच नहीं की। पैनल ने नोट किया कि आईआईटी का अध्ययन टीएचडीसी की गैबियन दीवार को डिजाइन और स्थापित करने की क्षमता की पुष्टि करता है जो इसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।

60. टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को टीबीएम प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा कराया – जो पूरी तरह से स्थापित होने पर 110 मीटर लंबा होगा। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को उस छत को बनाने के लिए संघनित सामग्री दिखाई जहां टीबीएम स्थापित है। टीम ने टीबीएम का दौरा किया और नोट किया कि टीबीएम ने पहले ही 13–किमी एचआरटी शुरू कर दिया है। टीम को बताया गया कि टीएचडीसी ने परिचालन संबंधी कारणों से कुछ समय के लिए टीबीएम का उपयोग बंद कर दिया था। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को वह स्थान भी दिखाया जहां पहले से ही मलबा डाला जा चुका था। पैनल समझता है कि टीएचडीसी का अनुमान है कि फरवरी 2023 के आसपास और लगभग 18 महीनों तक टीबीएम के पूर्ण संचालन में हर महीने लगभग 600–800 मीटर सुरंग खोदी जाएगी। पैनल नोट करता है कि, परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान डंप किए जाने वाले मलवे की मात्रा में काफी वृद्धि होगी।

61. पैनल टीम के साथ एक बैठक में, प्रबंधन ने दोहराया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कोई मलबा नहीं डाला गया और न ही डाला जाएगा, और यह कि मंदिर सुरक्षित है और रहेगा। टीम को सूचित किया गया कि डिजाइन परिवर्तन को शामिल करने के लिए निविदा प्रक्रिया के बाद मलवा निपटान मात्रा का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। प्रबंधन ने टीम को सूचित किया कि आयतन में परिवर्तन के बावजूद, सुरंग के निर्माण से उत्पन्न मलबे को समायोजित करने के लिए मंदिर परिसर से पर्याप्त दूरी पर जगह है। प्रबंधन ने टीम को सूचित किया कि वह टीएचडीसी के साथ चर्चा में रहेगा और मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं की निगरानी करेगा।

62. **आजीविका और आर्थिक स्थिति।** पैनल टीम ने उन गांवों में कई समुदाय के सदस्यों के साथ बात की जहां वे स्थानांतरित हुए थे और सामुदायिक बैठकों के दौरान और उन्होंने अपने विचार साझा करने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आभारी हैं। पैनल ने नोट किया कि कुछ समुदाय के सदस्य मानते हैं कि एक स्थायी नौकरी आजीविका बहाली का एक केंद्रीय हिस्सा है, इस प्रकार एक भ्रम है जिसमें वे टीडीएचसी या इसके ठेकेदारों के साथ स्थायी नौकरियों के लिए आजीविका की तुलना करते हैं। कई समुदाय के सदस्य उनके साथ स्थायी रोजगार चाहते थे और इस बात से निराश थे कि उपलब्ध अधिकांश नौकरियां अस्थायी थीं। उन्होंने कहा कि सामुदाय के युवाओं को रोजगार हासिल करने में कठिनाई हो रही है। टीएचडीसी के लिए काम करने वाले या इसके ठेकेदार जिनके साथ टीम ने बात की थी, वे चिंतित थे कि एक बार निर्माण बंद हो जाने के बाद, वे अपनी नौकरी खो देंगे, या यह कि नौकरियां उनके मौजूदा कौशल सेट से मेल नहीं खातीं और वे और अधिक कर सकते थे। टीएचडीसी के अधिकारियों ने पैनल को सूचित किया कि कार्यरत 533 पीएपी में से 118 हाट गांव से थे (72 टीएचडीसी के साथ और 46 इसके मुख्य ठेकेदार के साथ)। टीम ने देखा कि कई समुदाय के सदस्यों ने टीएचडीसी या इसके ठेकेदारों के साथ काम करने वाले या काम करने वाले परिवार के सदस्य होने का उल्लेख किया।

63. टीम ने महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की, जिन्होंने छह महीने की स्टेनोग्राफी या सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। महिलाओं ने दावा किया कि वे अपने द्वारा सीखे गए कौशल के आधार पर व्यवसाय स्थापित करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक्स और आईटी कौशल का अध्ययन करने वाले 18 युवाओं में से कुछ को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। टीम ने एक ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात की, जिसने कहा कि उसने छह महीने का विद्युत प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से चार दिल्ली में थे।

64. दसवाना और एलदाना (चित्र 2 देखें) में इसके पूर्वाभ्यास के दौरान, समुदाय के सदस्यों ने टीम को बताया कि जब वे हाट गांव में नदी के उस पार रहते थे तो वे उनके स्वामित्व में थे और वहां खेती करते थे। उन्होंने दावा किया कि अब उनके पास खेती के लिए कम जमीन है क्योंकि जब वे स्थानांतरित हुए तो उन्हें अपने खेती के भूखंडों के एक हिस्से पर अपना घर बनाना पड़ा।

समुदाय के सदस्यों ने कहा कि पहले, जब उनके पास पर्याप्त धन की कमी होती थी, तब वे अपने बड़े भूखंडों से उपज पर खुद को बनाए रखते थे। कुछ ने कहा कि उन्हें अपनी गायों और बैलों की संख्या को खत्म करना या कम करना पड़ा क्योंकि चरने के लिए जगह नहीं है और पानी सीमित है। कुछ महिलाओं ने कहा कि उनके पास पहले छह या सात गायें थीं और दूध बेचती थीं, लेकिन अब उनके पास केवल एक या दो हैं। एलदाना में, समुदाय के सदस्यों ने शिकायत की कि टीएचडीसी ने एक पुलिया प्रदान नहीं की और बारिश के दौरान सतही जल अपवाह उनके खेतों में भर गया और 10 से 12 दिनों तक स्थिर रहा। कई महिलाओं ने टीम को सूचित किया कि उन्हें चारा वार्षिकी नहीं मिल रही है और उन्हें चारा इकट्ठा करने के लिए अपने दिन बहुत पहले शुरू करने होंगे। लगभग सभी महिलाओं ने दावा किया कि वे अतिरिक्त आय के लिए बेचने के लिए चाराए जलाऊ लकड़ी और विभिन्न फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में जा रही हैंए जिनमें से एक का उपयोग वे अचार बनाने के लिए करती हैं। उन्होंने कहा कि इन कारकों के कारण उनकी आय में कमी आई है।

चित्र 2: एलदाना का दृश्य।

65. टीम ने नोट किया कि हाट गांव के अधिकांश परिवार नदी के उस पार दसवाना और एलदाना में बस गए थे, जो पड़ोसी गांव हैं। दोनो गांव एक घाटी के बीच एक पगडंडी से जुड़े हुए हैं। एलदाना की सीमाएं मायापुर से लगती हैं, जहां हाट के परिवार भी स्थानांतरित हो गए थे। टीम ने इन गांवों में खेती की जमीन और बगीचों का भी अवलोकन किया और कई घरों में गौशालाएं थीं। टीम ने नोट किया कि कुछ घरों में व्यक्तिगत जल भंडारण टैंक थे। समुदाय के सदस्यों ने टीम को बताया कि दसवाना और एलदाना बस्तियाँ पूरी तरह से उन लोगों से बनी हैं जो पहले हाट गांव में रहते थे।

66. टीम ने टीएचडीसी के अधिकारियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने टीएचडीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के विस्तार को साझा किया, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समुदाय का समर्थन करना शामिल था (उदाहरण के लिए, एक पुरुष और एक महिला चिकित्सक के साथ मुफ्त चिकित्सा सेवाएं स्थापित करना और जागरूकता बढ़ाना मासिक धर्म स्वच्छता पर महिलाओं और लड़कियों के लिए कार्यक्रम), समुदाय के सदस्यों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम (पॉलीहाउस खेती, मधुमक्खी पालन, सिलाई और बुनाई, और प्याज की खेती सहित), चारे के लिए भत्ता और विधवाओं की पेंशन। पैनल ने नोट किया कि हाट के समुदाय के सदस्य कार्यक्रम की पॉलीहाउस खेती और मधुमक्खी पालन आजीविका विकास परियोजनाओं में भाग लेते रहे हैं।

67. टीएचडीसी के अधिकारियों ने पैनल टीम को सूचित किया कि परियोजना वन पंचायत ;वन पंचायतद्ध का उपयोग करने वाले कई गांवों के लगभग 2500 परिवारों को सामुदायिक वन तक पहुंच के लिए वार्षिकी का भुगतान कर रही है और इसमें हाट के पूर्व निवासी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए एक कृषि श्रमिक के दैनिक वेतन के आधार पर सामुदायिक वन तक पहुँचने वाले प्रति परिवार को सालाना 16000 भारतीय रुपये (प्छत्) का भुगतान किया जाता है।[72] यह राशि मुद्रास्फीति के अनुसार नियमित रूप से बढ़ती गई। उन्होंने टीम को बताया कि जून 2024 में निर्माण पूरा होने के साथ वार्षिकी भुगतान बंद हो जाएगा।

68. पैनल ने तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ सलाहकार डीएचवी इंडिया प्रा॰ लिमिटेड और सीटीआरएएन कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा क्रमशः आयोजित परियोजना की मध्यावधि ;2012 और समाप्ति अवधि ;2019 की पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की। समाप्ति अवधि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन पद्धति में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके, माध्यमिक साहित्य और डेटाबेस का विश्लेषण, हितधारक साक्षात्कार और क्षेत्र अवलोकन शामिल हैं। दसवाना, एलदाना और हत्सरी टोले से तिरसठ परिवारों[73] ने इस अध्ययन में भाग लिया। अंतिम अवधि के मूल्यांकन के अनुसार, हाट गांव में प्रभावित आबादी का व्यावसायिक स्वरूप बदल गया था। इस समीक्षा में पाया गया कि जहां कृषि में लगे पीएपी की संख्या में 43-48 प्रतिशत की कमी आई, वहीं सरकारी या निजी रोजगार, व्यापार और व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई।[74]

69. पैनल नोट करता है कि अंतिम अवधि के मूल्यांकन से प्रभावित और विस्थापित आबादी में सभी प्रमुख व्यवसायों या व्यवसायों में परियोजना के बाद की अवधि के दौरान आय में वृद्धि का पता चला। पैनल ने नोट किया कि मूल्यांकन ने "15 वन पंचायत प्रभावित गाँवों में कृषि गतिविधियों की आय में 54-53% की वृद्धि और विस्थापित गाँवों में 81-85% की वृद्धि अर्थात एलदाना और दसवाना में वृद्धि का संकेत दिया। यह एचवाईवी [बीजों की उच्च उपज किस्मों] पर परिचय, भूमि की तैयारी और उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण, एनजीओ से समर्थन और कृषि और बागवानी अधिकारियों के रिसोर्स पर्सन के कारण है। श्रमिकों के आय स्तर में बड़े परिवर्तन देखे गए क्योंकि वन पंचायत प्रभावित गाँवों में 73% और विस्थापित गाँवों में 37-93% की वृद्धि हुई है।[75]

70. **जल आपूर्ति और वितरण।** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंदिर की अपनी यात्रा के भाग के रूप में, टीम को दो जल बिंदु दिखाए गए थे। समुदाय के सदस्यों ने टीम को सूचित किया कि पहले उनके पास प्राकृतिक जल तक निरंतर पहुंच थी जिसका समुदाय द्वारा सामूहिक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता था। उन्होंने कहा कि वे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए एक जल स्रोत का उपयोग करते थे और दूसरे को पवित्र माना जाता था" और औपचारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था।

71. एलदाना और दसवाना गाँवों के अपने दौरे के दौरान, समुदाय ने टीम को परियोजना द्वारा स्थापित पानी की टंकियाँ दिखाईं (चित्र 3 देखें), जिसके माध्यम से प्रत्येक घर में पाइप से पानी की आपूर्ति की जाती है

---

[72] 20 अक्टूबर, 2022 तक, INR 16,000 रूप्ये लगभग 193 डालर के बराबर है।

[73] हाट गांव से सटा हत्सरी टोला हाट के राजस्व गांव का हिस्सा है।

[74] सीटीआरएएन कंसल्टिंग लिमिटेड, वीपीएचईपी के आरएपी कार्यान्वयन की अंतिम अवधि की मूल्यांकन रिपोर्ट निगरानी और मूल्यांकन, जनवरी 2019, पीपी 31–34।

[75] सीटीआरएएन कंसल्टिंग लिमिटेड, वीपीएचईपी के आरएपी कार्यान्वयन की अंतिम अवधि के मूल्यांकन रिपोर्ट की निगरानी और मूल्यांकन, जनवरी 2019, पी। 88.

कुछ समुदाय के सदस्यों ने संकेत दिया कि जल भंडारण केवल प्रति दिन आधे घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त था। दूसरों ने कहा कि उनके पास प्रतिदिन ढाई घंटे पानी की आपूर्ति होती है, जो सुबह और शाम के बीच विभाजित होती है। समुदाय ने पानी की गुणवत्ता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। कुछ समुदाय के सदस्यों ने कहा कि नल का पानी बासी और गंदा है, और उन्होंने प्राकृतिक झरने के पानी के स्रोत को प्राथमिकता दी जो हाट गांव में था और जिसने उन्हें निरंतर आपूर्ति प्रदान की थी। समुदाय के कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती के दौरान पानी के पंप काम नहीं करते हैं और वे तीन या चार दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। समुदाय के साथ कई बैठकों के दौरान, टीम ने सुना कि दसवाना के निवासियों के पास जल कुण्ड तक पहुंच नहीं है[76] चूंकि गांव में पहुंच मार्ग नहीं है।

72. टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि उन्होंने एलदाना में 5000 लीटर के चार भंडारण टैंक और दसवाना[ें], जिसकी आबादी कम है में दो अतिरिक्त 6000 लीटर के टैंक उपलब्ध कराए हैं । अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि इतना पानी प्रत्येक घर को 810 लीटर पानी, या 185 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रदान करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह राज्य द्वारा निर्धारित पानी की न्यूनतम आपूर्ति के तीन गुना से अधिक है, जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर है। टीएचडीसी के अधिकारियों ने संकेत दिया कि जब समुदाय के किसी सदस्य द्वारा पानी की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाता है तो कंपनी पानी का टैंकरप्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रति सप्ताह औसतन एक बार होता है। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि कंपनी पानी के पाइप का व्यास बढ़ाने की योजना बना रही है और निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा टीएचडीसी के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने अधिक स्थायी समाधान तलाशने के लिए राज्य जल प्राधिकरण को नियुक्त किया था।

चित्र 3: एलदाना और दसवाना में पानी की टंकियाँ।

बाउजर एक मोबाइल टैंकर है जो आपात स्थिति में पानी उपलब्ध कराता है।

73. पैनल प्रबंधन और कंपनी के आपसी दृष्टिकोण को नोट करता है कि पुनर्वासित स्थानों में पानी की आपूर्ति या क्षमता के साथ कोई समस्या नहीं है लेकिन पानी की कमी कुछ समुदाय के सदस्यों के अपने पानी के टैंक और पंप होने और टीएचडीसी द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने से उत्पन्न होती है।¨। पैनल ने देखा कि इंजीनियरिंग के माध्यम से समाधान खोजना संभव हो सकता है, और असमान जल उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सामाजिक तनावों को संबोधित करने पर और विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

74. **शिकायत निवारण तंत्र।** समुदाय के साथ बैठकों के दौरान, टीम को पता चला कि कुछ सदस्यों को शिकायत प्रक्रिया या टीएचडीसी में अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक विशिष्ट संपर्क बिंदु के बारे में पता नहीं है। समुदाय के सदस्यों ने टीम को सूचित किया कि जब उन्होंने मोबाइल फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को उठाने का प्रयास किया, तो टीएचडीसी के कर्मचारियों ने शायद ही कभी उनकी कॉल उठाई, या उन्हें टीएचडीसी कार्यालयों तक पहुंचने से मना कर दिया गया। कई समुदाय के सदस्यों ने टीम को सूचित किया कि वे पानी या बिजली के बारे में शिकायत करने से डरते हैं इस चिंता के कारण कि वे टीएचडीसी या इसके ठेकेदार के साथ अपनी नौकरी खो सकते हैं।टीम ने विभिन्न समुदाय के सदस्यों से सुना कि टीएचडीसी या इसके ठेकेदार के लिए काम करने वाले परिवार के सदस्य बैठक में भाग लेने से डरते थे क्योंकि उन्हें कथित रूप से धमकी दी गई थी कि अगर उन्हें पैनल टीम के साथ बात करते हुए देखा गया तो उनकी नौकरी चली जाएगी।

75. प्रबंधन के अनुसार टीएचडीसी के पास एक शिकायत निवारण तंत्र है जिसमें एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का प्रावधान शामिल है। प्रत्युत्तर के अनुसार, पैनल नोट करता है कि जीआरसी वर्तमान में मौजूद नहीं है क्योंकि महामारी प्रतिबंधित शारीरिक बैठकों और जीआरसी की अध्यक्षता करने वाले स्वतंत्र व्यक्ति ने स्थिति छोड़ दी थी। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि कंपनी जीआरसी की अध्यक्षता के लिए एक विश्वसनीय, स्वतंत्र व्यक्ति की भर्ती कर रही है। शिकायतों की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर, प्रबंधन और टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि पहले समुदाय के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे पुनर्वास और पुनर्वास सहायता से संबंधित थे, जबकि वर्तमान में उठाए गए मुख्य मुद्दे बिजली, पानी की आपूर्ति, रोजगार और पहुंच के बारे में और टीएचडीसी अस्पताल और पंचायत सुविधा के लिए हैं।

76. टीएचडीसी के अधिकारियों के अनुसार, टीएचडीसी के साथ बैठक के दौरान, टीम को त्रैमासिक बैठकों के लिए शिकायत रजिस्ट्री दिखाई गई, जिनमें से अंतिम मई 2019 में कोविड–19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण आयोजित की गई थी। टीएचडीसी ने टीम को बताया कि समुदाय के सदस्य अक्सर अपनी चिंताओं और शिकायतों को उठाने के लिए टीएचडीसी के कर्मचारियों को फोन करते हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। टीएचडीसी के अधिकारियों ने टीम को सूचित किया कि वे शिकायतों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी एक स्टाफ सदस्य को सौंपेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया तदर्थ है और इसे सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

77. पैनल मानता है कि प्रबंधन ने परियोजना को सूचित किया है कि समुदाय के सदस्य जो कंपनी के लिए काम करते हैं और परियोजना के बारे में शिकायत करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रतिशोध का अनुभव नहीं करना चाहिए और रोजगार अनुबंधों को कंपनी और उसके ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थानीय लोगों को सामुदायिक बैठकों में भाग लेने से या आम, सामुदायिक चिंताओं को उठाने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए ।

78. **पर्यावरणीय निकासी।** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पैनल टीम ने परियोजना स्थल का दौरा किया। इस साइट के दौरे में कॉफर बांध, बांध स्थल पर नदी को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, तीन 400 मीटर लंबी गाद निकालने वाली सुरंगें, बिजलीघर के लिए 250 मीटर लंबी और 42 मीटर गहरी गुफा का स्थान और ट्रांसफार्मर के लिए छोटी गुफा। पैनल देखता है कि इस काम में से अधिकांश पहाड़ में है और बाहर से दिखाई नहीं देता है, और एचआरटी के अपवाद के साथ, काम अच्छी तरह से उन्नत हैं।

79. टीम के साथ एक बैठक में, टीएचडीसी ने संकेत दिया कि उसने अगस्त 2021 में पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर ली और 10 साल के लिए मंजूरी दे दी गई। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, एमओईएफसीसी ने कंपनी को आरईआईए विकसित करने की सलाह दी। टीएचडीसी के अधिकारियों के अनुसार इसके लिए परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। पैनल ने देखा कि टीम के दौरे के दौरान अनुरोधकर्ताओं ने पर्यावरण मंजूरी जारी करने पर चिंता नहीं जताई।

80. पैनल समझता है कि पर्यावरण मंजूरी की वैधता को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई थी, जिसने टीएचडीसी के पक्ष में फैसला सुनाया था। पैनल ने नोट किया कि पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया को अदालतों में चुनौती दी गई और कानूनी माना गया। पैनल इस मुद्दे को बंद मानता है।

E.3. पैनल की समीक्षा

81. पैनल अनुरोधकर्ताओं की गंभीर चिंताओं को स्वीकार करता है और हाल की पात्रता यात्रा के दौरान प्राप्त अतिरिक्त जानकारी और उनके साथ उत्पादक चर्चाओं के साथ–साथ पैनल की प्रक्रिया में उनके द्वारा रखे गए भरोसे की सराहना करता है। पैनल अनुरोध में उठाए गए मुद्दों पर प्रबंधन की विस्तृत प्रतिक्रिया और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की उसकी इच्छा को भी स्वीकार करता है।

82. **कूड़ा डंपिंग और लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर।** पैनल टीम ने देखा कि मंदिर और आसपास के मंदिरों को संरक्षित किया गया है और उन पर या उनके आस–पास कोई मलबा नहीं डाला जा रहा है। पैनल लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए प्रबंधन और टीएचडीसी की प्रतिबद्धता को नोट करता है, जिसे पैनल की 2014 की जांच रिपोर्ट में भी मान्यता दी गई है।[77] पैनल ने मंदिर परिसर के पास मलवा डालने के संबंध में उत्तराखंड के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए प्रबंधन और टीएचडीसी की प्रतिबद्धताओं को नोट किया और कहा कि मंदिर की सुरक्षा कैसे की जाएगी, इस पर परियोजना एएसआई के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए सहमत हुई है। पैनल ने निर्माण के बाद हाट गांव में पवित्र जल के स्रोत को बहाल करने के लिए टीएचडीसी की प्रतिबद्धता को भी नोट किया। पैनल आगे उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के फैसले से स्वतंत्र लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए प्रबंधन की दोहराई गई प्रतिबद्धता को नोट करता है।

83. हाट साइट पर मलवा डंपिंग के लिए परियोजना की वर्तमान और भविष्य की योजना पर सावधानीपूर्वक विचार करने और हाट गांव मे दृश्य अवलोकन के बाद, पैनल यह नहीं मानता है कि मंदिर परिसर को नुकसान हुआ है। इसके अलावा, पैनल टीएचडीसी और प्रबंधन द्वारा मंदिर परिसर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए की गई प्रतिबद्धताओं और टीएचडीसी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता से संतुष्ट है, विशेष रूप से उस अवधि के दौरान जब टीबीएम एचआरटी को बोर कर रहा है।

84 **आजीविका और आर्थिक स्थिति।** पैनल ने नोट किया कि पैनल की 2014 की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय हाट समुदाय ने नदी के दूसरी तरफ स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए कहा था, और अधिकांश पुनर्वास पहले ही हो चुका था। पैनल ने यह भी नोट किया कि कई समुदाय के सदस्यों ने पुष्टि की कि वे उस क्षेत्र में हाट गांव से नदी के उस पार की भूमि पर खेती करते थे जहां वे वर्तमान में (दसवाना और एलदाना गांव) में स्थानांतरित हो गए हैं। पैनल ने यह भी देखा कि पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रम की 2019 परियोजना की अंतिम अवधि की मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चलता है कि विस्थापित आबादी के सभी प्रमुख व्यवसायों या व्यवसायों के लिए परियोजना के बाद की अवधि में आय में वृद्धि हुई है।

पैनल मानता है कि आर्थिक नुकसान के दावे पुनर्वास होने के कई साल बाद और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के पूरा होने के तीन साल बाद आते हैं, जो वास्तव में यह निर्धारित करता है कि आजीविका बहाल कर दी गई है, और इसलिए इसे परियोजना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

85 **जल आपूर्ति और वितरण।** पैनल ने नोट किया कि परियोजना ने एल्दाना और दसवाना के गांवों में पाइप से पानी उपलब्ध कराया है और क्षमता राज्य द्वारा प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी की निर्धारित न्यूनतम आपूर्ति से तीन गुना से अधिक है। इसके अलावा, यदि समुदाय का कोई सदस्य जल आपूर्ति की समस्या का अनुभव करता है और कंपनी को इसकी रिपोर्ट करता है, तो एक आपातकालीन पानी का टैंकरप्रदान किया जाता है। पैनल इस विचार से सहमत है कि आपूर्ति किए गए पानी के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। पैनल टीएचडीसी द्वारा अधिक स्थायी समाधान खोजने के लिए राज्य जल प्राधिकरणों के साथ संलग्न होने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय के सभी घरों के सदस्यों को पानी की अधिक समान पहुंच बनाने के लिए पुनर्वासित स्थानों में पानी के उपयोग की निगरानी और विनियमन के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की प्रबंधन की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है।[78]

86. पैनल इस बात से सहमत है कि दसवाना और एलदाना गाँवों को आपूर्ति किए जाने वाले पानी और हाट गाँव में उपलब्ध पानी में अंतर है। जबकि पानी अब प्रत्येक घर में सीधे पाइप से जाता है, पिछली पहुंच सामूहिक रूप से उपयोग किए जाने वाले मुक्त–बहते जल स्रोत से थी। पैनल इस बदलाव को कोई नुकसान नहीं मानता है। पैनल नोट करता है कि प्रबंधन की प्रस्तावित कार्रवाई का उद्देश्य वितरण समस्याओं का समाधान करना है।

87. **शिकायत निवारण तंत्र।** पैनल ने देखा कि केंद्रीय संपर्क बिंदु, एक परिभाषित प्रक्रिया और जहां रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से दर्ज और बनाए रखा जाता है, के साथ कोई औपचारिक तंत्र नहीं है। पैनल ने पाया कि शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया न तो सुसंगत थी और न ही अच्छी तरह से दर्ज की गई थी। पैनल नोट करता है कि नियमित हितधारक बैठकें होती हैं जहां समुदाय के विचारों को रिकॉर्ड किया जाता है। पैनल मानता है कि टीएचडीसी ने हाल ही में दो अनुभवी सामुदायिक सहायकों को काम पर रखा है और हाट गांव के दो सदस्य सामुदायिक संपर्क कर्मियों के रूप में हैं। पैनल आगे नोट करता है कि समुदाय के सदस्यों के पास टीएचडीसी प्रबंधन टीम के कई सदस्यों के मोबाइल नंबर हैं, जो उनकी कॉल का जवाब देते हैं, हालांकि तदर्थ आधार पर।

88. पैनल नोट करता है कि प्रबंधन और टीएचडीसी दोनों एक अधिक व्यवस्थित जीआरएम प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता को पहचानते हैं। पैनल समझता है कि तंत्र में जीआरसी शामिल है, जिसका संचालन महामारी और उसके **प्रमुख द्वारा** छोड़ी गई रिक्ति से बाधित था। पैनल जीआरसी की अध्यक्षता करने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति की भर्ती के लिए टीएचडीसी की प्रतिबद्धता और जीआरएम प्रणाली को मजबूत करने के लिए टीएचडीसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है।

F. अनुशंसा

89. पैनल नोट करता है कि अनुरोधकर्ता और अनुरोध पैनल संकल्प में निर्धारित तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निष्कर्ष में और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, पैनल का मानना है कि परियोजना के परिणामस्वरूप मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पैनल ने मंदिर परिसर के संरक्षण के लिए टीएचडीसी और प्रबंधन दोनों की मजबूत प्रतिबद्धताओं को भी नोट किया। पैनल ने नोट किया कि कुछ समुदाय के सदस्यों की यह गलत धारणा है कि एक स्थायी नौकरी आजीविका की बहाली के बराबर है। पैनल का मानना है कि 2019 में समाप्त हुई एंड–टर्म रिसैटलमेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट में घरेलू स्तर के आर्थिक नुकसान को डेटा द्वारा समर्थित नहीं किया गया है।

और यह कि कई बाहरी कारकों ने अंतिम अवधि के मूल्यांकन के बाद से तीन वर्षों में कथित नुकसान को प्रभावित किया हो सकता है। पैनल का मानना है कि किसी भी कथित नुकसान को परियोजना से नहीं जोड़ा जा सकता है। पैनल ने नोट किया कि समुदाय ने स्थानांतरित करने के लिए स्थान खुद चुना और दसवाना और एलदाना को पानी की आपूर्ति की जाती पैनल नोट करता है किटीएचडीसी और प्रबंधन ने स्वीकार किया कि जलापूर्ति में कमियां हैं औरइसमें सुधार के लिए प्रतिबद्धताएं हैं। पैनल मौजूदा जीआरएम को प्रोजेक्ट की कमजोरी मानता है। हालांकि, इसे प्रबंधन और टीएचडीसी द्वारा भी स्वीकार किया गया है और इसे संबोधित करने के लिए प्रतिबद्धताएं मौजूद हैं।

90. उपरोक्त कारणों से, पैनल निरीक्षण के अनुरोध में उठाए गए मामलों की जांच की अनुशंसा नहीं करता है। यदि कार्यकारी निदेशक मंडल इस सिफारिश से सहमत होता है, तो पैनल तदनुसार अनुरोधकर्ताओं को सलाह देगा।

भारत : विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) (पी096124) के निरीक्षण पैनल समीक्षा के लिए अनुरोध (निरीक्षण के लिए तीसरा अनुरोध) पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

प्रबंधन ने भारत के निरीक्षण के लिए अनुरोध की समीक्षा की है: विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वीपीएचईपी) (पी096124) (निरीक्षण के लिए तीसरा अनुरोध), 12 जुलाई, 2022 को निरीक्षण पैनल द्वारा प्राप्त किया गया और 19 अगस्त, 2022 को पंजीकृत किया गया (आरक्यू22/04)). प्रबंधन ने निम्नलिखित प्रतिक्रिया तैयार की है।

21 सितम्बर , 2022

अंतर्वस्तु

संक्षिप्ताक्षर एवं आद्याक्षर शब्द ..... चतुर्थ

कार्यकारी सारांश ..... वि

I. परिचय 1

II. अनुरोध 1

III. परियोजना पृष्ठभूमि 2

IV. पात्रता विचार 4

V. प्रबंधन की प्रतिक्रिया 7

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1. दावे और प्रतिक्रियाएं

अनुलग्नक 2. उन्नत मंदिर परिसर की निर्माण बाद लैंडस्केपिंग योजना

अनुबंध 3. गेबियन दीवार की इंजीनियरिंग डिजाइन

नक्शा

नक्शा 1. आईबीआरडी संख्या 35230

फोटो

फोटो 1. मंदिर परिसर और आसपास के परियोजना कार्यों की हवाई तस्वीर (26 अगस्त, 2022)

फोटो 2. कंक्रीट कास्टिंग संयंत्र को समायोजित करने के लिए प्लेटफॉर्म

फोटो 3. दाईं ओर पहुंच मार्ग और बाईं ओर मंदिर परिसर (दृश्यमान नहीं) के साथ गेबियन दीवार का क्रॉस सेक्शन दृश्य

फोटो 4. गेबियन दीवार के पीछे का दृश्य (मंदिर परिसर की लाल छत दिखाई देती है)

फोटो 5. एलदाना पुनर्वास कालोनी में निजी आवासों के ऊपर व्यक्तिगत जल भंडारण टैंक

फोटो 6. कोफर डैम की बढ़ाई गई ऊंचाई

संक्षिप्ताक्षर एवं आद्याक्षर शब्द

एएसआई	भारती; पुरातत्व सर्वेक्षण
बीपी	बैंक प्रक्रियाएं
सीआईए	संचयी प्रभाव आकलन
सीएम	सेंटीमीटर
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईएसी	पर्यावरण मूल्यांकन समिति
ईएपी	आपातकालीन कार्य योजना
ईसी	पर्यावरणीय मंजूरी
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
जीआरएम	शिकायत निवारण तंत्र
जीडब्लूएच	गीगावाट घंटा
एचसीसी	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी
एचईपी	पनबिजली संयंत्र
एचआरटी	हेडरेस सुरंग
आईबीआरडी	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
इन्टैक	भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट
आईपीएन	निरीक्षण पैनल
केएम	किलोमीटर
एम	मीटर
एम3	घनमीटर
एमएएसएल	समुद्र स्तर से ऊपर मीटर की दूरी
एमएम	मिलीमीटर
एमओईएफसीसी	पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूआरजीआर	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय
एमडब्लू	मेगावाट
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल
ओपी	परिचालनात्मक नीति
ओपीएन	परिचालनात्मक नीति नोट
पीएपी	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
आर एंड आर	पुनर्व्यवस्था और पुनर्वास
आरएपी	पुनर्व्यवस्था कार्य योजना
आरसीसी	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट
आरईआईए	त्वरित पर्यावरण प्रभाव आकलन
एसएलएओ	विशेष भूअधिग्रहण अधिकारी
टीबीएम	सुरंग बोरिंग मशीन
टीएचडीसी	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल के रूप में भी संदर्भित)
वीपीएचईपी	विष्णु पीपलकोटी पनबिजली परियोजना

मुद्रा इकाई – भारतीय रुपया (आईएनआर)

21 सितंबर, 2022 को

1-00 अमेरिकी डॉलर = 79-49 रुपये

कार्यकारी सारांश

परियोजना

i. ***विष्णुगढ पीपलकोटी जलविद्युत प्रोजेक्ट (वीपीएचईपी) भारत के उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की रन–ऑफ–रिवर जलविद्युत उत्पादन परियोजना है।*** *परियोजना के बैंक द्वारा वित्त पोषित घटक हैं : (ए) वीपीएचईपी का निर्माण (438 मिलियन अमेरिकी डॉलर); और (बी) कार्यान्वयन एजेंसी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (यूएस + 10 मिलियन) की क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती के लिए तकनीकी सहायता।*

ii. ***वीपीएचईपी के उद्देश्य हैं :*** *(ए) अक्षय, कम कार्बन ऊर्जा के विस्तार के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि; और (बी) आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से स्थायी जलविद्युत परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में टीएचडीसी की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना। वीपीएचईपी से संयंत्र संचालन अवधि के दौरान प्रति वर्ष लगभग 1-6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद है। ?*

iii. ***वीपीएचईपी के निरीक्षण के लिए यह तीसरा अनुरोध है।*** *पैनल को पहले इस परियोजना पर निरीक्षण के लिए दो अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पहला अनुरोध 23 जुलाई, 2012 को और दूसरा 1 मार्च, 2022 को प्राप्त हुआ। पैनल ने पहले अनुरोध की जांच की और 1 जुलाई, 2014 को एक जांच रिपोर्ट जारी की। प्रबंधन निम्नलिखित के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करता रहा है– जांच के जवाब में कार्रवाई। दूसरा अनुरोध निरीक्षण पैनल द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया था क्योंकि यह निरीक्षण पैनल संकल्प के तहत आवश्यक चिंताओं को नए साक्ष्य के रूप में नहीं मानता था।*

iv. ***पैनल ने 19 अगस्त, 2022 को यह तीसरा अनुरोध दर्ज किया। पैनल के पंजीकरण के नोटिस में कहा गया है कि अनुरोध नए साक्ष्य प्रस्तुत करता है या नई परिस्थितियों का वर्णन करता है जो इससे संबंधित है :*** *(ए) भौतिक सांस्कृतिक संसाधन और यह आरोप कि मलबा डंपिंग से लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थिरता और अस्तित्व को खतरा है; (बी) समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का आरोप; और (सी) समुदाय के सदस्यों द्वारा पानी की आपूर्ति तक सीमित पहुंच का आरोप।*

प्रबंधन की प्रतिक्रिया

v. ***प्रबंधन के विचार में, यह अनुरोध निरीक्षण पैनल की स्थापना करने वाले बोर्ड के संकल्प में निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है जिसके लिए नए साक्ष्य या परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जो पूर्व अनुरोध के समय ज्ञात नहीं है।*** *इस तीसरे अनुरोध में उन मुद्दों को शामिल किया गया है जिनकी या तो 2014 में पहले ही जांच की जा चुकी थी, या वे मुद्दे जो मार्च 2022 में दूसरे अनुरोध में उठाए गए थे, और जिन्हें पैनल ने नए साक्ष्य या परिस्थितियों के रूप में योग्य नहीं माना। जबकि यह तीसरा अनुरोध नया संलग्न है*

दस्तावेज़, ये न तो मामले के लिए मूल हैं, और न ही इनमें कोई नया साक्ष्य या प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जैसा कि संकल्प द्वारा आवश्यक है।

vi. ***प्रबंधन ने अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और गैर–अनुपालन और नुकसान के आरोप से सहमत नहीं है।*** *प्रबंधन की दृष्टि में, बैंक ने अनुरोध द्वारा उठाए गए मामलों पर लागू नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। जबकि प्रबंधन अनुरोध में उठाई गई सामुदायिक चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखता है, यह नोट करता है कि ये चिंताएं परियोजना से उत्पन्न नहीं होती हैं, परियोजना गतिविधियों की गलतफहमी पर आधारित होती हैं, और उन मुद्दों से संबंधित होती हैं जिनकी पहले समीक्षा की जा चुकी है और उनका समाधान किया जा चुका है। प्रबंधन नीचे दिए गए मुद्दों पर निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं और स्पष्टीकरण प्रदान करता है।*

vii. ***लक्ष्मी नारायण मंदिर को कथित खतरा :*** **लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थल पर हुए कार्यों से न तो प्रभावित हुआ है और न ही भविष्य के कार्यों से प्रभावित होने का खतरा है।** मंदिर से कुछ दूरी पर होने वाले कूड़ा निस्तारण से मंदिर को कोई खतरा नहीं है। मंदिर के पीछे या उसके आस–पास कोई मलबा न तो डाला जा रहा है और न ही डाला जाएगा। प्रबंधन ने हवाई तस्वीरें भी शामिल की हैं, जो दर्शाती हैं कि मंदिर के पीछे कोई मलबा नहीं फेंका गया है।

viii. **अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर को मलबा डंपिंग से खतरा है, जो मंदिर के आसपास होने वाली परियोजना गतिविधियों की गलतफहमी से उपजा है।** अनुरोधकर्ता गलती से मंदिर के पीछे "कूड़ा डंपिंग" के रूप में पहचान करते हैं, वास्तव में मंदिर के पीछे ढलान को भरने और मजबूत करने के लिए उपयोग की जाने वाली बजरी है, जो सुरंग खोदने वाली मशीन (टीबीएम) के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंच मार्ग का समर्थन करती है। टीबीएम प्लेटफॉर्म के नीचे भराव सामग्री दोनों तरफ वनस्पति ढलानों और पहाड़ी के तल पर कुछ वनस्पतियों से बंधी है। मंदिर के पीछे गेबियन दीवार गंदगी के लिए एक बनाए रखने वाली दीवार नहीं है और उचित जल निकासी सहित अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। वर्षा का अपवाह पहुंच मार्ग के साथ पास के प्राकृतिक नाले में प्रवाहित होता है, ताकि ढलान को फिसलने से रोका जा सके। इसके अलावा, टीएचडीसी ने पहुंच सड़कों के किनारे जल निकासी का निर्माण करने और खंड को फिर से लगाने की योजना बनाई है।

ix. **परियोजना की तैयारी के भाग के रूप में, लक्ष्मी–नारायण मंदिर सहित भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का मूल्यांकन ओपी 4-11 के अनुरूप किया गया था।** परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) ने मंदिर को संरक्षित करने की आवश्यकता को पहचाना और परियोजना ने मंदिर परिसर के संरक्षण और उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएँ विकसित कीं। टीएचडीसी ने 2013 और 2017 में लक्ष्मी नारायण मंदिर का और आकलन करने के लिए पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण/संरक्षण के लिए देश के सक्षम निकाय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नियुक्त किया। सरकार के अनुरोध पर, एएसआई ने 2022 में मंदिर का एक और सर्वेक्षण किया। ये आकलन मंदिर की समग्र अवनति की पुष्टि करते हैं। अनुरोध के दावे के विपरीत, एएसआई का यह निष्कर्ष नहीं है कि हाट को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। मंदिर की उम्र के बारे में एएसआई का आकलन भी मंदिर के आदि शंकराचार्य (एक वैदिक विद्वान और शिक्षक) से संबंध के अनुरोधकर्ताओं के दावे का खंडन करता है।

x. ***सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कथित गिरावट : परियोजना द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन और बैंक द्वारा समीक्षा किए गए कथित "समुदाय के सदस्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति" का समर्थन नहीं करते हैं।***

परियोजना ने लक्षित और अनुकूलित शमन उपायों को प्रायोजित किया है, जो स्थानीय समुदायों पर परियोजना के संभावित सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन करने वाले कई अध्ययनों पर आधारित थे। पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) के लिए अंतिम अवधि की मूल्यांकन रिपोर्ट में हाट गांव के विस्थापित परिवारों के सभी प्रमुख व्यवसायों में बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता चलता है, जो परियोजना के बाद के परिदृश्य में नहीं बदले हैं।

xi. **पुनर्वास के बाद के मूल्यांकन में 7 भूमि प्रभावित गांवों में कृषि से प्रति व्यक्ति आय में 37 प्रतिशत, व्यापार से 50 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 11 प्रतिशत और श्रम क्षेत्र में 42 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई।** एलडाना और दसवाना (पुनर्वास कॉलोनियां जिनमें हाट के ग्रामीण चले गए) में, रिपोर्ट में कृषि से प्रति व्यक्ति आय में 81 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, व्यवसाय से 50 प्रतिशत की वृद्धि, निजी क्षेत्र के रोजगार में 34 प्रतिशत और श्रम से 38 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। गतिविधियाँ। कृषि से प्राप्त आय वाले लोगों के लिए पर्याप्त वृद्धि को कृषि तकनीकों में सुधार और आरएपी कार्यान्वयन के लिए किराए पर लिए गए गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और सरकारी अधिकारियों के समर्थन के परिणामस्वरूप नोट किया गया था।

xii. ***प्रबंधन नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में पद्धतिगत कठोरता का अभाव है क्योंकि यह पूरी तरह से स्व–घोषणा और धारणा पर आधारित है।*** *किसी भी प्रतिक्रिया को सत्यापित नहीं किया गया है या साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इस प्रकार, सर्वेक्षण सुविख्यात पद्धति संबंधी चुनौतियों जैसे प्रेरक फ्रेमिंग, और आय की प्रणालीगत अंडर–रिपोर्टिंग के मुद्दे के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है। सबसे पहले, जिस तरह से प्रश्नावली को संरचित किया गया है, वह एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि समुदाय अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से टीएचडीसी पर निर्भर है। यह सवाल गलत है क्योंकि समुदाय ने ही टीएचडीसी में रोजगार की मांग की थी। हालांकि यह सच है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद कृषि भूमि की मात्रा कम हो गई थी, सर्वेक्षण इस तथ्य को स्पष्ट करने में विफल रहा कि अधिग्रहित अधिकांश भूमि कृषि योग्य नहीं थी, और इसलिए इसकी उत्पादकता कम थी। तथ्य यह है कि पुनर्वास कॉलोनियों में निर्मित घरों का औसत आकार मूल घरों के आकार के दोगुने से अधिक है, सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है, जो केवल निर्माण की उच्च लागत का हवाला देता है। अंत में, सर्वेक्षण लाभ साझाकरण, सामुदायिक विकास निधि और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना द्वारा प्रदान किए गए व्यापक समर्थन पर कब्जा नहीं करता है। प्रबंधन के विचार में, सर्वेक्षण को परियोजना द्वारा शुरू किए गए व्यापक अध्ययनों को विश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं माना जा सकता है, जो समुदाय में सकारात्मक सामाजिक–आर्थिक विकास का संकेत देते हैं।*

xiii. <u>जलापूर्ति</u> **: टीएचडीसी पुनर्वास स्थल की घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रहा है, जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से काफी अधिक है और समुदाय द्वारा पहले उपयोग की जाने वाली राशि से अधिक है। अनुरोध में उठाई गई कथित पानी की कमी पुनर्वास कॉलोनी के अंदर समुदाय के सदस्यों के बीच पानी के अनुचित व्यपवर्तन के कारण हुई है।** कई परिवारों ने अपने निजी छत के टैंकों को भरने के लिए समुदाय की सेवा वितरण लाइन में पंप स्थापित किए हैं। अन्य लोग भी वर्षा आधारित सिंचाई को बढ़ाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से घरों के पास सब्जी के भूखंडों को सींचने के लिए। यह कुछ घरों के लिए समान जल उपलब्धता को प्रभावित करता है। जबकि यह परियोजना के नीति के अनुपालन का मामला नहीं है- टीएचडीसी. जिसने समुदाय की शिकायतों के जवाब में हाल ही में आपूर्ति में वृद्धि की है. इस आंतरिक वितरण चुनौती को दूर करने के लिए समुदाय का समर्थन करने के लिए तैयार है।

xiv. **प्रबंधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बैंक नीति आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखते हैं, परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्थाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है।** यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय समुदाय के साथ परियोजना का जुड़ाव 2006 से लगातार बना हुआ है और ऋण लेने वाला नियमित रूप से ग्रामीणों की चिंताओं को ध्यान में रखता है, जिसके कारण डिजाइन समायोजन होता है। परियोजना का जीआरएम बना हुआ है और सामुदायिक चिंताओं को दूर करना जारी रखता है।

xv. प्रबंधन को विश्वास नहीं है कि अनुरोध में उठाई गई चिंताएं बैंक की नीति का अनुपालन न करने का परिणाम हैं। हालांकि, प्रबंधन फिर भी टीएचडीसी के साथ नीचे दी गई कार्रवाइयों पर सहमत है, जो अनुरोधकर्ताओं की कुछ चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी :

- टीएचडीसी मंदिर के चारों ओर ढलानों पर वनस्पति लगाकर उन्हें और बढ़ाने की अपनी योजना

- को आगे बढ़ाएगा। काम पूरा होने के बाद टीएचडीसी ने सभी डंपिंग साइटों को पूरी तरह से कवर करने के लिए इस वृक्षारोपण का विस्तार करने पर पहले ही सहमति दे दी थी। इसके अलावा, वर्षा अपवाह के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, टीएचडीसी ने टीबीएम प्लेटफॉर्म तक पहुंच मार्ग के किनारे जल निकासी का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है।

- टीएचडीसी, समुदाय के परामर्श से, सभी परिवारों के लिए पानी की अधिक समान पहुंच स्थापित करने के लिए पुनर्वास क्षेत्रों में पानी के उपयोग की निगरानी/विनियमन के लिए एक उपयुक्त तंत्र (या तो ग्राम सभा या एक समर्पित नई समिति के माध्यम से) स्थापित करने में समुदाय का समर्थन करेगा।

I. परिचय

1ण 19 अगस्त, 2022 को, निरीक्षण पैनल ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ("आईबीआरडी," या "बैंक") द्वारा वित्तपोषित भारत: विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ("वीपीएचईपी," या "परियोजना") (पी096124) के संबंध में निरीक्षण के लिए एक अनुरोध, आईपीएन अनुरोध आरक्यू 22/04 (इसके बाद "अनुरोध" के रूप में संदर्भित) (निरीक्षण के लिए तीसरा अनुरोध) दर्ज किया।

2ण **पाठ की संरचना।** दस्तावेज़ में निम्नलिखित खंड शामिल हैंरू खंड प्प अनुरोध प्रस्तुत करता है; खंड प्प्प परियोजना पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है; खंड प्ट विशेष मुद्दों पर चर्चा करता है; और खंड ट में प्रबंधन की प्रतिक्रिया शामिल है। अनुबंध 1 अनुरोधकर्ताओं के दावों को प्रबंधन की विस्तृत प्रतिक्रियाओं के साथ तालिका प्रारूप में प्रस्तुत करता है। अनुलग्नक 2 और 3 प्रासंगिक भूनिर्माण योजनाओं और इंजीनियरिंग डिजाइनों के चित्र प्रदान करते हैं। परियोजना का नक्शा और प्रासंगिक तस्वीरें भी प्रदान की गई हैं।

II. अनुरोध

3ण निरीक्षण के लिए अनुरोध उत्तराखंड के चमोली जिले के हाट गांव के 83 समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था (इसके बाद ष्अनुरोधकर्ताष् के रूप में संदर्भित)। अनुरोधकर्ताओं ने गोपनीयता की मांग की है और तीन व्यक्तियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है।

4ण अनुरोध में कई अनुबंध शामिल थे, जिन्हें गोपनीयता बनाए रखने के लिए संपादन के साथ प्रबंधन को प्रदान किया गया था। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करने वाले ग्राम सभा हाट का संकल्प (हिन्दी में);
- लक्ष्मी नारायण मंदिर दिनांक 04-04-2022 पर भारतीय पुरातत्व सोसायटी (एएसआई) की रिपोर्ट;
- एनजीओ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (आईएनटीएसीएच) का दिनांक 21-12-2021 का पत्र टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी) और विश्व बैंक को हाट गांव और मंदिर के संबंध में कॉपी किया गया;
- 92 सर्वे शीट और सर्वे शीट का अंग्रेजी अनुवाद ग्रामीणों को परिचालित किया गया;
- हाट गांव के संबंध में एक कथित रूप से प्राचीन तांबे के शिलालेख का चित्र;
- हाट गांव द्वारा मंदिर को विरासत स्थल घोषित करने का संकल्प दिनांक 28-03-2022 पारित;
- डॉ. जुयाल और प्रो. सुंदरियाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में वैकल्पिक मलबा डंप साइट का सुझाव दिया गया है; और
- उत्तराखंड में जलविद्युत के संबंध में दिनांक 25-02-2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक का कार्यवृत्त।

III. परियोजना पृष्ठभूमि

5ण **परियोजना।** वीपीएचईपी को 30 जून, 2011 को 922 मिलियन डॉलर की कुल परियोजना लागत के लिए अनुमोदित किया गया था। बैंक ने उधारकर्ता, टीएचडीसी, जो कार्यान्वयन एजेंसी भी है और शेष 274 मिलियन डॉलर प्रदान कर रहा है, को 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। 100 मिलियन डॉलर प्रत्येक के दो निरस्तीकरणों के बाद, वर्तमान बैंक वित्तपोषण राशि 448 मिलियन डॉलर है। परियोजना की वर्तमान समापन तिथि 30 जून, 2023 है। यह एक श्रेणी ए परियोजना है, और निम्नलिखित सुरक्षा नीतियों को ट्रिगर किया गया है : पर्यावरण मूल्यांकन (ओपी/बीपी 4-01), प्राकृतिक आवास (ओपी/बीपी 4-04), भौतिक सांस्कृतिक संसाधन (ओपी/बीपी 4-11), अनैच्छिक पुनर्वास (ओपी/बीपी 4-12), वन (ओपी/बीपी 4-36), बांधों की सुरक्षा (ओपी/बीपी 4-37), और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर परियोजनाएं (ओपी/बीपी 7-50)।

6ण **परियोजना के उद्देश्यों।** परियोजना के विकास के उद्देश्य हैं "(ए) नवीकरणीय, निम्न–कार्बन ऊर्जा के अतिरिक्त के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि; और (बी) आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से स्थायी जलविद्युत परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में ऋण लेने वाले की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना। वीपीएचईपी को भारत के उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की रन–ऑफ–रिवर जलविद्युत उत्पादन परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। यह 90 प्रतिशत निर्भर वर्ष में 1636 गीगावाठ घंठा उत्पन्न करेगा, और यह भारत के उत्तरी ग्रिड में थर्मल उत्पादन के विस्तार की आवश्यकता को कम करने में मदद करेगा।

7ण **परियोजना घटक।** परियोजना के दो घटक हैं : (प) चमोली जिला, उत्तराखंड, भारत में 444–मेगावाट जलविद्युत परियोजना का निर्माण; और (पप) टीएचडीसी में क्षमता निर्माण और संस्थागत मजबूती का समर्थन करना। अनुरोध में उठाए गए मुद्दे पहले घटक से संबंधित हैं।

8ण **निरीक्षण के लिए पिछले अनुरोध.** निरीक्षण पैनल ("पैनल") ने पहले परियोजना पर निरीक्षण के लिए दो अनुरोधों की समीक्षा की। पहला 23 जुलाई, 2012 को प्राप्त हुआ, जिसके बाद पैनल ने जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट[1] 1 जुलाई 2014 को कार्यकारी निदेशक मंडल ("बोर्ड") को प्रस्तुत की ("2014 जांच" या "जांच")। 30 सितंबर 2014 को, बोर्ड ने पैनल की जांच रिपोर्ट के जवाब में प्रस्तुत प्रबंधन रिपोर्ट और सिफारिश में शामिल कार्य योजना को मंजूरी दे दी[2]; कार्य योजना अभी भी कार्यान्वयन के अधीन है और प्रबंधन बोर्ड को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान कर रहा है। निरीक्षण के लिए दूसरा अनुरोध 1 मार्च, 2022 को प्राप्त हुआ था। पैनल ने इस अनुरोध को पंजीकृत नहीं किया क्योंकि यह निर्धारित किया गया था कि उसमें उठाई गई चिंताएं 2014 में पहले से ही जांचे गए मुद्दों से संबंधित थीं और पैनल संकल्प के तहत आवश्यक नए सबूत पेश नहीं किए। इसलिए पैनल ने 20 अप्रैल, 2022 को दूसरे अनुरोध के संबंध में गैर–पंजीकरण का नोटिस जारी किया।[3]

---

[1] https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/ip/PanelCases/81%20-%20Investigation%20Report%20%28English%29.pdf

[2] https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/ip/PanelCases/81%20-%20Management%20Report%20and%20Recommendation%20%28English%29.pdf

[3] https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/cases/documents/156-India-VPHEP%202-Notice%20of%20Non-Registration-20%20April%202022.pdf

9ण **12 जुलाई, 2022 को निरीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।**12 जुलाई, 2022 को पैनल द्वारा प्राप्त उनके अनुरोध में, अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि वीपीएचईपी ने उन्हें पहले ही नुकसान पहुंचाया है, और परियोजना से संबंधित मलवा डंपिंग से भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। उनका कहना है कि परियोजना ने वैकल्पिक डंपिंग स्थलों का पता लगाने की उपेक्षा की है। अनुरोधकर्ता हाट गांव के परिवारों के अनैच्छिक पुनर्वास और आजीविका के नुकसान के बारे में भी चिंता जताते हैं; उन्हें पुनर्वास क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली जलापूर्ति सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में भी शिकायतें हैं। उनका दावा है कि प्रभावित समुदाय के सदस्यों की शिकायतों को नहीं सुना जाता है। इसके अलावा, वे एक बार बन चुके बांध की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं।

IV. पात्रता विचार

10ए **प्रबंधन का निवेदन है कि पैनल की स्थापना के संकल्प के अनुसार अनुरोध अपात्र है।** जिन अनुरोधों को जांच के लिए अपात्र माना जाता है, उनमें किसी विशेष मामले या ऐसे मामलों से संबंधित अनुरोध शामिल हैं, जिन पर पैनल ने पूर्व अनुरोध प्राप्त होने पर अपनी सिफारिश पहले ही कर दी है, जब तक कि नए साक्ष्य या पूर्व अनुरोध के समय अज्ञात परिस्थितियों से उचित न हो।

11ए **प्रबंधन के विचार में, यह तीसरा अनुरोध केवल या तो उन मुद्दों को कवर करता है जिनकी 2014 में पहले ही जांच की जा चुकी थी, या वे मुद्दे जो दूसरे अनुरोध में उठाए गए थे और जिन्हें पैनल नए साक्ष्य या परिस्थितियों के रूप में योग्य नहीं मानता था।** विशेष रूप से, पैनल ने अपने पंजीकरण के नोटिस में नोट किया है कि यह तीसरा अनुरोध नए साक्ष्य प्रस्तुत करता है या नई परिस्थितियों का वर्णन करता है : (i) भौतिक सांस्कृतिक संसाधन और यह आरोप कि मलवा डंपिंग से लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थिरता और अस्तित्व को खतरा है, (ii) समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का आरोप, और (iii) समुदाय के सदस्यों द्वारा पानी की आपूर्ति तक सीमित पहुंच का आरोप। हालाँकि, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, इन तीन मुद्दों में से कोई भी ऐसी नई परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं करता है जो पहले के अनुरोधों में नहीं उठाई गई थीं, और न ही आरोप नए साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं। पहले या दूसरे अनुरोध के तहत पैनल द्वारा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों और पानी की आपूर्ति तक पहुंच सहित पुनर्वास और पुनर्वास पैकेजों की या तो समीक्षा की गई या मूल्यांकन किया गया। वास्तव में, पैनल ने 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण की अपनी सूचना में निष्कर्ष निकाला कि ष्इस अनुरोध में उठाई गई चिंताओं – जिसमें पुनर्वास, पुनर्वास और भौतिक सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा शामिल है – से संबंधित है परियोजना के पहलू जिन्हें 2014 की जांच में संबोधित किया गया था। पैनल प्रबंधन के इस कथन को भी नोट करता है कि गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य छोटे सामुदायिक मंदिरों की रक्षा की जाएगी। ख्.., पैनल आगे नोट करता है कि सुरक्षात्मक उपाय वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

12ए ***जबकि तीसरा अनुरोध नए दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है, ये न तो मामले के लिए मूल हैं, न ही वे नए साक्ष्य या परिस्थितियाँ प्रस्तुत करते हैं जैसा कि पैनल संकल्प द्वारा आवश्यक है :***

- *लक्ष्मी मंदिर पर एएसआई की रिपोर्ट (दिनांक 04-04-2022)* **:**यह रिपोर्ट मंदिर के पुरातात्विक मूल्य के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) में निष्कर्षों की पुष्टि करती है और एएसआई की पिछली रिपोर्टों के अनुरूप भी है। यह रिपोर्ट नए साक्ष्य या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं करती है।

- *हाट गांव व मंदिर के संबंध में इन्टैक का पत्र दिनांक 21-12-2021* / इस पत्र में कोई नई जानकारी या सबूत नहीं है। इन्टैक एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी कोई आधिकारिक क्षमता नहीं है, और इस तरह इस मामले पर एक तीसरे पक्ष के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। एएसआई भारत में पुरातात्विक ऐतिहासिकता के मुद्दों पर राय देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है, और इसलिए इस पत्र का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है या कोई नई जानकारी नहीं है।

- *ग्रामीणों को बांटे गए 92 सर्वे शीट* **:**जैसा कि नीचे और अधिक विस्तार से बताया गया है, सर्वेक्षण में बुनियादी पद्धतिगत आवश्यकताओं का अभाव है। सर्वेक्षण पूरी तरह से स्व–घोषणा पर आधारित है, और सर्वेक्षण में कोई भी प्रतिक्रिया साक्ष्य द्वारा समर्थितया सत्यापित नहीं की गई है

इसके अलावा, कई प्रतिक्रियाएँ समुदाय के पुनर्वास के बाद की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने वाले अन्य अध्ययनों के निष्कर्षों से असंगत हैं। इसलिए, सर्वेक्षण को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, और इसलिए इसमें कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।

- *हाट गांव के संबंध में एक कथित प्राचीन तांबे के शिलालेख का चित्र :* प्रबंधन को तांबे के शिलालेख के उद्गम, इसके मूल स्थान, या इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के बारे में पता नहीं है, और इसलिए इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। प्रबंधन आगे नोट करता है कि एएसआई की तीन रिपोर्ट में से कोई भी तांबे के शिलालेख का कोई संदर्भ नहीं देता है, और इसलिए वर्तमान मामले में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट नहीं है।

- *ग्राम सभा हाट के प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करने का संकल्प (हिंदी में) तथा हाट गांव द्वारा मंदिर को विरासत स्थल घोषित करने का संकल्प दिनांक 28-03-2022 पारित :* प्रबंधन हाट ग्राम सभा के संकल्प को स्वीकार करता है जिसमें लक्ष्मी नारायण और अन्य मंदिरों को ग्राम सभा द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का सांस्कृतिक महत्व पहले से ही ईआईए में पहचाना गया था और ईएमपी में परिलक्षित हुआ था, और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, टीएचडीसी इस मंदिर के लिए ओपी 4-11 के अनुरूप तरीके से शमन उपाय करना जारी रखता है। प्रबंधन यह भी नोट करता है कि ग्राम सभा के पास इमारतों के ऐतिहासिक चरित्र और पुरातात्विक संरक्षण के लिए उनकी पात्रता घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए इस प्रस्ताव का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है या कोई नई जानकारी नहीं है।

- *डॉ. जुयाल और प्रो. सुंद्रियाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट* में वैकल्पिक मलबा डंप साइट का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर मलबा डाला जा रहा है, जो कि गलत है। रिपोर्ट के विचार और निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि वे गलत धारणाओं पर आधारित हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता या प्रमाणिक मूल्य नहीं है।

- *उत्तराखंड में जलविद्युत के संबंध में 25-02-2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक का कार्यवृत्त :* ये कार्यवृत्त सरकार के उस निर्णय को दर्शाते हैं कि भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के बाद वीपीएचईपी के निर्माण को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। प्रबंधन इस अनुरोध के लिए इस दस्तावेज़ की प्रासंगिकता को समझने में विफल रहा है।

13ए **प्रबंधन के विचार में, नए साक्ष्य या परिस्थितियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता एक ऐसे अनुरोध को प्रस्तुत करके पूरी नहीं की जा सकती है जो उन्हीं मामलों से संबंधित है जिन पर पैनल पहले ही दो बार अपनी सिफारिश कर चुका है, दस्तावेजों के साथ जिनका या तो कोई साक्ष्य मूल्य या सार नहीं है या बैंक नीतियों के साथ गंभीर गैर–अनुपालन के कारण कथित रूप से होने वाले भौतिक नुकसान के मुद्दे से संबंधित नहीं है।**

14ए **पैनल प्रक्रिया अनुरोधकर्ताओं द्वारा पैनल के निर्णयों और निष्कर्षों के लिए चुनौतियों का प्रावधान नहीं करती है।** इसलिए, यदि अनुरोधकर्ता पैनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो यह अनुरोधों को बार–बार फाइल करने का प्रावधान नहीं करता है। पैनल संकल्प के पैराग्राफ 15(डी) और 29(एफ) बार–बार अपील होने से रोकने के लिए स्पष्ट आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं। प्रबंधन के विचार में, हालांकि, यह तीसरे अनुरोध का मामला है, जहां इन स्पष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

15ण **जैसा कि नीचे और 4 फरवरी 2022 को प्रस्तुत इसके 7वें एमएपी प्रगति रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, यह प्रबंधन का विचार है कि तीसरे अनुरोध में उठाए गए नुकसान या संभावित नुकसान के सभी परियोजना–विशिष्ट दावों को या तो पहले ही संबोधित कर दिया गया है या वर्तमान में शमन और प्रबंधन उपायों के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है।** बैंक और टीएचडीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के साथ संचार के खुले चौनल बनाए हैं कि उनकी चिंताओं को सुना और संबोधित किया जाता है, और टीएचडीसी किसी भी शेष चिंताओं को हल करने के लिए समुदाय और जिला प्रशासन के साथ जुड़ना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, प्रबंधन का मानना है कि यह तीसरा अनुरोध जांच के योग्य नहीं है।

[4] निरीक्षण पैनल जांच रिपोर्ट फरवरी 17, 2022 के जवाब में प्रबंधन की कार्य योजना के कार्यान्वयन पर भारत – विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सातवीं प्रगति रिपोर्ट।

V. प्रबंधन की प्रतिक्रिया

16ए प्रबंधन के विस्तृत जवाबों के साथ अनुरोधकर्ताओं के दावे अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

17ए **जैसा कि ऊपर अनुभाग IV में अधिक विस्तार से बताया गया है, यह अनुरोध, प्रबंधन की दृष्टि में, निरीक्षण पैनल स्थापित करने वाले बोर्ड के संकल्प के अनुसार अपात्र है।** परियोजना की जांच के लिए यह तीसरा अनुरोध उन मुद्दों को शामिल करता है जिनकी या तो 2014 में पहले ही जांच की जा चुकी थी, या वे मुद्दे जो मार्च 2022 में दूसरे अनुरोध में उठाए गए थे, और जिन्हें पैनल ने नए साक्ष्य या परिस्थितियों के रूप में योग्य नहीं माना। जबकि इस तीसरे अनुरोध में नए दस्तावेज़ संलग्न हैं, ये न तो मामले के लिए प्रासंगिक हैं, और न ही इनमें कोई नया साक्ष्य या प्रासंगिक जानकारी शामिल है जो "नए साक्ष्य या परिस्थितियों को पूर्व अनुरोध [एस] के समय ज्ञात नहीं" के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा। संकल्प द्वारा आवश्यक।

18ए **प्रबंधन नोट करता है कि पंजीकरण के पैनल के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यह तीसरा अनुरोध नए साक्ष्य या परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित हैं:** "(i) भौतिक सांस्कृतिक संसाधन और यह आरोप कि मलबा डंपिंग से लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थिरता और अस्तित्व को खतरा है; (ii) समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का आरोप; और (iii) समुदाय के सदस्यों द्वारा जल स्रोतों तक सीमित पहुंच का आरोप।"

19ए **प्रबंधन द्वारा मामले की समीक्षा दर्शाती है कि अनुरोध में लगाए गए आरोप या तो नए नहीं हैं और पहले से ही प्रबंधित किए जा रहे हैं, या असमर्थित हैं, और यह कि उद्धृत प्रतिकूल प्रभाव प्रमाणित नहीं हैं।** प्रबंधन ने अनुरोध में उठाए गए मुद्दों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और नीचे दिए गए प्रत्येक मुद्दे पर अधिक विस्तार से प्रतिक्रिया दी है।

20ए **लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थल पर हुए कार्यों से न तो प्रभावित हुआ है और न ही भविष्य के कार्यों से प्रभावित होने का खतरा है।** इसके अलावा, परियोजना ने मंदिर परिसर के संरक्षण और उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएँ विकसित की हैं। मंदिर से काफी दूर होने वाले कूड़ा निस्तारण से मंदिर को कोई खतरा नहीं है। मंदिर के पीछे या उसके आस–पास कोई मलबा न तो डाला जा रहा है और न ही डाला जाएगा। प्रबंधन ने अतिरिक्त हवाई तस्वीरें भी शामिल की हैं जो दर्शाती हैं कि मंदिर के पीछे कोई मलबा नहीं डाला गया है। मंदिर के पीछे गेबियन दीवार गंदगी के लिए एक बनाए रखने वाली दीवार नहीं है और उचित जल निकासी सहित अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। वर्षा का अपवाह पहुंच मार्ग के साथ पास के प्राकृतिक नाले में प्रवाहित होता है, ताकि ढलान पर फिसलन को रोका जा सके। इसके अलावा, टीएचडीसी ने पहुंच सड़कों के किनारे जल निकासी का निर्माण करने और खंड को फिर से लगाने की योजना बनाई है।

21ए **परियोजना द्वारा किए गए और बैंक द्वारा समीक्षा किए गए व्यापक अध्ययन कथित "समुदाय के सदस्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति" का समर्थन नहीं करते हैं।** परियोजना ने लक्षित और अनुकूलित शमन उपायों को प्रायोजित किया है, जो स्थानीय समुदायों पर परियोजना के पूर्व संभावित सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन करने वाले कई अध्ययनों पर आधारित थे। टर्म–टर्म आरएपी मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी प्रमुख व्यवसायों में हाट गांव से विस्थापित परिवारों के लिए बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का पता चलता है, जो परियोजना के बाद के परिदृश्य में नहीं बदले हैं।

22ए प्रबंधन नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक और पद्धतिगत कठोरता का अभाव है क्योंकि यह पूरी तरह से स्व–घोषणा पर आधारित है। कोई भी

प्रतिक्रिया सत्यापित या साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इस प्रकार, सर्वेक्षण सुविख्यात पद्धति संबंधी चुनौतियों जैसे प्रेरक फ़्रेमिंग और आय की प्रणालीगत कम रिपोर्टिंग के मुद्दे के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है। इसके अलावा, सर्वेक्षण लाभ साझा करने, सामुदायिक विकास निधियों और लक्षित आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना द्वारा प्रदान किए गए व्यापक समर्थन का संज्ञान नहीं लेता है। प्रबंधन के विचार में, सर्वेक्षण को विश्वसनीय रूप से उन व्यापक अध्ययनों को चुनौती देने वाला नहीं माना जा सकता है जिन्हें परियोजना ने कमीशन किया है, जो पेशेवर कर्मचारियों द्वारा किए गए थे, जो समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने में योग्य थे।अंतिम अवधि के मूल्यांकन सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से सामने आया कि समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से कृषि और व्यवसाय से आय के स्तर में कई गुना वृद्धि हुई है और पुनर्वास कालोनियों में बनाए गए नए घर औसतन उनके पिछले घरों के आकार के दोगुने से अधिक हैं। यहाँ तक कि व्यावसायिक प्रतिमान भी लगभग एक जैसा ही रहा है। इसके अलावा, सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं में परियोजना द्वारा प्रदान किए गए अनुदान और समर्थन शामिल नहीं हैं।

23ए **टीएचडीसी पुनर्वास स्थल की घरेलू जरूरतों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि से काफी अधिक पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रहा है[5] और उससे अधिक जो पहले समुदाय द्वारा एक्सेस किया गया था। अनुरोध में उठाई गई कथित पानी की कमी सबसे अधिक संभावना पुनर्वास कॉलोनी के अंदर समुदाय के सदस्यों के बीच पानी के अनुचित मोड़ के कारण हुई है।** कई परिवारों ने अपने निजी छत के टैंकों को भरने के लिए समुदाय की सेवा वितरण लाइन में पंप स्थापित किए हैं। अन्य लोग भी वर्षा आधारित सिंचाई को बढ़ाने के लिए घरेलू जल का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से अपने घरों के पास सब्जी के भूखंडों को सींचने के लिए। आपूर्ति योजना दोनों के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है और इसलिए, यह घरों के लिए एक समान जल आपूर्ति को प्रभावित करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लाइन के अंत में हैं। जबकि यह मुख्य रूप से बैंक नीति के साथ परियोजना के अनुपालन का मामला नहीं है, टीएचडीसी, जिसने समुदाय की शिकायतों के जवाब में हाल ही में आपूर्ति में वृद्धि की है, इस आंतरिक वितरण चुनौती को दूर करने के लिए भी समुदाय का समर्थन करने को तैयार है।

24ए **प्रबंधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बैंक नीति आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखते हैं, परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्थाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है।** यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय समुदाय के साथ परियोजना का जुड़ाव 2006 से लगातार बना हुआ है और ऋण लेने वाला नियमित रूप से ग्रामीणों की चिंताओं को ध्यान में रखता है, जिसके कारण डिजाइन समायोजन होता है।

25ए नीचे, प्रबंधन ने तीन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया का विस्तार किया : (i) लक्ष्मी नारायण मंदिर को खतरा; (ii) बदतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति; और (iii) जल आपूर्ति।

लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थिरता और अस्तित्व के लिए कथित खतरा

26ए ***पृष्ठभूमि। हाट गांव को 2011 में ओपी*** 4.12 ***लागू कर प्रतिष्ठित डोमेन के तहत अधिग्रहित किया गया था***। जबकि परियोजना के लिए मूल रूप से पूरे गांव का अधिग्रहण आवश्यक नहीं था, इसे समुदाय के अनुरोध पर अधिग्रहित किया गया था, जो उस भूमि पर स्थानांतरित करना चाहते थे जो नदी के उस पार पहले से ही उनके स्वामित्व में थी। स्थानांतरण हुआ, और आज तक, गांव में सभी आवासीय आवासों को नष्ट कर दिया गया है क्योंकि यह क्षेत्र अब परियोजना कार्य की खुदाई के लिए चार स्वीकृत मलवा निपटान स्थलों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। परियोजना की शुरुआत से टीएचडीसी, गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर को

[5] राज्य के नियमों के अनुसार ग्रामीण परिवारों के लिए न्यूनतम जल आपूर्ति 55 लीटर/प्रति व्यक्ति/दिन निर्धारित की गई है। टीएचडीसी पुनर्वास कालोनियों में 810 लीटर/दिन/घर उपलब्ध करा रहा है।

संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि परियोजना के ईआईए और ईएमपी में प्रमाणित है और समुदाय को बार–बार आश्वासन देता है।

27ए मंदिर को संरक्षित करने के अलावा, टीएचडीसी ने एक बार सिविल कार्य पूरा हो जाने के बाद मंदिर क्षेत्र के लिए पहुंच और सौंदर्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भूमि बहाली और भूनिर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, और परियोजना सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है और हटा दिया गया है। टीएचडीसी द्वारा मंदिर और उसके आसपास के निर्माण के बाद की लैंडस्केपिंग योजना तैयार की गई है और बैंक द्वारा इसकी समीक्षा की गई है (अनुबंध 2 देखें)।

28ए **ईएमपी के अनुसार हाट गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर संरक्षण प्रयासों के अलावा भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण के अन्य प्रयास किए गए हैं।** इसमें शामिल हैं: (i) ग्राम प्रधान और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के परामर्श से बिल्व के पेड़ लगाना; (ii) गाँव में अन्य छोटे सामुदायिक मंदिरों की रक्षा करना; और (iii) अपने निवासियों के साथ निजी घरों में छोटे मंदिरों और मंदिरों को स्थानांतरित करना।

29ए परियोजना की तैयारी के भाग के रूप में, लक्ष्मी–नारायण मंदिर सहित भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का मूल्यांकन ओपी 4-11 के अनुरूप किया गया था। परियोजना ईआईए ने मंदिर को संरक्षित करने की आवश्यकता को पहचाना और परियोजना ने मंदिर परिसर के संरक्षण और उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएँ विकसित कीं। टीएचडीसी ने 2013 में लक्ष्मी नारायण मंदिर का और आकलन करने के लिए पुरातत्व अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण/संरक्षण के लिए देश की सक्षम संस्था एएसआई को नियुक्त किया और 2017 में इस अध्ययन पर फिर से विचार किया गया। सरकार के अनुरोध पर, एएसआई ने 2022 में मंदिर का एक और सर्वेक्षण किया।

30ए मंदिर को संरक्षित करने के लिए परियोजना की प्रतिबद्धता के बावजूद, प्रबंधन ने नोट किया कि अनुरोध सही ढंग से मंदिर के एएसआई के आकलन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसे एएसआई ने "कई बदलावों के माध्यम से जाना" और यह कि "गर्भगृह को छोड़कर, शेष घटक पुराने नहीं हैं और बाद में जोड़ा गया। अनुरोध के इस दावे के विपरीत कि हाट को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए, एएसआई ने निष्कर्ष निकाला कि हाट में आवासीय संरचनाएं "सामान्य घर या उनके अवशेष पाए गए हैं जो किसी भी पुरातात्विक या कलात्मक विशेषता से रहित हैं।" इसके अलावा, मंदिर की उम्र के बारे में एएसआई का आकलन आदि शंकराचार्य से मंदिर के जुड़ाव के अनुरोधकर्ताओं के दावे का खंडन करता है।[6]

31ए **प्रबंधन आगे नोट करता है कि आई एन टी ए सी एच द्वारा जारी पत्र, जिसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, में कोई नई जानकारी नहीं है।** इसके अलावा, इन्टैक एक गैर सरकारी है। संगठन की कोई आधिकारिक क्षमता नहीं है, और इस तरह इस मामले पर तीसरे पक्ष के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। एएसआई भारत में पुरातात्विक ऐतिहासिकता के मुद्दों पर राय देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकरण बना हुआ है।

मंदिर की सुरक्षा

32ए **लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थल पर हुए कार्यों से न तो प्रभावित हुआ है और न ही भविष्य के कार्यों से प्रभावित होने का खतरा है।** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंदिर के पीछे या उसके आस–पास कोई मलबा नहीं डाला जा रहा है और न ही डाला जाएगा। मंदिर से काफी दूर होने वाले कूड़ा निस्तारण से मंदिर को कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत, परियोजना ने मंदिर परिसर के संरक्षण और उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएँ विकसित की हैं। एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बादए भूमि उपचार और भूनिर्माण से मंदिर के आसपास के क्षेत्र की पहुंच और उपस्थिति में और सुधार होगा।

[6] 8वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय वैदिक विद्वान। एएसआई का कहना है कि मंदिर 11वीं–12वीं शताब्दी ईस्वी का हो सकता है।

33ए **अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर को मलबा डंपिंग से खतरा है, जो मंदिर के आसपास होने वाली परियोजना गतिविधियों की गलतफहमी से उपजा है।** मंदिर के पीछे या उसके आस–पास मलबा नहीं डाला जा रहा है। अनुरोधकर्ता गलती से मंदिर के पीछे ष्कूड़ा डंपिंगष् के रूप में पहचान करते हैं, वास्तव में बजरी का उपयोग मंदिर के पीछे ढलान को भरने और मजबूत करने के लिए किया जाता है, जो एक पहुंच मार्ग का समर्थन करता है। इस ढलान की किसी भी फिसलन से मंदिर की रक्षा के लिए गेबियन दीवार का निर्माण किया गया है। जैसा कि नीचे फोटो 1 में देखा गया है, वनस्पति पहले से ही बढ़ने लगी है और क्षेत्र को कवर कर रही है, जिससे वहां होने वाले मलवा डंपिंग के दावे का खंडन होता है। दोनों पहुंच मार्ग उपयोग में हैं, जो संभव नहीं होगा यदि मलबा डाला जा रहा हो, विशेष रूप से निचली सड़क के पास के क्षेत्र में। जैसा कि नीचे अधिक विस्तार से बताया गया है, मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा और ढलानों की स्थिरता की विधिवत निगरानी की जा रही है।

फोटो 1: मंदिर परिसर और आसपास के परियोजना कार्यों की हवाई तस्वीर (26 अगस्त, 2022)। मंदिर परिसर के उत्तर में दीवार के पीछे (यानी गेबियन दीवार के पीछे) कोई मलबा नहीं डाला जा रहा है।

34ण **मंदिर से काफी दूर पूर्व गांव के अन्य हिस्सों में मलबा डंप किया जाता है।** प्रबंधन नोट करता है कि टीएचडीसी द्वारा अधिग्रहीत गांव का मलबा डंपिंग के लिए उपयोग पूरी तरह से राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है, और आवश्यक पर्यावरण परमिट प्राप्त किए गए हैं।[7] चूंकि मंदिर को संरक्षित किया जाएगा और पहुंच प्रदान की जाएगी, पूर्व गांव में मलवा डंप करने से कोई नुकसान नहीं होगा।

35ण **मंदिर के दाहिनी ओर दिखाई देने वाले बजरी मंच पर भी यही बात लागू होती है (फोटो 2 देखें)।** इस बजरी को वहां केवल एक बार जमा किया गया है, कंक्रीट संयंत्र के लिए एक मंच बनाने के लिए जो हेडरेस सुरंग के लिए खंडों की ढलाई कर रहा है। पूर्ण किए गए खंडों को निर्माण में उपयोग किए जाने तक संयंत्र के चारों ओर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा रहा है। क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाएगा और मंदिर परिसर को प्रभावित नहीं करेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र के उपयोग का अर्थ यह भी है कि मंदिर के चारों ओर मलबा डंप करना किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा, क्योंकि यह सुरंग खंडों के उत्पादन और भंडारण में बाधा उत्पन्न करेगा। एक बार सिविल कार्य पूरा हो जाने के बाद प्लेटफॉर्म की ढलानों को भी वनस्पति के साथ बहाल किया जाएगा, और परियोजना सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है और हटा दिया गया है।

फोटो 2- कंक्रीट कास्टिंग प्लांट को समायोजित करने के लिए प्लेटफार्म

36ण **मंदिर के पीछे गेबियन दीवार ढलान और मंदिर के पीछे पहुंच मार्ग का समर्थन करती है (फोटो 3 देखें)।** यह दीवार गंदगी के खिलाफ एक बनाए रखने वाली दीवार के रूप में काम नहीं करती है, न ही यह कभी इरादा था। गेबियन दीवार लगभग 100 मीटर लंबी और आधार पर 9 मीटर तक मोटी होती है। इस गेबियन दीवार को कुल 100 मिमी की परत के साथ और मजबूत किया गया था। एक स्कैन

[7] मलवा निपटान स्थलों को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है और 2021 की उनकी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) में इसका उल्लेख किया गया है। पर्यावरणीय पहलुओं पर भारत की सर्वोच्च अदालत, नेशनल ग्रीन द्वारा ईसी को बरकरार रखा गया है। ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 16 अगस्त, 2022 के अपने आदेश में।

फोटो [4] में देखा जा सकता है कि इस दीवार में किसी तरह का कोई मलवा, या कोई अन्य मलबा नहीं रखा जा रहा है, या इसके खिलाफ ढेर नहीं लगाया जा रहा है। वास्तव में, बजरी भराव किसी भी संभावित फिसलन के खिलाफ टीबीएम प्लेटफॉर्म के पैर में ढलान को मजबूत कर रहा है। दीवार को विभिन्न इंजीनियरिंग पहलुओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बारिश से उत्पन्न कोई भी अपवाह, ढलान की फिसलन से रक्षा करते हुए, पास के प्राकृतिक जल निकासी के लिए पहुंच मार्ग के साथ बहता है। इसके अलावा, बारिश के पानी के रिसने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित हाइड्रोस्टेटिक दबाव को कम करने के लिए गेबियन दीवार को कई नालियों के साथ प्रदान किया गया है। टीएचडीसी अपवाह को प्राकृतिक जल निकासी की ओर निर्देशित करने के लिए पहुंच सड़कों के साथ–साथ अतिरिक्त नालियों का निर्माण करने की भी योजना बना रहा है। इसलिए, यह चिंता कि यह दीवार इतनी मजबूत नहीं होगी कि डंप किए गए मलवे को रोक सके, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, न ही भविष्य में इसकी योजना है। यह गलतफहमी एएसआई के 2022 के नोट में भी दिखाई देती है,[8] साथ ही अनुरोध से जुड़े तकनीकी पेपर ("हाट गांव में एडिट टनल से मलबा डंप करने के लिए वैकल्पिक स्थान के लिए सुझाव") में।

37ण ***प्रबंधन ने अनुरोध से जुड़े तकनीकी पेपर :हाट गांव में एडिट टनल से मलबा डंपिंग के लिए वैकल्पिक स्थान के लिए सुझाव की समीक्षा की है।*** एक सामान्य टिप्पणी के रूप में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेपर इस गलत धारणा से शुरू होता है कि मलवा डाला जाता है और, मंदिर के ऊपर जमा किया जाता है। चूंकि यह मामला नहीं है- पेपर का तर्क और निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं है।

38ण **इसके अलावा, पेपर उनके तकनीकी, पर्यावरण, सामाजिक, सुरक्षा और वित्तीय व्यवहार्यता मानदंड के संबंध में मलवा डंपिंग विकल्पों का व्यापक विश्लेषण प्रदान नहीं करता है।** पेपर द्वारा सुझाया गया कचरा डंपिंग समाधान, प्रबंधन के विचार में, बहुत अधिक पर्यावरणीय जोखिम पेश करेगा। पेपर की अधिक विस्तृत समीक्षा अनुबंध 1 के आइटम 6 में पाई जा सकती है।

फोटो 3- दाहिनी ओर पहुंच मार्ग और बाईं ओर मंदिर परिसर (दृश्यमान नहीं) के साथ गेबियन दीवार का क्रॉस–सेक्शन दृश्य। यदि गेबियन दीवार का उपयोग संग्रहित मलबे से बचाने के लिए किया जाता है, तो यह पहुंच मार्ग वाहनों द्वारा उपयोग करने योग्य नहीं होगा।

[8] हाटगाँव (ग्राम हाट) पीपल कोटी, जिला चमोली में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निरीक्षण नोट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) 04 अप्रैल, 2022 (अनुरोध के लिए दूसरा संलग्नक)।

फोटो 4- गेबियन दीवार के पीछे का दृश्य (मंदिर परिसर की लाल छत दिखाई दे रही है) यह दर्शाता है कि इसके पीछे कोई मलबा नहीं डाला जा रहा है

समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया

39ण **प्रबंधन नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में पद्धतिगत कठोरता का अभाव है क्योंकि यह पूरी तरह से स्व–घोषणा पर आधारित है।** किसी भी प्रतिक्रिया को सत्यापित नहीं किया गया है या साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इस प्रकार, सर्वेक्षण सुविख्यात पद्धति संबंधी चुनौतियों जैसे प्रेरक फ्रेमिंग, और आय की प्रणालीगत अंडर–रिपोर्टिंग के मुद्दे के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है। सर्वेक्षण में भूस्वामियों की पुनर्वास के लिए सहमति भी शामिल नहीं है, जो लगभग सभी ने टीएचडीसी के साथ हस्ताक्षरित व्यक्तिगत समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में प्रदान की है।

40ण **इसके अलावा, सर्वेक्षण लाभ साझाकरण, सामुदायिक विकास निधि और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना द्वारा प्रदान किए गए व्यापक समर्थन पर कब्जा नहीं करता है।** प्रबंधन के विचार में, सर्वेक्षण को विश्वसनीय रूप से व्यापक अध्ययन के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे परियोजना ने कमीशन किया है, और जो पेशेवर कर्मचारियों द्वारा किए गए थे, जो समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने में योग्य थे। खोई हुई संपत्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत मुआवजे के अलावा, परियोजना ने हाट के विस्थापित परिवारों को 1 मिलियन (लगभग 12520 डालर) के विशेष अनुदान का भुगतान किया है। टीएचडीसी ने संबंधित सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और निजी फर्मों के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, परिधीय विकास आदि जैसे क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ कई सामुदायिक विकास गतिविधियां शुरू की हैं। लक्ष्य समुदायों के सतत आजीविका, समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। लाभ व्यक्तियों की क्षमता निर्माण से लेकर समुदाय को सहायता प्रदान करने तक होते हैं। परियोजना ने आसपास के समुदाय के सामाजिक–आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां भी शुरू की हैं। इसमें छात्रवृत्ति प्रदान करना, लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण खेल, ग्रामीण चिकित्सा शिविर, परियोजना औषधालय तक पहुंच

आदि शामिल हैं। परियोजना ईंधन और चारे के नुकसान को दूर करने के लिए परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर का भुगतान भी कर रही है। इसका भुगतान निर्माण अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। एक बार चालू हो जाने के बाद परियोजना शुरू होने की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए प्रति माह प्रत्येक प्रभावित परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।

41ए **प्रबंधन नोट करता है कि समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था जब पुनर्वास प्रक्रिया शुरू होने के पांच साल बाद इसका मूल्यांकन किया गया था।**[9] बैंक नीति की आवश्यकता है कि षविस्थापित व्यक्तियों को उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार या कम से कम उन्हें बहाल करने के प्रयासों में सहायता की जानी चाहिए,ष और इन प्रयासों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई और पर्याप्त बजट के साथ किए गए बैंक द्वारा मंजूरी दे दी गई है, और हैं अच्छी तरह से प्रलेखित। परियोजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भविष्य में किसी भी बदलाव के लिए परियोजना को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, न ही बैंक नीति के अनुरूप, विशेष रूप से ऐसे समय में जब इस तरह के परिवर्तनों के स्रोत परे हो सकते हैं। स्थानांतरण समय सीमा।

42ए **अंतिम अवधि की आरएपी मूल्यांकन रिपोर्ट में 7 भूमि प्रभावित गांवों में कृषि से प्रति व्यक्ति आय में 37 प्रतिशत की वृद्धि, व्यापार से 50 प्रतिशत की वृद्धि, सेवा क्षेत्र में 11 प्रतिशत और श्रम क्षेत्र में 42 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। एलदाना और दसवाना (पुनर्वास कॉलोनियों) में, रिपोर्ट में कृषि से प्रति व्यक्ति आय में 81 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, व्यापार से 50 प्रतिशत की वृद्धि, निजी क्षेत्र के रोजगार में 34 प्रतिशत और श्रम गतिविधियों से 38 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई।**कृषि से प्राप्त आय वाले लोगों के लिए पर्याप्त वृद्धि को उन्नत कृषि तकनीकों की शुरुआत और आरएपी कार्यान्वयन के लिए नियुक्त गैर सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारियों के समर्थन के परिणामस्वरूप नोट किया गया था।

43ए सर्वेक्षण में इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया है कि पुनर्वास कॉलोनियों में बने घरों का औसत आकार पिछले घरों के आकार के दोगुने से अधिक है।. घरों का बढ़ा हुआ आकार निर्माण की उच्च लागत को दर्शाता है जिसे सर्वेक्षण में उद्धृत किया गया है।

44ए **परियोजना ने उन योजनाओं में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए लक्षित और अनुकूलित शमन उपाय विकसित किए हैं जो स्थानीय समुदायों पर परियोजना के संभावित सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का आकलन करने वाले कई अध्ययनों पर आधारित थे और इन उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।** अध्ययन और योजनाओं में एक व्यापक ईआईए, आरएपी और एक पुनर्वास कार्य योजना शामिल है। अंतिम अवधि की आरएपी मूल्यांकन रिपोर्ट हाट गांव से विस्थापित परिवारों के लिए बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का पता लगाती है।

45ए **बेसलाइन डेटा सामाजिक प्रभाव आकलन द्वारा प्रदान किया गया था और इसकी तुलना आरएपी मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट (2012) और समाप्ति अवधि आरएपी मूल्यांकन रिपोर्ट (2019) से की गई थी।** आधारभूत आधार के अनुसार, प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जो कि समुदाय अभी भी कर रहे हैं। कृषि के बाद सरकारी सेवा और फिर गैर–कृषि श्रम

---

9 2019 की अंतिम अवधि का मूल्यांकन आरएपी कार्यान्वयन के अंत में किया गया था (आरएपी कार्यान्वयन में 5 वर्ष लगे)। सभी हाट परिवारों (छह परिवारों को छोड़कर जिन्होंने मुआवज़ा लेने से इनकार कर दिया था) टर्म टर्म मूल्यांकन के समय तक पुनर्वास कॉलोनी में चले गए थे। पुनर्वास कॉलोनियों में स्थानांतरित होने वाले 77 परिवारों में से 75 प्रतिशत ने 2015 तक ऐसा किया था, और 94 प्रतिशत ने 2017 तक स्थानांतरित कर दिया था।

था। इनमें से कोई भी परियोजना के बाद के परिदृश्य में नहीं बदला है।

46ण **समुदाय के परामर्श से नियोजित और कार्यान्वित आजीविका बहाली उपायों के अलावा, परियोजना लाभ–साझाकरण तंत्रों का भी समर्थन करती है जो समुदाय का समर्थन करते हैं।** स्थानीय विकास कोष की दो श्रेणियां हैं :

- पहले में निर्माण अवधि के दौरान पाँच वर्षों में 19 प्रभावित गाँवों के लिए 90 मिलियन रुपये (लगभग 1.12 मिलियन डॉलर) की समर्पित निधि शामिल है। समुदायों द्वारा निवेश योजनाएं तैयार की जाएंगी। कुछ अनुबंध, प्छत् 200000 (लगभग 2500 डालर) तक, समुदाय के सदस्यों द्वारा कार्यान्वित किए गए थे।

- दूसरे की आवश्यकता है, जैसा कि राष्ट्रीय हाइड्रो नीति द्वारा अनिवार्य है, कि संयंत्र के लाभ का एक प्रतिशत परियोजना के कमीशन के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित समुदायों सहित व्यापक क्षेत्र में स्थानीय विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध हो।

47ण पीएपी की आजीविका को बहाल करने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में टीएचडीसी ने कई तरह की पहल की है, जिसमें प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, आजीविका प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास सहायता शामिल हैं। विस्थापित समुदाय के बहुमत (कुल 148 विस्थापित घरों में से 140) के रूप में, हाट के निवासियों को अक्सर इन पहलों के कार्यान्वयन में प्राथमिकता दी जाती थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

48ण परियोजना द्वारा नियुक्त किए गए 551 पीएपी में से 122 पीएपी हाट समुदाय से हैं (72 को टीएचडीसी द्वारा किराए पर लिया गया है और शेष 50 को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), परियोजना पर मुख्य सिविल वर्क्स ठेकेदार द्वारा किराए पर लिया गया है)। 551 पीएपी में से, टीएचडीसी ने 171 (18 स्थायी कर्मचारियों के रूप में; बाकी ठेका श्रमिकों के रूप में) को रोजगार दिया है, जबकि एचसीसी ने 218 पीएपी को सीधे नियोजित किया है और बाकी लोगों को वेंडरों, वाहनों को किराए पर लेने, भूमि को पट्टे पर देने, मकानों का किराया आदि जैसे अन्य माध्यमों से आय सहायता प्रदान की है।

49ण **इसके अलावा, परियोजना के तहत कई रोजगार वृद्धि के अवसर सृजित किए गए हैं।** परियोजना के तहत प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा, परियोजना के तहत पीएपी की आय बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए गए। 2014–2015 में, टीएचडीसी ने होटल प्रबंधन, मोटर यांत्रिकी और राजमिस्त्री जैसे क्षेत्रों में या फिटर, इलेक्ट्रीशियन, और उत्खनन ऑपरेटर जैसे व्यवसायों में 246 युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रायोजित किया। इसके अलावा, पात्र पीएपी को 200000 रुपये तक के छोटे सिविल कार्यों के निर्माण जैसे मंदिरों के रास्ते (हाट में स्थित नहीं), चारदीवारी और जलापूर्ति कार्यों के लिए अनुबंध दिए गए हैं।

50ण **इसके अलावा, सितंबर 2019 से, टीएचडीसी ने क्षेत्र में भूमि आधारित रोजगार के अवसरों को विकसित करने और पीएपी और अन्य समुदाय के सदस्यों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आजीविका विकास एजेंसी (मृदा) को नियुक्त किया है।** यह पहल परियोजना के साथ नौकरियों के लिए स्थानीय समुदायों की बढ़ती मांग के जवाब में थी, जिसे समर्थन देना परियोजना के लिए संभव नहीं था। कृषि आजीविका के अवसरों की पहचान करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करती है और उन्हें तकनीकी सहायता, सरकारी सब्सिडी तक पहुँचने, बाजार लिंकेज बनाने आदि में मदद करती है। अब तक कुल 104 पायलट कार्यान्वयन के अधीन हैं जिससे 241 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 56 लाभार्थी हाट समुदाय के हैं।

विष्णुगढ़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (तीसरा अनुरोध)

51ण **स्थानीय विकास निधि के तहत, मार्च 2022 तक, टीएचडीसी ने सामुदायिक विकास गतिविधियों को अपने स्थानीय लाभ–साझाकरण तंत्र के हिस्से के रूप में 104 मिलियन रुपये (लगभग 1.42 मिलियन डॉलर) के कुल बजट के साथ लागू किया था।** इनमें ऊपर उल्लिखित निर्माण/मरम्मत अनुबंधों के साथ, छोटी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण, समुदाय को स्वास्थ्य और शिक्षा सहायता प्रदान करना और आजीविका समर्थन शामिल हैं।

52ण **ईंधन और चारा पहुंच। परियोजना ईंधन और चारे के लिए सामुदायिक वन भूमि तक पहुंच के संभावित नुकसान के लिए शमन उपायों को लागू कर रही है।** यह मुआवजे के उपाय के रूप में ख़राब हुए क्षेत्रों में चारा सामग्री और पेड़ों के पुनरू रोपण के लिए वित्तपोषण कर रहा है। 2012 से, प्रत्येक प्रभावित परिवार को निर्माण अवधि

के दौरान ईंधन और चारा इकट्ठा करने के लिए वन पंचायत (यानी, सामुदायिक वन) तक पहुंच के अस्थायी नुकसान की भरपाई के लिए नकद वार्षिकी प्रदान की गई है। वार्षिकी न्यूनतम कृषि मजदूरी के 100 दिनों के बराबर है और सभी परियोजना प्रभावित गांवों के परिवारों को भुगतान किया जा रहा है। जुलाई 2022 तक, टीएचडीसी ने हाट समुदाय से 86 सहित 2,596 परिवारों को 122,786,00 (लगभग 1.57 मिलियन डॉलर) का संवितरण किया था। यह भत्ता निर्माण अवधि के अंत तक जारी रहेगा।

53ण हाट की 33 विधवाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिला है। भारतीय जीवन बीमा निगम (22 विधवाओं के लिए) और शेष 11 विधवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। टीएचडीसी ने इन दोनों एजेंसियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और विधवाओं के लिए पेंशन योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान किया है।

समुदाय के सदस्यों द्वारा जल स्रोतों तक कथित सीमित पहुंच

54ण पुनर्वास से पहले हाट समुदाय के पास पाइप से पीने का पानी नहीं था। पानी आस–पास के प्राकृतिक स्रोतों से लाना पड़ता था, जिससे प्रत्येक घर द्वारा वहन की जा सकने वाली मात्रा सीमित हो जाती थी। पुनर्वास क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को टीएचडीसी द्वारा निर्मित और अनुरक्षित जल आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से घर पर ही पाइप द्वारा जल प्राप्त होता है।

55ण टीएचडीसी पुनर्वास स्थल की घरेलू जरूरतों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम आपूर्ति से काफी अधिक पानी उपलब्ध करा रहा है।समुदाय की मांग के जवाब में पुनर्वास कॉलोनियों में पाइप से पानी की आपूर्ति को क्रमिक रूप से बढ़ाया गया है, प्रारंभिक 20,000 लीटर प्रति दिन से 40,000 लीटर प्रति दिन और फिर वर्तमान 64,000 लीटर प्रति दिन (या प्रति परिवार 810 लीटर प्रति दिन) तक। उत्तराखंड राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में कम से कम 55 लीटर/प्रति व्यक्ति/दिन के प्रावधान की परिकल्पना की जानी चाहिए।[10]

[10] केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा जारी ष्जल आपूर्ति और उपचारष पर मैनुअल के अनुसार, पाइप जलापूर्ति वाले लेकिन बिना सीवरेज वाले घरों के लिए न्यूनतम जल आपूर्ति 70 लीटर/प्रति व्यक्ति/दिन निर्धारित की गई है। 2019 में, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए इस मानदंड को संशोधित कर 55 लीटर/प्रति व्यक्ति/दिन कर दिया गया था। टीएचडीसी पुनर्वास कालोनियों में 810 लीटर/दिन/घर उपलब्ध करा रहा है।

फोटो 5: एलदाना पुनर्वास कॉलोनी में निजी आवासों के ऊपर अलग–अलग जल भंडारण टैंक।

56ण पीएपी के मुख्य पुनर्वास कॉलोनियों (एलदाना और दसवाना) में चले जाने के बाद, टीएचडीसी ने सभी घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराया। टीएचडीसी द्वारा स्थापित पंपिंग सुविधा में 24,000 लीटर क्षमता का एक मुख्य टैंक और दो पंप, एलदाना के लिए 10 एचपी का पंप और दसवाना के लिए 12 एचपी का पंप शामिल है।

57ण दसवाना में 6,000 लीटर क्षमता के दो टैंक हैं, और एलदाना में 5,000 लीटर क्षमता के चार टैंक हैं। टैंकों की कुल क्षमता 32,000 लीटर है, और पानी को दिन में दो बार पंप किया जाता है, जिससे दो कॉलोनियों में औसतन 64,000 लीटर या प्रति घर प्रति दिन 810 लीटर पानी की आपूर्ति होती है।

58ण टीएचडीसी नियमित रूप से पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता की निगरानी करता है और छह महीने के अंतराल पर टैंकों की सफाई करता है। पिछली बार जून 2022 में निगरानी की गई थी और गुणवत्ता स्वीकार्य पाई गई थी।

59ण **अनुरोध में उठाई गई पानी की कमी की शिकायतें पुनर्वास कॉलोनियों के भीतर समुदाय के सदस्यों द्वारा पानी के अनुचित उपयोग की प्रथाओं के कारण हो सकती हैं।** कई परिवारों ने अपनी निजी पानी की टंकियों को भरने के लिए सर्विस डिलीवरी लाइन में टैपिंग पंप स्थापित किए हैं (ऊपर फोटो 5 देखें)। यह पानी के दबाव और उपलब्ध मात्रा को प्रभावित करता है, और इसलिए गांव के सभी घरों में समान पानी की आपूर्ति को प्रभावित करता है, पाइप नेटवर्क के अंतिम छोर पर स्थित घरों पर अधिक बार प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति नेटवर्क को व्यक्तिगत घरेलू जल पंपों के संचालन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। इसके अलावा, कुछ परिवार वर्षा आधारित सिंचाई को बढ़ाने के लिए घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से अपने घरों के पास सब्जी के भूखंडों के लिए। **टीएचडीसी द्वारा मेन लाइन को पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद, सिंचाई के लिए घरेलू पेयजल का यह उपयोग भी समुदाय के सदस्यों द्वारा पानी की कमी की शिकायतों में योगदान देता है।** शिकायतों के जवाब में, टीएचडीसी ने वितरण पाइपों का व्यास बढा कर अंतिम छोर पर स्थित घरों के लिए जल आपूर्ति बढाई है।

60ण प्रबंधन की दृष्टि में, यह परियोजना के लिए नीति अनुपालन का मामला नहीं है, क्योंकि **टीएचडीसी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहा है। समुदाय द्वारा पानी को अनुचित रूप से मोड़ने के मुद्दे को निस्तारित करने की आवश्यकता है।** प्रबंधन ने सुझाव दिया है कि टीएचडीसी समुदाय को आंतरिक रूप से एक समाधान खोजने में सहायता

करने का प्रस्ताव करता है. जो पुनर्वास कॉलोनी में समान जल वितरण और खपत सुनिश्चित करेगा। प्रबंधन ने टीएचडीसी से पुनर्वास कॉलोनी में जल वितरण और खपत को मापने के साधनों पर विचार करने के लिए भी कहा है ताकि अधिक समान वितरण और खपत योजना स्थापित करने में मदद मिल सके।

कार्रवाई

61ण प्रबंधन को विश्वास नहीं है कि अनुरोध में उठाई गई चिंताएं बैंक की नीति का पालन न करने के कारण हुई हैं। हालांकि, प्रबंधन फिर भी टीएचडीसी के साथ नीचे दी गई कार्रवाइयों पर सहमत है, जो अनुरोधकर्ताओं की कुछ चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा।

- टीएचडीसी मंदिर के चारों ओर ढलानों पर वनस्पति लगाकर उन्हें और बढ़ाने की अपनी योजना को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले, टीएचडीसी ने वेटिवर घास लगाकर सियासैन डंपिंग क्षेत्र में एक बड़े ढलान को सफलतापूर्वक स्थिर कर दिया।[11]टीएचडीसी पहले से ही इस वृक्षारोपण को सभी डंपिंग साइटों को पूरी तरह से कवर करने के लिए विस्तारित करने पर सहमत हो गया था और मंदिर के आस–पास के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करेगा। इसके अलावा, वर्षा अपवाह के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, टीएचडीसी ने टीबीएम प्लेटफॉर्म तक पहुंच सड़कों के साथ अतिरिक्त जल निकासी का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है, सतही अपवाह को पास के प्राकृतिक नाले में प्रवाहित किया जाएगा।

- टीएचडीसी, समुदाय के परामर्श से, पानी के लिए अधिक समान पहुंच स्थापित करने के लिए पुनर्वास क्षेत्रों में पानी के उपयोग की निगरानी/विनियमन के लिए एक उपयुक्त तंत्र (या तो ग्राम सभा या एक समर्पित नई नागरिक समिति के माध्यम से) सभी घरों के लिए स्थापित करने में समुदाय का समर्थन करेगा।

निष्कर्ष

62ण प्रबंधन की दृष्टि में, बैंक ने अनुरोध द्वारा उठाए गए मामलों पर लागू नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। नतीजतन, प्रबंधन का मानना है कि बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में विफलता से अनुरोधकर्ताओं के अधिकार या हित सीधे और प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं और न ही होंगे।

[11] क्राइसोपोगोन ज़िज़ानियोइड्स

परिशिष्ट 1.
दावे और प्रतिक्रियाएं

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
1ए	**ओपी 4.11 भौतिक सांस्कृतिक संसाधन परिचालन मैनुअल** 1000 साल पुराने एक मंदिर और पूजा के पवित्र स्थान को गंभीर रूप से खतरे में डालने और मौजूदा विरासत और परंपराओं को नष्ट करने के लिए टीएचडीसीआईएल ने हाट गांव और पूरे देश के लिए गंभीर अपकार किया है। यह ग्रामीणों या उनकी पारंपरिक प्रथाओं पर उचित विचार किए बिना आगे बढ़ा है, और यहां तक कि ईआईए में मंदिर की प्रासंगिकता को छुपाने का अहंकार और छल भी था। यह इस मामले में विश्व बैंक की नीति का सीधा उल्लंघन है जैसा कि नीचे स्पष्ट है – **हाट की अनूठी ऐतिहासिकता** कि हाट गांव एक प्राचीन टोला है जो भारत के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। 9वीं शताब्दी के आसपास आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी–नारायण मंदिर की स्थापना की और इसके साथ ही नित्य पूजा के लिए हाट के ग्राम समुदाय को जोडा। इसके लिए वह बंगाल से गौड़ ब्राह्मणों को लाए और वे यहाँ बस गए। प्राचीन समय में यह श्री बद्रीनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों का मुख्य आधार (मुख्यपदाव) था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित लक्ष्मी नारायण का मंदिर आज भी हाट में खड़ा है और सभी अनुष्ठान 2007 तक हो रहे थे, जब टीएचडीसीएल ने जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू किया। बद्रीनाथ से पहले अंतिम पड़ाव होने के नाते, इस मंदिर ने उन लोगों को पूजा के लिए एक वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जो बद्रीनाथ तक की कठिन चढाई नहीं कर सकते थे, इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल बन गया। मुख्य लक्ष्मी–नारायण मंदिर के आसपास शिव, चंडिका, गणेश और सूर्य कुंड जैसे अन्य देवताओं के मंदिरों का समूह है, जो सभी 8–9वीं शताब्दी के हैं। इसके अलावा, स्थानीय देवता (बगड़वाल, भीमयाल, हनुमान, बिल्वेश्वर) भी हैं जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए थे और हमारी समृद्ध संस्कृति और संपन्न परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। **एएसआई द्वारा 04-04-2022 को स्वीकृत हाट की ऐतिहासिकता** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 15-03-2022 को हाट स्थल का दौरा किया और 04-04-2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। चूंकि लक्ष्मी नारायण मंदिर आश्चर्यजनक रूप से 1000 साल पुराना है, आंतरिक गर्भगृह अभी भी मूल संरचना के साथ है, इसे तुरंत मंदिर को एक प्राचीन स्मारक के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी और इसे उचित संरक्षण प्रदान करना चाहिए था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि 'लक्ष्मी नारायण मंदिर *प्राचीन संरचना के रूप में माने जाने के अत्यंत* लायक पाया गया है *...'और फिर भी यह निंदनीय है कि ऐसी साइट को संरक्षित नहीं किया गया है और इसके बजाय मलबे के डंपिंग के लिए चुना गया है।*	*परियोजना की तैयारी के भाग के रूप में लक्ष्मी–नारायण मंदिर सहित भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का मूल्यांकन ओपी 4.11 के अनुरूप किया गया था। परियोजना ने मंदिर परिसर के संरक्षण और उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएँ विकसित की हैं। स्थल पर हुए कार्यों से मंदिर प्रभावित नहीं हुआ है, न ही भविष्य के कार्यों से प्रभावित होने का खतरा है।* अनुरोध में एएसआई द्वारा बहुत चुनिंदा रूप से मंदिर के 2022 के आकलन का हवाला दिया गया है। "हाटगाँव (ग्राम हाट) में लक्ष्मी नारायण मंदिर के संरक्षण के लिए निरीक्षण रिपोर्ट" ("रिपोर्ट") में लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ–साथ अन्य संरचनाओं और अवशेषों की एक महत्वपूर्ण संख्या, जो "मंदिर की पृष्ठभूमि में थे", का व्यापक मूल्यांकन शामिल था। एएसआई ने जहां पहचान किए गए अवशेषों की एक बहुत ही चुनिंदा संख्या के संरक्षण के लिए कहा है, रिपोर्ट बताती है कि शेष संरचनाएं "जो कि प्राचीन, प्रकृति की मानी जाती थीं, लेकिन [...] साधारण घर या उनके अवशेष पाए गए हैं जो कि किसी पुरातात्विक या कलात्मक विशेषता से रहित हैं।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि "--केवल लक्ष्मी नारायण मंदिर को प्राचीन संरचना के रूप में माने जाने लायक पाया जाता है जिसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है और जिसकी छत और मंडप और हॉल को सीमेंट, कंक्रीट से बदल दिया गया है।" अंत में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टीएचडीसी ने पिछले 2–3 वर्षों से लक्ष्मी नारायण मंदिर के संरक्षण कार्य को करने के लिए एएसआई से संपर्क किया है। रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के काम पर विचार किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय समुदाय और टीएचडीसी के साथ एक समझौते की जरूरत होगी ताकि एएसआई कुशलता से काम कर सके। *भौतिक सांस्कृतिक संसाधन मूल्यांकन : जैसा कि परियोजना के ईआईए में वर्णित है[1] 2009 में, परियोजना स्थलों के 7 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को कवर करते हुए एक पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी।* 63 गांवों में से 10 में पुरातात्विक/विरासत अवशेष हैं।[2] ये अवशेष विभिन्न प्रकार (संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, धार्मिक मूर्तियां, महापाषाण दफन) और विविध सांस्कृतिक महत्व के हैं, इसलिए अनुरूप संरक्षण उपायों की आवश्यकता है। 2009 ईआईए के तहत किए गए सर्वेक्षण ने हाट में लक्ष्मी नारायण मंदिर को एकमात्र उल्लेखनीय स्मारक के रूप में पहचाना, लेकिन कहा कि "यह मंदिर केंद्रीय और राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची में नहीं है।" ईआईए में इन निष्कर्षों के आधार पर, प्रोजेक्ट ईएमपी में लक्ष्मी नारायण मंदिर, और अन्य पहचाने गए सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण और उन्नत करने के लिए एक विशेष योजना शामिल है।

[1] वीपीएचईपी के लिए पर्यावरण अध्ययन, नवंबर 2009, 2008026/ईसी/अंतिम रिपोर्ट।

[2] अनुभाग देखें ७.10.4। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, नवंबर 2009 के अन्वेषण परिणाम ß

	21.12.2021 को इन्टैक ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाट गांव के स्थल की सुरक्षा की जानी चाहिए– गाँव और प्राचीन मंदिर संरचनाओं के सांस्कृतिक महत्व का संज्ञान लेते हुए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इन्टैक) ने भी पूरे गाँव के जीर्णोद्धार की सिफारिश की। इन्टैक द्वारा भेजा गया एक पत्र जिसकी प्रति विश्व बैंक और ठीएचडीसीआईएल को भेजी गई है, उसमें कहा गया है: *"प्राचीन मंदिर स्थल और हाट गांव से जुड़े उच्च महत्व को देखते हुए, हम टीएचडीसी से प्राचीन मंदिरों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति के रूप में मान्यता देने और वित्त पोषण एजेंसी, विश्व बैंक से प्रभावित स्थलों को बहाल करने और विश्व बैंक के स्थायी आजीविका के जनादेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक गांव को पूरी तरह से परियोजना के हिस्से के रूप में के संरक्षित करने का आग्रह करते हैं।"*	टीएचडीसी ने 2013 में लक्ष्मी नारायण मंदिर और इसके आसपास के इलाकों का आगे आकलन करने के लिए पुरातत्व अनुसंधान एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण/संरक्षण के लिए देश के सक्षम निकाय एएसआई को नियुक्त किया। समुदाय के अनुरोधों के जवाब में, टीएचडीसी ने 2017 में एएसआई से एक अतिरिक्त आकलन कार्य करने का अनुरोध किया। 2022 में एएसआई ने स्थानीय समुदाय के साथ उपरोलिखित समझौते के अधीन मंदिर के जीर्णोद्धार की इच्छा व्यक्त की। अप्रैल 2022 की रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है: "यद्यपि मंदिर की तिथि निश्चित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थापत्य के आधार पर यह 11वीं–12वीं शताब्दी ईस्वी का हो सकता है" ***यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए थे, इसलिए उनका मंदिर की स्थापना से सीधा संबंध संभव नहीं है।*** "लक्ष्मी नारायण मंदिर एक साधारण वास्तुकला है, दोनों आंतरिक और बाहरी […] गर्भगृह को छोड़कर, शेष घटक पुराने नहीं हैं और बाद में जोड़े गए हैं। […] मंदिर के विभिन्न स्तर, स्थापत्य घटक […] सुझाव देते हैं कि मंदिर परिसर में कई परिवर्तन और परिवर्धन हुए हैं"। टीएचडीसी लक्ष्मी नारायण मंदिर के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि ईएमपी में शामिल किए जाने से पता चलता है और ईएमपी में इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, यदि आवश्यक हो। जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, साइट का पेशेवर और गुणवत्ता मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसी भी एएसआई के साथ नियमित संपर्क में है। *लक्ष्मी नारायण मंदिर की वर्तमान स्थिति :2014 की जांच रिपोर्ट (पैराग्राफ 209–210) में निर्धारित सिफारिशों के अनुरूप, परियोजना ने लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। मंदिर से दूर मलबा हटाया जा रहा है। इस मुद्दे पर आगे की चर्चा के लिए, आइटम 5 देखें।* टीएचडीसी द्वारा मंदिर और उसके आसपास के निर्माण के बाद की लैंडस्केपिंग योजना तैयार की गई है और यह क्षेत्र के लिए पहुंच और सौंदर्य संबंधी चिंताओं को दूर करेगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर के संरक्षण के प्रयासों के अलावा, ईएमपी के अनुसार हाट गांव में अन्य भौतिक सांस्कृतिक संसाधन संरक्षण के प्रयास किए गए हैं: - ग्राम प्रधान और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के परामर्श से बिलवा के पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है। - गांव के अन्य छोटे सामुदायिक मंदिरों को भी संरक्षित किया जाएगा। ईएमपी ने इसके लिए धन का बजट तैयार किया है

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		गांव के मंदिरों में वृद्धि; जरूरत पड़ने पर टीएचडीसी पूरक धनराशि देने को तैयार है। – छोटे निजी घरों में मंदिरों और मंदिरों को निवासियों के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है।
2ए	**हाट में मिला तांबे का प्राचीन शिलालेख (ताम्रपत्र)।** कि, इसके अतिरिक्त 8–9वीं शताब्दी का एक प्राचीन ताम्रपत्र श्ताम्रपत्रश भी मौजूद है, जो गांव हाट की प्राचीन ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है। इस तांबे के शिलालेख का पुरालेख अध्ययन एएसआई में प्रक्रियाधीन है और अंतिम रिपोर्ट अगस्त में आने की उम्मीद है। फिर भी प्रारंभिक जानकारी ने पुष्टि की है कि शिलालेख को 9वीं शताब्दी के एक व्यापारी द्वारा बनाया गया है, यह हाट गांव का भी उल्लेख करता है और एक मंदिर को भी संदर्भित करता है। इस प्रकार जगह की ऐतिहासिकता को मान्य करना। **2014 – कॉपर शिलालेख** महान ऐतिहासिक मूल्य और साक्ष्य की इस कलाकृति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि 2014 की टीम ने किसी भी तरह से स्थल और मंदिर की अपार सांस्कृतिक और विरासत क्षति की जांच नहीं की थी। हालांकि आज, जब ग्रामीणों को एहसास हुआ कि वे अपनी आवाज उठा सकते हैं, एएसआई और इनटैक ने स्वीकार किया कि स्थल और मंदिर संरक्षण के योग्य हैं।	तांबे के शिलालेख के अस्तित्व को दिसंबर 2021 में प्रबंधन के ध्यान में लाया गया था। प्रबंधन तांबे के शिलालेख के मूल स्थान, इसके मूल स्थान, या इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता से अवगत नहीं है, और इसलिए इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। प्रबंधन आगे नोट करता है कि एएसआई हाट साइट की अपनी तीन समीक्षाओं में से किसी में भी ष्तांबे के शिलालेखष का उल्लेख नहीं करता है।
3ए	**टीएचडीसीआईएल ने अपने ईआईए के लिए 2009 में मंदिर का पुरातत्व सर्वेक्षण किया** टीएचडीसीआईएल द्वारा 2009 में की गई पुरातात्विक रिपोर्ट में ही स्वीकार किया गया है कि लक्ष्मी–नारायण मंदिर 'परियोजना तत्काल प्रभावित क्षेत्र' (पीआईएए) में स्थित है, यानी परियोजना स्थल के 500 मीटर के भीतर। यह निम्नानुसार बताता है : *"लक्ष्मी–नारायण हाट में PIAA क्षेत्र में स्थित है। मंदिर 9–10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का हो सकता है। यह मंदिर कई संरचनात्मक परिवर्तनों और परिवर्धन के तहत चला गया है, लेकिन गर्भगृह / गर्भगृह अपनी स्थिति में है, आंशिक रूप से दफन है।"* आगे पहाड़ी गाँवों की जीवित परम्पराओं को पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है जिसमें कहा गया है – *'सांस्कृतिक संपत्तियों, स्थलों, लोककथाओं, किंवदंतियों, इमारतों जैसे पुरातात्विक अवशेषों के अलावा लगभग सभी 63 गांवों ने अपने पुरातात्विक, प्राकृतिक धार्मिक और पवित्र विरासत को बहुत ही अनुष्ठान और पारंपरिक तरीके से संरक्षित किया है।'* **लेकिन टीएचडीसीआईएल ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दबा दिया** यदि परियोजना प्राधिकरण (टीएचडीसीआईएल) ने प्राचीन मंदिर, जिससे हमारा ग्राम समुदाय अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, और जो इसे एक संरक्षित स्थल बनाता है, की उपस्थिति की सटीक सूचना दी होती तो हमारे गांव को पहली बार में ही उखड़ कर पुनर्वासित नहीं किया जाना चाहिए था।	***यह गलत है कि टीएचडीसी ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दबा दिया है। परियोजना दस्तावेज स्पष्ट रूप से मंदिर के अस्तित्व, सक्षम राष्ट्रीय निकाय एएसआई द्वारा वर्गीकरण के अनुसार इसके महत्व, साथ ही साथ मंदिर परिसर के प्रबंधन, संरक्षण और वृद्धि के लिए प्रस्तावित कदमों का संकेत देते हैं।*** ***अनुरोध में आरोपित शब्द ("परियोजना का सांस्कृतिक संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है") परियोजना के ईआईए में प्रकट नहीं होता है। वास्तव में, ईआईए के निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधान हैं :*** **धारा 2-4 विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों की प्रयोज्यता (2009 की ईआईए रिपोर्ट का पृष्ठ 9] अध्याय 2)भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों के संबंध में कहता है कि :** *"परियोजना प्रभावित क्षेत्र के भीतर, कुछ पुराने, परित्यक्त भवन/ढांचे हैं, जो हाट गांव से सियासैन गांव के रास्ते में पड़ते हैं। तीर्थयात्री बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान इसी स्थान पर रुकते थे। यह सुझाव दिया जाता है कि संरचनाओं की सही उम्र का पता लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रस्तावित विकास के लिए संरचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांस्कृतिक गुणों (जैसे सामुदायिक धार्मिक गुण, पवित्र उपवन, और मौका–खोज) पर प्रभाव की बहुत कम संभावना है। ईआईए में ऐसी संपत्तियों की पहचान करने और ऐसी संपत्तियों के प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए की प्रक्रियाएँ शामिल हैं,। निर्माण के दौरान यदि कोई कलाकृतियां पाई जाती हैं तो चांस फाइंड प्रक्रिया लागू होगी।*

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
	लेकिन, दुर्भाग्य से कंपनी ने अपने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट में निम्नानुसार कहा है : *"7-6 भौतिक और सांस्कृतिक संसाधनों पर प्रभाव :* ***परियोजना प्रभावित क्षेत्र और परियोजना तत्काल प्रभावित क्षेत्र के भीतर सांस्कृतिक संसाधनों पर परियोजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।–(टीएचडीसी, ईआईए रिपोर्ट)*** टीएचडीसी द्वारा अपने ईआईए दिनांकित (अपलोड) 2009 में की गई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि हालांकि मंदिर की बाहरी संरचना अतीत में आंशिक रूप से ढकी और मरम्मत की गई हो सकती है, मंदिर का आंतरिक गर्भगृह अभी भी मूल है। लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के समय छुपाया गया था, और हमारे गांव को बिना सोचे–समझे कूड़ा डंप क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। वास्तव में, यदि अधिकारी ईमानदार होते, और अच्छे इरादे रखते, तो वे विशेषज्ञों की मदद से मंदिर को उसके पुराने पारंपरिक स्थापत्य डिजाइन और सुंदरता के लिए बहाल कर देते। वास्तव में उन्हें उसी समय एएसआई को सूचित करना चाहिए था और परियोजना को कहीं और स्थानांतरित कर देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने 2016 को छोड़कर एएसआई से संपर्क नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप न केवल हमारे समुदाय बल्कि हमारी राष्ट्रीय विरासत के साथ भी घोर अन्याय हुआ है।	**पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट (पृष्ठ 186 – 2009 की ईआईए रिपोर्ट का अध्याय 3) कहा गया है कि "यह सुझाव दिया जाता है कि अलकनंदा नदी के दाहिने हाथ की ओर के गांवों में पड़ने वाले मंदिरों को बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के लिए विचार किया जा सकता है"। परिच्छेद में हाट का भी उल्लेख है। इसके अलावा, रिपोर्ट मौका खोजने की प्रक्रिया पर विस्तार से बताती है और प्रबंधन/संरक्षण उपायों के लिए सिफारिशों का वर्णन करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "पुरातत्व प्रबंधन के लिए 25,00,000/– रुपये (पच्चीस लाख रुपये) का अस्थायी बजट प्रस्तावित है।"** **2009 की ईआईए रिपोर्ट की धारा 3.10 (पृष्ठ 174–175)कहा गया है कि :** "इस मंदिर में कई संरचनात्मक परिवर्तन और परिवर्धन हुए हैं, लेकिन गर्भगृह / पवित्र स्थल अपनी स्थिति में है, आंशिक रूप से जमींदोज है। चूंकि यह मंदिर केंद्रीय और राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची में नहीं है। लंबे समय से उपेक्षित होने के कारण, लक्ष्मी–नारायण की मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, मूल मूर्ति/ प्रतिमा के स्थान पर दसावतार की छवियों को दर्शाती एक आधुनिक सीमेंटेड अनुपातहीन आकृति को मूल नक्काशीदार पत्थर के फ्रेम के भीतर रखा गया है, जबकि पाँच फ्रेम के ऊर्ध्वाधर खंभे पर हैं। अमलका जैसे शिखर के कुछ घटक परिसर में बिखरे पड़े हैं। इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है।
4ण	**हाट की पूरी ग्राम सभा ने मंदिर को संरक्षित विरासत स्थल घोषित करने का संकल्प पारित किया।** दिनांक 28-03-2022 को ग्राम सभा हाट की बैठक में लक्ष्मी–नारायण एवं अन्य मंदिरों को ग्राम सभा द्वारा संरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। संकल्प इस प्रकार बताता है : *"आज हम सभी प्रतिनिधि और ग्राम सभा हाट के सदस्य सर्वसम्मति से हमारे भगवान लक्ष्मी–नारायण के मंदिर के साथ–साथ हाट के अन्य मंदिरों के समूह की घोषणा करते हैं। चंडिका देवी, शिव मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, सूर्यकुंड आदि हमारी ग्राम सभा द्वारा संरक्षित हैं जिसमें और उसके आस–पास कोई हानिकारक या हानिकारक गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा हम घोषणा करते हैं कि ग्राम हाट सदियों से भगवान लक्ष्मी–नारायण के मंदिर और मंदिरों के अन्य समूह का मालिक है" (अंग्रेजी अनुवाद)*	प्रबंधन हाट ग्राम सभा के संकल्प को स्वीकार करता है जिसमें लक्ष्मी नारायण और अन्य मंदिरों को ग्राम सभा द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सांस्कृतिक महत्व को भी ईआईए द्वारा पहचाना गया और ईएमपी में परिलक्षित किया गया; जैसा कि ऊपर बताया गया है, टीएचडीसी ओपी 4-11 के अनुरूप इस मंदिर के लिए शमन उपाय करना जारी रखता है। ***हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्राम सभा इमारतों के ऐतिहासिक चरित्र और पुरातात्विक सुरक्षा के लिए उनकी योग्यता पर राय देने के लिए सक्षम प्रशासनिक निकाय नहीं है।*** ***निरीक्षण पैनल की टिप्पणियों और दृढ़ संकल्प, 20 अप्रैल, 2022 :*** 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण की अपनी सूचना में, पैनल ने संकेत दिया कि "इस अनुरोध में उठाई गई चिंताएं – पुनर्वास, पुनर्वास और भौतिक सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सहित – परियोजना के पहलुओं से संबंधित हैं। जिन्हें 2014 की जांच में संबोधित किया गया था। पैनल प्रबंधन के इस बयान को भी नोट करता है कि गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर और अन्य छोटे सामुदायिक मंदिरों की रक्षा की जाएगी। [-..] पैनल आगे नोट करता है कि सुरक्षात्मक उपाय वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
5ण	**मंदिर के ठीक पीछे मलबा फेंक कर टीएचडीसीआईएल ने मंदिर को खतरे में डाला– मार्च 2022** सुरंग बोरिंग मशीन (टीबीएम) द्वारा 2016 से उत्पन्न टनों मलबे को गर्भगृह से बमुश्किल 10 मीटर की दूरी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक पीछे फेंक दिया गया है। इस मलबे को सहारा देने वाली दीवार एक कमजोर गेबियन दीवार है और गिरने के कगार पर है। इसके अलावा चरम मौसम की घटनाओं, बादल फटने और जलवायु परिवर्तन के कारण केंद्रित वर्षा के मामले में, जैसा कि उत्तराखंड पिछले एक दशक से नियमित रूप से देख रहा है, प्राचीन मंदिर बहने वाले टनों मलबे के नीचे दफन होने के अत्यधिक खतरे में है। सितंबर 2021 को 16 परिवारों के अंतिम समूह के घरों को गिराए जाने और बलपूर्वक बेदखली के बाद, टीएचडीसीआईएल ने मार्च–2022 में गांव क्षेत्र के अंदर मलबा डंप करना भी शुरू कर दिया, जबकि पुनर्वास के संबंध में विश्व बैंक और निरीक्षण पैनल के साथ हमारी बातचीत चल रही थी। यह आज तक जारी है और मलबे की ऊंचाई चंडिका मंदिर और अन्य मंदिरों के समूह की ऊंचाई को पार कर गई है। चूंकि मुख्य हेड रेस टनल पर काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मलबे की ऊंचाई अंततः लक्ष्मी नारायण मंदिर से भी अधिक हो जाएगी, जो वास्तव में स्मारक के लिए मौत की सजा होगी। **एएसआई की अप्रैल–2022 की रिपोर्ट में बताया गया है कि मलबा मंदिरों को खतरे में डाल रहा है :** प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को हाट में साइट का दौरा करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात एएसटी देहरादून सर्कल के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया और 04-04-2022 को एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें प्राचीन लक्ष्मी–नारायण मंदिर की उपस्थिति को भी स्वीकार किया गया और इसके संरक्षण उपायों की सिफारिश की गई। एएसआई ने कूड़ा डंपिंग रोकने और डंपिंग जोन को मंदिर से दूर हटाने की भी सिफारिश की। एएसआई की दिनांक 04-04-2022 की रिपोर्ट इस प्रकार है : *'वर्तमान में मंदिर के ऊपरी हिस्से में टीएचडीसी द्वारा चट्टान से भरे तार पिंजरों से बनी एक ब्रेस्ट वॉल प्रदान की गई है जो डंप की गई मिट्टी/अपशिष्ट सामग्री के दबाव का सामना करने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होती है। बारिश के मौसम में मिट्टी के भीतर जलभृत बनने के कारण दबाव बढ़ सकता है। टीएचडीसी एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई आरआरसी या चिनाई वाली दीवार प्रदान कर सकता है और यदि संभव हो तो मंदिर के ऊपरी हिस्से में न्यूनतम डंपिंग का सुझाव दिया जाता है।'* *'डंपिंग क्षेत्र मंदिर से दूर होना चाहिए।'* *'टीएचडीसी को सबसे पहले मंदिर परिसर के पास कूड़ा डंप करना बंद करना चाहिए और अन्य उपलब्ध क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए और मौजूदा मंदिरों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए मुख्य मंदिर और अन्य सहायक मंदिर सहित बाहरी सीमा का निर्माण करना चाहिए।'*	***कोई मलबा नहीं डाला जा रहा है या मंदिर के पीछे या उसके आस–पास फेंका नहीं जाएगा और परियोजना कार्यों से मंदिर को कोई खतरा नहीं है।*** *मंदिर के पीछे की दीवार मलबा डंपिंग कार्यों से जुड़ी नहीं है। इस दीवार का उद्देश्य विशेष रूप से इसके पीछे की ढलान को मजबूत और सहारा देकर मंदिर की रक्षा करना है।* *चिंताओं को व्यक्त किया गया है (अनुरोधकर्ताओं द्वारा उद्धृत एएसआई रिपोर्ट सहित) कि मंदिर के पीछे गेबियन दीवार इतनी मजबूत नहीं हो सकती है कि डंप किए गए कचरे के लिए एक रिटेनिंग वॉल के रूप में कार्य कर सके। वास्तव में, ये चिंताएँ अप्रासंगिक हैं क्योंकि दीवार के पीछे कोई मलबा नहीं डाला जा रहा है। दीवार को इसके पीछे के ढलान को सहारा देने के लिए डिजाइन किया गया है और यह एक मजबूत संरचना है, जिसका आधार 9 मीटर चौड़ा है।* *यही बात अनुरोध से जुड़े तकनीकी पेपर ("हट विलेज में एडिट टनल से मलबा डंपिंग के लिए वैकल्पिक स्थान के लिए सुझाव") पर भी लागू होती है। यह पेपर इस गलत धारणा पर आधारित है कि मलबा डाला जाता है और "[---] मंदिर के ऊपर" जमा किया जाता है और इसलिए पेपर के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और अप्रासंगिक हैं।* ***टीएचडीसी ने पुष्टि की कि वह मलबा डंप करने के लिए मंदिर से कुछ दूरी पर गांव में अन्य क्षेत्रों का उपयोग कर रहा है।*** *परियोजना के लिए मलबा डालने के लिए साइटों की पहचान करने की प्रक्रिया में, टीएचडीसी ने परियोजना क्षेत्र के भीतर कई साइटों पर विचार किया। चार मानदंडों के आधार पर अंतिम रूप से चार का चयन किया गया जिसमें परिदृश्य, लागत प्रभावशीलता, उत्पादन के स्रोत से निकटता, भूजल/सतही जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव, राहत, वनीकरण का दायरा, और कटाव नियंत्रण/तलछट को रोकना शामिल था। इन साइटों को सभी आवश्यक वैधानिक और नियामक अनुमतियां प्राप्त हुई हैं, और अगस्त 2021 के नवीनतम ईसी में परिलक्षित होती हैं। इस ईसी की समीक्षा की गई और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए भारत के सर्वोच्च निकाय एनजीटी द्वारा इसे बरकरार रखा गया।* ***परियोजना के तहत जमा किए जाने वाले मलबे के प्रारंभिक अनुमानों को परियोजना के डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद अद्यतन किया गया था। चूंकि हाट, जिसे पहले से ही मलवा डंपिंग साइट के रूप में नामित किया गया था और अधिग्रहीत भूमि में अपेक्षित अतिरिक्त मलबे को सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए पर्याप्त जगह थी, मलवा जमा करने के साथ मंदिर से काफी दूर पूर्व गांव के अन्य हिस्सों में,इस साइट (अन्य तीन स्थानों के साथ) का पूरी तरह से उपयोग करने का निर्णय लिया गया था।*** **निरीक्षण पैनल की टिप्पणियों और दृढ़ संकल्प, 20 अप्रैल, 2022 :** • जैसा कि 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण के पैनल के नोटिस में संकेत दिया गया था, पैनल ने नोट किया कि "मंदिर की दीवार के पीछे कूड़ा डंप नहीं किया जाएगा।"

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
	इसके बावजूद आज भी कूड़ा डंपिंग बदस्तूर जारी है। अंत में, पूरी त्रासदी को खत्म करने के लिए गांव अब 1000 साल की विरासत के विनाश का सामना कर रहा है, और 1000 साल पुराने मंदिर के धीमे लेकिन अपरिवर्तनीय विनाश में पीढ़ियों की भक्ति, प्रतिदिन कीचड़ में दबी जा रही है। **लक्ष्मी नारायण मंदिर के विनाश से सांस्कृतिक और विरासत की हानि को 2014 में निस्तारित नहीं किया गया –** रिपोर्ट में ही कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर को एक स्वयंप्रकाश मंदिर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह मंदिर या उसमें मूर्ति नहीं है जो पवित्रता की प्राथमिक वस्तु है बल्कि साइट ही है। हालांकि मलबा डंपिंग के लिए किसी वैकल्पिक साइट पर कभी विचार नहीं किया गया। पृष्ठ 57 पीटी 209 पर यह कहा गया है: 'जबकि वीएचईपीपी इस स्वयंप्रकाश मंदिर को नहीं डुबोएगा और इसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, यह निर्माण संबंधी गड़बड़ी का अनुभव कर सकता है क्योंकि मुख्य सुरंगों में से एक मंदिर के पास स्थित है।" इस 1000 साल पुरानी संरचना के महान महत्व या इसके आसपास के क्षेत्र में मलबा डंपिंग के प्रभाव, या सदियों पुरानी परंपराओं और विरासत के नुकसान के माध्यम से ग्रामीणों को नुकसान की भावना का कोई अन्य संदर्भ नहीं है।	• पैनल ने यह भी नोट किया कि मलबा डंपिंग के किसी भी संभावित जोखिम, जिससे मंदिर को खतरा होगा, को कम करने के लिए "सुरक्षात्मक उपायों को लागू किया जा रहा है"। • पैनल ने कहा कि "इसी तरह की प्रतिबद्धता परियोजना अधिकारियों द्वारा भी की गई थी और 2014 की जांच रिपोर्ट में शामिल की गई थी।" • वास्तव में, अपनी 2014 की जांच रिपोर्ट में, पैनल कचरा निपटान के मुद्दे को स्पष्ट करने वाले प्रबंधन के महत्व को नोट करता है। पैनल कंपन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए टीबीएम तकनीक का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमों को नोट करता है। पैनल सुरंगों के साथ 500 मीटर गलियारे के भीतर आने वाली संरचनाओं के संभावित नुकसान को कवर करने के लिए एक बीमा योजना की परियोजना में प्रावधान को भी नोट करता है। पैनल ने पाया कि ये उपाय संभावित नुकसान को कम करने या कम करने के कदम के रूप में बैंक नीति ओपी/बीपी 4-01 का अनुपालन करते हैं। पैनल ने पाया कि ओपी/बीपी 4-37 के अनुपालन में, प्रबंधन ने भूकंप, भूस्खलन और चरम मौसम से संबंधित अनुरोध में उठाए गए जोखिमों को कम करने के लिए परियोजना डिजाइन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन चरणों के दौरान टीएचडीसी द्वारा प्रासंगिक अध्ययनों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए।" 2014 के निरीक्षण पैनल जांच रिपोर्ट के जवाब में प्रबंधन रिपोर्ट और सिफारिश में कहा गया है कि, "प्रबंधन ओपी/बीपी 4.01 और 4.37 के प्रावधानों के साथ बैंक के अनुपालन के पैनल के मूल्यांकन का स्वागत करता है। प्रबंधन इस बात से सहमत है कि सुरंग उत्खनन उप–उत्पादों का निपटान इस तरह से किया जाना चाहिए जो नदी के किसी भी संदूषण को रोकता है और एक अनुकूली प्रबंधन मोड में होता है। वीपीएचईपी का अनुमान है कि टीबीएम ऑपरेशन से उत्खनित मलबे को सुरंग के जरिए कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से उस स्थान पर ले जाया जाएगा जहां से इसे स्पॉइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्थानांतरित किया जाएगा, जो रेल या डीजल ट्रकों द्वारा हो सकता है। इस मामले में मलबा मुख्य रूप से चट्टान के टुकड़ों से बनी होगी और घोल या रसायनों के साथ मिश्रित नहीं होगी।" **पृष्ठभूमि, शमन उपाय और वर्तमान स्थिति:** कूड़ा डंप साइट और इन साइटों पर जमा की जाने वाली मात्रा को पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरणीय क्लियरेंस के माध्यम से भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए 08/22/2007 को दस साल, जिसे बाद में तीन बार बढ़ाया गया (2017 से 2020 तक तीन साल के लिए, 2020 से एक साल के लिए 08/21/2021 तक, और 10 साल के लिए 08/26/2021 से शुरू) के लिए अनुमोदित किया गया है (जैसा कि एमओईएफसीसी तब जाना जाता था) । एमओईएफसीसी द्वारा प्रदान की गई 2021 की पर्यावरणीय मंजूरी में चार डंपिंग साइटों और इन चिन्हित साइटों में उत्पन्न और डंप किए जाने वाले मलबे की अनुमानित मात्रा का उल्लेख है।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		PMF of 10840 cumec. (xvii) **Muck Disposal Areas**: Out of the 40.00 L cum (lakh cubic meter) of the total muck likely to be generated from the construction works of the project at least 14.00 L cum will be utilized for construction purposes of different project components, filling works and other infrastructure works. For dumping of the remaining muck i.e. 31.20 Lcum, four dump yards areas viz. (i) Haat, (ii) Jaisaal, (iii) Gulabkoti and (iv) Siyasain, have been earmarked adjacent to project components and are operational. In these 4 identified sites dumping will be done and further they will be restored and vegetated with proper landscaping. *2021 पर्यावरणीय मंजूरी से अंश, मलवा निपटान क्षेत्रों का संकेत* कुछ अपीलकर्ताओं की अपील के आधार पर, 16 अगस्त, 2022 को एमओईएफसीसी द्वारा परियोजना को 2021 में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाते हुए, एनजीटी ने निष्कर्ष निकाला कि "परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर दिया गया है [...], कि ईएसी ने पर्यावरणीय प्रभावों के मुद्दों को संबोधित किया है जिसमें मिट्टी का क्षरण, घटती पानी की गुणवत्ता, सौंदर्य मूल्य में कमी, जलीय जैव विविधता की हानि और ब्लास्टिंग के प्रभाव शामिल हैं और प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं। [---] पर्यावरणीय मंजूरी दिनांक 26/08/2022 में कोई प्रक्रियात्मक अवैधता नहीं है [---]" ***प्रारंभिक मलबा अनुमान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर आधारित था, जिसे परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने से कई साल पहले 2006 में तैयार किया गया था।*** *डीपीआर ने हेडरेस टनल (एचआरटी) की खुदाई के लिए टीबीएम के उपयोग पर विचार नहीं किया। डीपीआर के आधार पर, 2009 ईएमपी ने अनुमान लगाया कि वीपीएचईपी द्वारा लगभग 1.5 मिलियन घन मीटर मलबा उत्पन्न किया जाएगा। चिन्हित किए गए चार डंप स्थलों में से हाट गांव में मलवा निपटान क्षेत्र की क्षमता 282,100 घन मीटर आंकी गई थी।* एमओईएफसीसी ने पर्यावरणीय मंजूरी का विस्तार करते हुए, परियोजना को एक त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (आरईआईए) विकसित करने और मलबा डंपिंग जरूरतों का पुनर्मूल्यांकन शामिल करने के लिए ईएमपी को अद्यतन करने की सलाह दी[3]। अद्यतन, अधिक विस्तृत पोस्ट–डीपीआर डिजाइन के आधार पर, और परियोजना के विभिन्न घटकों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए (टीबीएम का उपयोग करते हुए एचआरटी उत्खनन सहित), वीपीएचईपी द्वारा उत्पन्न होने वाले मलबे की कुल मात्रा लगभग 4 मिलियन घन मीटर होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें से 3.12 मिलियन मिलियन घन मीटर को डंप यार्डों में डंप किया जाना है, जिसमें हाट निपटान स्थल की अनुमानित क्षमता 1.27 मिलियन मिलियन घन मीटर है। 2021 पर्यावरणीय मंजूरी चार गज की दूरी पर डाली जाने वाली कुल राशि की पुन: पुष्टि करता है। ***अनुरोधकर्ताओं का यह आरोप कि मंदिर को मलबा डंपिंग से खतरा है, मंदिर के आसपास होने वाली परियोजना गतिविधियों की गलतफहमी से उपजा है। मलबा मंदिर के पीछे या उसके आस–पास नहीं डाला जा रहा है। अनुरोध में मंदिर के पीछे गलतफहमी में "मलबा डंपिंग" के रूप में पहचान की गई सामग्री वास्तव में मंदिर के पीछे ढलान को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है, जो टीबीएम के स्थल तक पहुंच मार्ग का समर्थन करती है। इस ढलान से मंदिर को किसी भी फिसलन से बचाने के लिए गेबियन दीवार का निर्माण किया गया है। वर्षा का कोई भी अपवाह पहुंच मार्ग के साथ पास के प्राकृतिक जल निकासी में बहता है।*** ***इसके अलावा, गैबियन दीवार के साथ नालियां बनाई गई हैं जो वर्षा जल के रिसाव के कारण उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी संभावित हाइड्रोस्टेटिक दबाव को कम कर रही हैं।***

[3] ईएमपी को आरईआईए के एक भाग के रूप में अद्यतन किया गया था।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		यहां पहले से ही वनस्पतियां बढ़ने लगी हैं और क्षेत्र को आच्छादित करना शुरू कर दी हैं, जो वहां होने वाले मलबा डंपिंग के दावे को खारिज करता है। दोनों पहुंच मार्ग उपयोग में हैं, जो यदि विशेष रूप से निचली सड़क मलबा डाला जा रहा हो, तो संभव नहीं होगा। प्रबंधन विशेष रूप से निम्नलिखित नोट करता है : • ***टीएचडीसी ने पुष्टि की कि लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवार के पीछे कोई मलबा नहीं डाला जाएगा।*** • मंदिर के पीछे गेबियन दीवार लगभग 100 मीटर लंबी और आधार पर 9 मीटर मोटी (ऊंचाई के साथ परिवर्तनीय) है। इस गेबियन दीवार को शॉटक्रीट की 100 मिमी की परत के साथ और मजबूत किया गया है, जिससे यह देखने में भी बेहतर हुई है। यह दीवार गंदगी को रोकने के लिए सहारा दीवार के रूप में काम नहीं करती है, न ही यह कभी इरादा था। इस दीवार में किसी तरह का कोई मलबा, या कोई अन्य मलबा नहीं रखा जा रहा है, या इसके पास ढेर नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए, यह चिंता कि यह दीवार इतनी मजबूत नहीं होगी कि डंप किए गए मलबे को रोक सके, अप्रासंगिक है क्योंकि ऐसा न तो हो रहा है और न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है। यह गलतफहमी मलबा डंपिंग के संबंध में अनुरोधकर्ताओं के आरोप के जवाब में एएसआई के 2022 के नोट में भी दिखाई देती है[4]। • लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर (लक्ष्मी नारायण मंदिर से चंडिका माता मंदिर तक) के निर्माण के बाद की पूरी लैंडस्केपिंग योजना को ग्रामीणों के साथ साझा किया गया और चर्चा की गई (अनुलग्नक 2 देखें)। • चंडिका माता मंदिर तक की शेष दूरी के लिए, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) की रिटेनिंग वॉल प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य मंदिर परिसर को ढलान के किसी भी फिसलन से बचाना है। • दीवारों के पीछे के ढलान मुक्त जल निकासी हैं। किसी भी हाइड्रोस्टेटिक दबाव को छोड़ने के लिए 1 मीटर की दूरी पर ड्रेन पाइप लगाए गए हैं। 50 सेंटीमीटर व्यास वाली नालियां बारिश के पानी के साथ–साथ नाली के पानी को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने और निस्तारण के लिए पूरी दीवार की लंबाई तक जाती हैं। बारिश के दौरान सतह का अपवाह पहुंच मार्ग के साथ पास के प्राकृतिक नाले में बहता है, जो खड़े पानी के कारण किसी भी रिसाव को सीमित करता है। इसके अलावा, टीएचडीसी की योजना निकटवर्ती प्राकृतिक नाले तक पहुंच मार्ग के साथ–साथ अतिरिक्त नालियों का निर्माण करने और इस खंड पर वृक्षारोपण करने की है।

4 4हटगाँव (गाँव हाट) पीपल कोटी, जिला चमोली में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निरीक्षण नोट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) 04 अप्रैल, 2022 (अनुरोध के लिए दूसरा संलग्नक)।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		• भविष्य के परिसर की भूनिर्माण योजना में मंदिर परिसर को ढलान से बचाने के लिए सभी तरफ अतिरिक्त रिटेनिंग दीवारें शामिल होंगी।[5]
6ण	**2022 में वैज्ञानिक द्वारा मलबा डंपिंग के लिए वैकल्पिक साइट की पहचान की गई** चूंकि टीएचडीसीआईएल कंपनी ने ग्रामीणों की चिंताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और विकल्प की तलाश किए बिना ग्राम हाट के साइट और विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मलबा फेंकना जारी रखा है, इसलिए ग्राम सभा हाट ने मामले मे अपनी पहल कीं। इसने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित भूविज्ञानी पीआरएल अहमदाबाद के पूर्व वैज्ञानिक, डॉ. नवीन जुयाल, जो पिछले 40 वर्षों से हिमालयी इलाके में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, को उनके सहयोगी प्रो. वाईपी सुंद्रियाल, जो वर्तमान में गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के प्रमुख हैं, के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए आमंत्रित किया। इन विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने एक वैकल्पिक स्थल की पहचान की जो न केवल बहुत स्थिर था, जो 10,000 साल पुराने चट्टान निर्माण पर था, बल्कि निर्जन और असिंचित भी था। उनकी रिपोर्ट बताती है कि यह साइट नदी के बाएं किनारे के करीब भी थी और ट्रॉलियों के माध्यम से मलबे को ले जाया जा सकता था। हमारे प्राचीन ऐतिहासिक गाँव के अस्तित्व को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक वैकल्पिक मलबा डंप साइट पर विचार करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। **2014 – मलबा डंपिंग के लिए वैकल्पिक साइट** इसका रिपोर्ट में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है, हालांकि पेज 72, बिंदु 265 में यह उल्लेख किया गया है कि नीति का हवाला देते हुए कि, 'जहां संभव हो, या कम से कम, सभी वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों की खोज से बचा जाना चाहिए', विश्व बैंक की नीति इस बात का समर्थन करती है कि अनैच्छिक पुनर्वास से बचा जाना चाहिए। टीएचडीसीआईएल कंपनी ठीक यही काम करने में विफल रही। और हाट के हताश ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके अपने दम पर ऐसा करने का बीड़ा उठाया।	***प्रबंधन ने अनुरोध से जुड़े पेपर ("हट गांव में एडिट टनल से मलबा डंप करने के लिए वैकल्पिक स्थान के लिए सुझाव") की समीक्षा की है। एक सामान्य टिप्पणी के रूप में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेपर गलत धारणा पर आधारित है कि मलबा डाला जाता है और "[---] मंदिर के ऊपर" जमा किया जाता है। चूंकि यह मामला ही नहीं है, इसलिए पेपर के तर्क और निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं।*** ***इसके अलावा, पेपर तकनीकी, पर्यावरण, सामाजिक, सुरक्षा और वित्तीय व्यवहार्यता मानदंडों के संबंध में कूड़ा डंपिंग विकल्पों का व्यापक विश्लेषण प्रदान नहीं करता है। प्रबंधन के विचार में, पेपर द्वारा सुझाया गया कचरा डंपिंग समाधान बहुत अधिक पर्यावरणीय जोखिम पेश करता है, जैसा कि नीचे और अधिक विस्तार से बताया गया है।*** **हाट में मलबा डंपिंग साइट :** टीएचडीसी द्वारा किए गए विकल्पों के पहले के विश्लेषण में मलबा डंपिंग साइटों का चयन करते समय तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, सुरक्षा और वित्तीय सहित मानदंडों के एक सेट पर विचार किया गया था। डंप साइटों के चयन में विशेष रूप से, निम्न को ध्यान में रखा गया : भूविज्ञान, भू–तकनीकी पहलू, स्थलाकृति, भूकंपीयता, नदी प्रणाली, पुरातत्व, पेशेवर और सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, वित्तीय व्यवहार्यता आदि। मलबा डंपिंग साइटों के स्थान को अंतिम रूप देते समय, सुरक्षा और पर्यावरणीय कारकों के बारे में अत्यंत सावधानी बरती गई, जिसमें लंबी दूरी तक मलबा ढोने के परिणामस्वरूप होने वाले छलकाव एवं वायु गुणवत्ता में गिरावट से हो सकने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए मलबा परिवहन के लिए अधिकतम दूरी तय करना शामिल है। ***इसके अलावा, परियोजना के ईआईए और ईएमपी में आधार और ढलान संरक्षण के उचित डिजाइन के साथ मलबा प्रबंधन के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग योजनाएं शामिल हैं।*** *टीएचडीसी ने खुदाई, निपटान, भंडारण और बाद में हाट गांव सहित नामित निपटान क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत पद्धति और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किया है। इसके अलावा, टीएचडीसी ने मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्वास के लिए योजनाएं विकसित की हैं, और जैसा कि पहले बताया गया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुनर्वास और संरक्षण पर एएसआई के साथ चर्चा चल रही है।* ***पेपर में प्रस्तुत प्रस्तावित वैकल्पिक डंपिंग साइट का विश्लेषण।*** *पेपर अलकनंदा के बाएं किनारे पर एक वैकल्पिक साइट का सुझाव देता है और ट्रॉलियों द्वारा मलबे के परिवहन का प्रस्ताव करता है। टीएचडीसी द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण के विपरीत,* रिपोर्ट तकनीकी, पर्यावरण, सामाजिक, सुरक्षा और वित्तीय व्यवहार्यता मानदंडों के संबंध में मलबा डंपिंग विकल्पों का व्यापक विश्लेषण प्रदान नहीं करती है।

5 5चंडिका माता मंदिर के समीप एक छोटा सा शिव मंदिर है। ये सभी छोटे मंदिर मंदिर परिसर में आते हैं।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		पेपर में प्रस्तावित वैकल्पिक साइट के संबंध में विशेष रूप से, निम्नलिखित टिप्पणियां की जा सकती हैं: • हाट स्थल पर जमा किया जाने वाला अधिकांश मलबा पास के टीबीएम ऑपरेशन से आना है। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद टीबीएम में निर्बाध सुरंग उत्खनन शामिल होगा, जिसके लिए लगातार उपलब्ध मलवा डंपिंग की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित साइट के लिए सड़क पहुंच की आवश्यकता होगी, जिससे पर्याप्त अतिरिक्त लागत आएगी और परियोजना के पर्यावरण और सामाजिक पदचिह्न में वृद्धि होगी। • ईसी और आरईआईए के अनुसार, हाट में जमा किए जाने वाले मलवे की कुल मात्रा लगभग 1.27 मिलियन घन मीटर है। यह स्पष्ट है कि, परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रॉलियों के आकार के आधार पर, दैनिक आधार पर एचआरटी उत्खनन द्वारा उत्पादित मलबे की मात्रा को समय पर और सुरक्षित तरीके से परिवहन करना तकनीकी और पर्यावरणीय रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। • निम्नलिखित पर्यावरण और सुरक्षा पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है : i. मलबे को अलकनंदा के पार ले जाना पड़ता है, जिससे गलती से नदी में गिरने का खतरा बढ़ जाता है; ii. इसके अलावा, टीबीएम ऑपरेशन द्वारा उत्पादित मलबा घोल के रूप में होगा, जिससे ट्रॉलियों से संभावित रिसाव के कारण रोपवे का उपयोग करके परिवहन करना अधिक जटिल हो जाएगा। बाएं किनारे पर स्लरी ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण/स्थापना के अपने पर्यावरण और तकनीकी सरोकार होंगे। भले ही हाट में स्लरी ट्रीटमेंट प्लांट दाहिने किनारे पर बना रहे, फिर भी उपचारित कीचड़ को दूसरी तरफ ले जाने की आवश्यकता होगी, और छलकने का जोखिम बना रहेगा। iii. प्रस्तावित स्थल सुरंग के मुहाने से 200 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है (हवाई से मापा जाता है)। लंबवत रूप से, इसे डंपिंग (रिपोर्ट का चित्र 1) के लिए 50 मीटर से अधिक की दूरी तय करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी परिवहन के लिए अपनी तकनीकी बाधाएँ हैं। • हाट में वर्तमान मलबा निपटान स्थल अलकनंदा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर से काफी ऊपर है, जिसका अर्थ है कि मलबा नदी में गिरने या बाढ़ के प्रवाह के मामले में बह जाने की संभावना मामूली है। वैकल्पिक स्थान पर मलवा जमा करने से पर्यावरण को बहुत अधिक जोखिम होगा। रिपोर्ट के चित्र 1 के अनुसार, वैकल्पिक रूप से रिटेनिंग वॉल का आधार साइट वर्तमान साइट की तुलना में ऊंचाई में कम से कम 20 मीटर कम है, जिससे यह संकीर्ण घाट मे बाढ़ के प्रवाह के जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		किसी भी मामले में, पेपर में सुझाया गया क्षेत्र नदी के ठीक ऊपर स्थित है, जिसमें डंपिंग क्षेत्र की नींव/सुरक्षा के क्षरण की उच्च संभावना है, जिससे यह नदी में गिरने वाले मलबे के जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ***इस प्रकार, उपर्युक्त रिपोर्ट में उल्लिखित वैकल्पिक साइट में वर्तमान साइट की तुलना में बहुत अधिक पर्यावरणीय जोखिम हैं, जिसे टीएचडीसी द्वारा विस्तृत मूल्यांकन के बाद चुना गया था।*** **पृष्ठभूमि, शमन उपाय और वर्तमान स्थिति :** 2021 के आरईआईए में विकल्पों पर एक अध्याय है, जो इंगित करता है कि शुरुआत में पांच डंपिंग साइटों पर विचार किया गया था। हालाँकि, केवल चार को अंतिम रूप से चुना गया था, अर्थात् (i) हाट; (ii) सियासैन; (iii) जैसल; और (iv) गुलाबकोटि। मैना नदी के स्थल को नीचे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर आगे के विचार से बाहर रखा गया था। जैसा कि परियोजना के लिए मलवा प्रबंधन योजना (2021 आरईआईए का हिस्सा) में संकेत दिया गया है, चार नामित मलवा डंपिंग साइटों को कई मानदंडों के आधार पर पहचाना गया था, जिनमें शामिल हैंरू परिदृश्य; लागत प्रभावशीलता; पीढ़ी के स्रोत से निकटता; भूजल/सतही जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव; राहत; वनीकरण का दायरा; कटाव नियंत्रण/तलछट गिरफ्तारी; और सामाजिक प्रभाव। योजना मलवा निपटान के लिए परिवहन के साधनों की पहचान करती है; प्रत्येक साइट पर कार्यान्वयन के लिए मलवा निपटान विकल्प; वनस्पति, और भूनिर्माण उपायों के लिए प्रजातियों का चयन। मूल परियोजना डिजाइन के लिए पूरे हाट गांव की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, टीएचडीसी के साथ परामर्श के दौरान, हाट समुदाय ने या तो बिजलीघर को हाट से कम से कम एक किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने या पूरे गांव को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। चूंकि भूवैज्ञानिक कारणों से बिजलीघर को स्थानांतरित करना संभव नहीं था, इसलिए 2010 में पूर्ण पुनर्वास पर सहमति हुई, जिसमें समुदाय ने नदी के बाएं किनारे पर अपनी भूमि पर स्वयं को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। इस समझौते के बाद 2011 में टीएचडीसी द्वारा हाट गांव की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। हाट गांव में निपटाए गए मलवे के अलग–अलग रूप होंगे, जिसमें बोल्डर, बजरी, पिसी रेत और गारा शामिल है। **निरीक्षण पैनल की टिप्पणियां और स्थापनाएं, 20 अप्रैल, 2022:** **ऊपर आइटम 5 में पैनल की टिप्पणियों के पहले तीन बुलेट देखें।**
7ए	**ओपी 4-12 अस्वैच्छिक पुनर्वास–** *टीएचडीसीआईएल के संचालन का तरीका भी आजीविका के मामले में और समुदायों को स्थानांतरित करने से बचने के मामले में इस नीति का सीधा उल्लंघन है। उपलब्ध वैकल्पिक मलबा डंपिंग साइट के आलोक में, (ए)*	***ओपी 4.12 के अनुपालन में पुनर्वास प्रक्रिया की योजना बनाई और संचालित की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परामर्श के दौरान समुदाय द्वारा की बई मांग पर पूरे हाट गांव का अधिग्रहण किया गया था। समुदाय ने पहले से ही नदी के पार अपने स्वामित्व भूमि पर स्व–स्थानांतरण का विकल्प भी चुना। प्रबंधन नोट करता है कि समुदाय के सदस्यों के साथ सामूहिक और व्यक्तिगत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे,***

	[विस्थापन से बचने/न्यूनतम करने का नीतिगत उद्देश्य] यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।	***और यह कि टीएचडीसी द्वारा दी जाने वाली मुआवजा दरें बाजार दरों से काफी अधिक थीं। हालांकि, हाट के 6 परिवारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए और अब तक मुआवजे की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। टीएचडीसी ने उनका मुआवजा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) के कार्यालय में जमा कर दिया है, जहां से वे इसे किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं।***
		पृष्ठभूमि, शमन के उपाय और वर्तमान स्थिति :
		आरएपी और पुनर्वास कार्य योजना सहित परियोजना के तहत उपयोग किए गए पुनर्वास उपकरण प्रभावित समुदायों और स्थानीय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर विकसित किए गए थे। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आरएपी को एक स्थानीय उत्तराखंड एनजीओ द्वारा लागू किया गया था। इन उपकरणों की समीक्षा की गई और बैंक द्वारा मंजूरी दे दी गई।
		पेश किए गए पुनर्वास पैकेज में मौद्रिक मुआवजा और आजीविका पुनर्वास उपाय शामिल थे। यह पैकेज व्यापक विचार–विमर्श के बाद तय किया गया था और भूमि के लिए भुगतान किया गया मुआवजा प्रचलित दरों (सरकार द्वारा स्थापित दरों से तीन से चार गुना) से बहुत अधिक था। पुनर्वास पैकेज में पीएपी के साथ स्व–पुनर्वास भत्ता, गृह निर्माण अनुदान, पुनर्वास भत्ता, निर्वाह अनुदान, स्थानांतरण अनुदान, मवेशी शेड अनुदान और संपत्ति के नुकसान के लिए 10 लाख रुपये का एक विशेष पैकेज (लगभग 12,520 डॉलर) जैसे कई मद शामिल थे। टीएचडीसी ने 10 साल की अवधि के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली का भुगतान करने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा, कमजोर समूहों के साथ–साथ परियोजना के कारण बेघर हुए व्यक्तियों की जरूरतों के अनुरूप विशेष प्रावधानों को बनाया गया था।
		टीएचडीसी ने निम्नानुसार दो क्षतिपूर्ति विकल्पों की पेशकश की :
		• सर्किल रेट पर मुआवजा[6] और 58,400 रुपये से 290,000 रुपये तक के विभिन्न अनुदान और भत्ते प्रभाव की डिग्री के आधार पर थे। इस विकल्प के तहत, घर के मुखिया के अलावा, सभी वयस्क बेटों को वैवाहिक स्थिति देखे बिना अलग परिवार माना जाता था, जिससे लाभ कई गुना बढ़ जाता था; और • सभी आर एंड आर सहायता सहित 100,000 रुपये प्रति नाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) की दर पर सहमति हुई।
		टीएचडीसी ने प्रत्येक परिवार के लिए दोनों विकल्पों के तहत अर्जित होने वाले मुआवजे की गणना की और इस जानकारी को साझा किया ताकि परिवार को सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके।
		टीएचडीसी ने भूमिहीन परिवारों को 150,000 रुपये का भुगतान भी किया ताकि वे अपने घर के लिए जमीन खरीद सकें।
		हाट समुदाय के प्रतिनिधियों ने पुनर्वास के लिए एक पैकेज और प्रक्रिया पर टीएचडीसी के साथ चर्चा की और सहमति व्यक्त की। हाट प्रतिनिधियों ने टीएचडीसी के साथ 2009 में जिला प्रशासन की उपस्थिति में एक सामूहिक

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद व्यक्तिगत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए : • 134 परिवारों ने व्यक्तिगत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। • 6 परिवारों ने एमओयू साइन नहीं किया। 2011 में भूमि अधिग्रहण के बाद भी ये परिवार हाट गांव में ही रह रहे थे। इन छह परिवारों को मुआवजा दिया गया था, जो जिला भू–प्रशासन के पास है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा लिया नहीं गया है। समुदाय के साथ समझौते के बाद, 2011 में ओपी 4.12 के अनुरू॰ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (हालांकि प्रख्यात डोमेन) के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया। **निरीक्षण पैनल की टिप्पणियां और स्थापनाएं, 20 अप्रैल, 2022:** 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण की अपनी सूचना में, पैनल ने कहा कि "2014 की जांच में गांव के पुनर्वास, आजीविका की बहाली और आजीविका पुनर्वास पैकेज के मुद्दों को संबोधित किया गया था।" पैनल ने गाँव के अधिग्रहण की स्थितियों के बारे में अपनी समझ, "प्रतिष्ठित डोमेन के माध्यम से अधिग्रहीत" के साथ–साथ समुदाय के स्व–स्थानांतरण के विकल्प के बारे में अपनी समझ जैसे कि "जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 92 प्रतिशत परिवार [हाट] गांव ने अलकनंदा नदी के दूसरी ओर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया" का भी संकेत दिया।
8[ण]	**दिनांक 22-9-21 को हाट के 16 घरों की बलपूर्वक बेदखली एवं ढहाना** 22.09.2021 को, सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, टीएचडीसीएल ने 200 से अधिक पुलिस कर्मियों, 2 पोकलैन उत्खननकर्ताओं और 1 बुलडोजर के साथ जबरदस्ती ग्रामीणों के घरों में घुसकर सामान/सामान बाहर फेंक दिया और उनके घरों को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये वे ग्रामीण थे जिन्होंने कोई मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था और जिन्होंने पुनर्वास करने से इनकार कर दिया था। बेदखली क्रूर और भारी–भरकम तरीके से की गई थी। प्राचीन विरासत में प्राप्त देवी–देवताओं के घरों में पूजा स्थल, मंदिर, गौशालाएं, रास्ते और ग्राम हाट के बिजली के तार भी नष्ट हो गए, जिससे ग्रामीण बेघर, आश्रयहीन, असहाय और अपनी आजीविका गतिविधियों से रहित हो गए।	***हाट गांव को ओपी 4-12 को लागू करते हुए 2011 में प्रतिष्ठित डोमेन के तहत अधिग्रहित किया गया था। हालांकि पूरे गांव का अधिग्रहण मूल रूप से परियोजना के लिए आवश्यक नहीं था, इसे समुदाय के अनुरोध पर अधिग्रहित किया गया था, जो संयुक्त रूप से स्थानांतरित करना चाहते थे। स्थानांतरण हुआ; सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और बाजार दरों से काफी अधिक मुआवजे का भुगतान किया गया।*** ***हालांकि, हाट के छह परिवारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए और अब तक मुआवजे की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। इमारतों को खाली करने और आत्मसमर्पण करने के लिए दस वर्षों की अवधि में पर्याप्त नोटिस प्राप्त करने के बाद, अंततः राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, स्थानीय पुलिस के समर्थन से भवनों को सुरक्षित किया जाना था।*** ***3 घरों के निवासी जो अभी भी बसे हुए हैं, उन्हें टीएचडीसी द्वारा वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया था। सभी घरों का सामान एकत्र किया गया और सूची बनाई गई और मालिकों द्वारा उठाए जाने के लिए सुरक्षित रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुरोध गलत आधार पर तर्क दे रहा है कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए लागू किया जा रहा प्रतिष्ठित डोमेन प्रभावित पक्ष द्वारा प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करले पर उलट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, और***

[6] यह भूमि और संपत्ति कर निर्धारण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर है। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की गणना के लिए उसी दर का उपयोग किया जाता है।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		11 साल पहले मुआवजा ले लेने और स्थानांतरित होने से इनकार करने के बाद भूमि का अधिग्रहण किया गया था।
		पृष्ठभूमि, शमन उपाय और वर्तमान स्थिति :
		समुदाय के साथ एक समझौते के बाद, 2011 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (प्रतिष्ठित डोमेन के माध्यम से) के तहत ओपी 4-12 के अनुरूप भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2015 तक, हाट के अधिकांश निवासी गाँव से बाहर चले गए थे, जैसा कि सहमति हुई थी। विस्तार से :
		• वीपीएचईपी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी स्वामित्व वाली 31-62 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के बाद 148 परिवार विस्थापित हुए।
		• इनमें से 148 में से 140 परिवार हाट गांव के हैं; शेष 8 में जैसल के 5 और बतूला के 3 शामिल हैं।
		• इन 140 हाट परिवारों में से 134 बाहर चले गए हैं।
		• इन 134 परिवारों में से :
		A) हाट के 127 पुनर्वासित परिवारों को पूरा बकाया मुआवजा मिल गया है और वे नए घरों में चले गए हैं।
		B) 7 परिवारों ने एसएलएओ मुआवजा स्वीकार कर लिया है। ये 7 परिवार हाट गांव से बाहर भी चले गए हैं लेकिन उन्होंने टीएचडीसी से आर एंड आर सहायता नहीं ली है। पेश किया गया आरएंडआर पैकेज अभी भी टीएचडीसी के पास है और पीएपी द्वारा किसी भी समय इसका दावा किया जा सकता है।
		• 6 परिवारों ने अभी तक टीएचडीसी द्वारा अधिग्रहित अपने घरों और जमीनों का मुआवजा स्वीकार नहीं किया है। 2011 से टीएचडीसी द्वारा एसएलएओ के पास देय सभी मुआवजा राशि जमा कर दी गई है।
		हाट में बचे छह परिवारों के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया :
		• 2015 से 2021 तक, टीएचडीसी ने सभी छह परिवारों को पांच अलग–अलग नोटिस जारी किए और साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया कि वे अपना मुआवजा वसूल करें और घर खाली कर दें।
		• फरवरी 2015, सितंबर 2015, मार्च 2019, जुलाई 2021 और अगस्त 2021 में पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए थे।
		• अगस्त 2021 में अंतिम नोटिस और सितंबर 2021 में स्थानीय समाचार पत्र में जारी अतिरिक्त सार्वजनिक नोटिस में बताया गया था कि ढांचों को तोड़ना आसन्न था।
		• जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त अग्रिम सूचना दिए जाने के बाद ढांचों का विध्वंस किया गया था। केवल तीन निवासियों के पास हाट के बाहर वैकल्पिक आवास नहीं था;

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		टीएचडीसी ने उनके लिए विशेष प्रावधान किए : A) xxxxxxxका घर पूरा होने वाला है। टीएचडीसी ने उनका 11,000 रुपये प्रति माह का किराया भत्ता 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। B) xxxx ने अपनी उम्र और विकलांगता को देखते हुए टीएचडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रहने की इच्छा जताई है। टीएचडीसी उनकी मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है और अपने कर्मचारियों को दैनिक सहायता के लिए उनके आवास का नियमित दौरा करने का जिम्मा सौंप दिया है। C) एक तीसरा पीएपी, xxxxx , किराए के मकान में रह रहा है। उन्होंने हाल ही में टीएचडीसी से छह महीने के लिए अपने किराए की राशि का भुगतान करने पर विचार करने के लिए कहा है ताकि xxxxxएक बार मुआवजा मिल जाने पर वह मकान बना सकें। यह अनुरोध प्रक्रियाधीन है। • उन सभी निवासियों के सामान, जिनकी संरचनाओं को हटा दिया गया था, को सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और सुरक्षित रखने के लिए टीएचडीसी को सौंप दिया गया था। टीएचडीसी ने सभी गृहस्वामियों को नोटिस भेजा है कि वे अपना सामान एकत्र कर लें। आज तक, दो को छोड़कर सभी परिवारों ने अपना सामान एकत्र कर लिया है।
9[ण]	एक विधवा, जिसका घर तोड़ा जा रहा था, सहित कुछ प्रदर्शनकारियों को थाने में बंद कर दिया गया और शाम को ही उसे मुख्य सड़क पर छोड़ दिया गया। उनका इकलौता बेटा जो सेना में काम करता है, अपने देश की सेवा करने के लिए घर से दूर था। कुछ मामलों में जहां मालिक अनुपस्थित थे, उनके घर पर सभी फर्नीचर और सामानों के साथ बुलडोजर चला दिया गया। रिपोर्ट है कि दूध बेचने से लेकर उसके बिस्तर के नीचे तक जमा उसकी सारी बचत खत्म हो गई।	***प्रबंधन ने टीएचडीसी से एक विधवा को कथित रूप से बंधक बनाने के संबंध में जानकारी मांगी। टीएचडीसी को इस विधवा के "पुलिस द्वारा बंद" किए जाने की जानकारी नहीं है। टीएचडीसी ने बैंक को सूचित किया कि उसने इस विधवा के लिए आवास की व्यवस्था की थी, लेकिन वह ग्राम प्रधान (ग्राम प्रधान) के घर पर रहना पसंद करती थी। टीएचडीसी उसके लिए एक गौशाला (पहले से ही पूर्ण) के साथ प्रतिस्थापन घर (30 सितंबर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद) का निर्माण कर रहा है। टीएचडीसी द्वारा उन्हें छह महीने के किराए का भुगतान किया गया है।*** मकानों को गिराने से पहले मालिकों के सामान को सुरक्षित, सूचीबद्ध और जमा किया गया था। उन्हें मालिकों द्वारा उनके संग्रह के लिए सुरक्षित रखा गया था। प्रबंधन नोट करता है कि इन छह परिवारों को पिछले 10 वर्षों में भवनों को खाली करने के लिए पर्याप्त नोटिस प्राप्त हुए हैं।
10[ण]	**पुनर्वास से पहले की तुलना में बदतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति में ग्रामीण** हाट के लगभग 99% परिवारों ने बहुत दृढ़ता से दोहराया है कि मुआवजे के पैकेज के बावजूद पुनर्वास के बाद न केवल सामाजिक कल्याण और सुरक्षा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी उनकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब है। अधिक सटीक रूप से पता लगाने के लिए कि किस तरह से, किस आधार पर, और क्यों ग्रामीणों को लगा कि वे इससे पहले से भी बदतर हैं, 20 प्रश्नों के साथ एक सर्वेक्षण पत्रक जारी किए गए (सभी भरे हुए 92 पत्रक के साथ अंग्रेजी में नमूना संलग्न है)।	***प्रबंधन नोट करता है कि अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक और पद्धतिगत कठोरता का अभाव है क्योंकि यह पूरी तरह से स्व–घोषणा पर आधारित है। किसी भी प्रतिक्रिया को सत्यापित नहीं किया गया है या साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। जिस तरह से प्रश्नावली को संरचित किया गया है, वह एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि समुदाय अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से टीएचडीसी पर निर्भर है। इस प्रकार, सर्वेक्षण प्रेरक बनावट और आय को उत्तरोत्तर कम बताने के मुद्दे जैसे सुज्ञात पद्धति संबंधी चुनौतियों के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है*****

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
	कुल मिलाकर लगभग 142 में से 92 परिवार इसे भरने के लिए सहमत हुए। 4 परिवार (सहित), जिन्होंने कोई मुआवज़ा लेने से मना कर दिया था और सितंबर 2021 में जिनके घर ज़बरदस्ती तोड़ दिए गए, उन्होंने पत्रक नहीं भरा. जिन 30–32 परिवारों के पारिवारिक व्यक्ति टीएचडीसीआईएल में स्थायी या अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, उन्होंने दबाव महसूस किया और इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अन्य 8–10 परिवार जो वर्तमान में गांव से दूर रह रहे हैं, उन्हें अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। इन परिपत्रों के आंकड़ों से जो मुख्य तथ्य सामने आते हैं, वे हैं – **केवल 1 व्यक्ति ने कहा कि वे पहले से बेहतर स्थिति में हैं,** बाकी सभी 91 परिवारों ने कहा कि वे पहले से भी बदतर स्थिति में हैं। उन्होंने जो कारण दिए, वे थे : 'टीएचडीसीआईएल में नौकरियों, जिस पर बिना यह जाने कि क्या हमें अगले दिन हटा दिया जाएगा, वे पूरी तरह से निर्भर हैं, की अस्थायी प्रकृति के कारण तनाव से कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता भी पैदा हो रही है। गांव का सामाजिक–सांस्कृतिक ताना–बाना तहस–नहस हो गया है। हम अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सामाजिक रूप से कमजोर हो गए हैं। पहले हम एक परिवार की तरह थे लेकिन अब नहीं हैं। विस्थापित क्षेत्र में मूलभूत संसाधनों एवं सुविधाओं का अभाव आर्थिक रूप से वंचित। पहले हम गांव में खेती करते थे लेकिन अब हम गाँव के शेष समुदाय से बिखर गए हैं और कट गए हैं। हमारे पास पशुपालन के लिए पानी, लकड़ी और घास थी और हम पहले अपने गांव में संपन्न थे। अब न तो अच्छी जल आपूर्ति और न ही आय का कोई स्थायी स्रोत, इससे हम नष्ट हो गए हैं। अब आर्थिक रूप से हम पूरी तरह टीएचडीसी पर निर्भर हैं। हमने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता खो दी है। विस्थापन से पहले हमारे पास जीविका के और भी कई साधन थे जो अब उपलब्ध नहीं हैं। पहले कम पैसों में हम बेहतर जिंदगी जी रहे थे। हम भूमिहीन हैं और अल्पसंख्यक हैं क्योंकि हम अनुसूचित जनजाति के हैं। परियोजना अधिकारियों द्वारा हमारा शोषण किया गया। विस्थापन के बाद की स्थिति का हमें पहले से अंदाजा नहीं था कि हमारा जीवन इतने गहरे गड्ढे में होगा। हम अब बेबस हैं। कोई नहीं सुन रहा है। हम अपने पूर्वजों की विरासत को खो रहे हैं, ऐसे में बेहतर सामाजिक और आर्थिक जीवन की उम्मीद कैसे की जा सकती है.' 92 साक्षात्कारों में से के पास अस्थायी नौकरियां थीं और – टीएचडीसीआईएल द्वारा नियोजित नहीं किए गए थे।	***इसके अलावा, सर्वेक्षण के परिणाम उन अध्ययनों के परिणामों के बिल्कुल विपरीत हैं जिन्हें परियोजना ने कमीशन किया था, और समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करने में योग्य पेशेवर कर्मचारियों द्वारा किए गए थे।*** ***सर्वेक्षण सही ढंग से नोट करता है कि भूमि अधिग्रहण के बाद कुछ पीएपी के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व कम हो गया है, लेकिन इस तथ्य पर कब्जा नहीं करता है कि अधिग्रहित अधिकांश भूमि कृषि नहीं थी और इसलिए इसकी उत्पादकता कम थी। सर्वेक्षण में उठाई गई टीएचडीसी पर निर्भरता के बारे में चिंता भी गलत है क्योंकि समुदाय ने लगातार टीएचडीसी और परियोजना में नौकरियों की मांग की है। तथ्य यह है कि पुनर्वास कॉलोनियों में निर्मित घरों के औसत आकार में मूल घरों की तुलना में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह भी सर्वेक्षण में शामिल नहीं है। घरों का बढ़ा हुआ आकार सर्वेक्षण में उद्धृत निर्माण की लागत को दर्शाता है।*** **पृष्ठभूमि, शमन उपाय और वर्तमान स्थिति :** नष्ट हुई संपत्ति के लिए पारस्परिक रूप से सहमत मुआवजे के अलावा, परियोजना ने हाट के विस्थापित परिवारों को 10 लाख रुपये (लगभग 12,520 डॉलर) के विशेष अनुदान का भुगतान किया है। टीएचडीसी ने लक्षित समुदायों की सतत आजीविका, समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, परिधीय विकास आदि जैसे क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ संबंधित सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और निजी फर्मों के साथ साझेदारी में कई सामुदायिक विकास गतिविधियां शुरू की हैं। लाभ व्यक्तियों की क्षमता निर्माण से लेकर समुदाय को सहायता प्रदान करने तक होते हैं। परियोजना ने आसपास के समुदाय के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां भी शुरू की हैं। इसमें छात्रवृत्ति प्रदान करना, लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना, ग्रामीण खेल, ग्रामीण चिकित्सा शिविर, परियोजना डिस्पेंसरी तक पहुंच आदि शामिल है। परियोजना ईंधन और चारे के नुकसान को दूर करने के लिए परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर भुगतान भी कर रही है। इसका भुगतान निर्माण अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। एक बार चालू हो जाने के बाद परियोजना शुरू होने की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए प्रति माह प्रत्येक प्रभावित परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। कई अध्ययनों ने स्थानीय समुदायों पर परियोजना के संभावित सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का प्रत्याशित और संभावित मूल्यांकन किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित शमन उपायों का सुझाव दिया है कि परियोजना से पीएपी के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन रिपोर्टों में एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पुनर्वास कार्रवाई योजना शामिल है। टीएचडीसी ने आरएपी, जिसमें आजीविका बहाली के उपाय भी शामिल थे, को लागू करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन की सेवाओं को किराए पर लिया। जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना में भी सामुदायिक विकास के उपाय

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
	28 परिवारों ने कहा कि मुआवजे के पैकेज के रूप में उन्हें जो पैसा मिला है, वह पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए पर्याप्त था। 50 ने कहा कि उन्हें जो राशि मिली है, वह पर्याप्त नहीं है। 10 को मुआवजा नहीं मिला और 4 ने जवाब नहीं दिया। 57 लोगों ने कहा कि पुनर्वास से पहले पशुपालन, बाग और खेती ही उनकी आजीविका थी। 35 ने कहा कि उनके पास रोजगार के अन्य साधन थे। हालांकि भूमि अधिग्रहण के बाद केवल 24 ने पशुपालन, बाग या खेती जारी रखी। 68 ने इन आजीविका के इन साधनों को छोड़ दिया। 69 लोगों के बहुमत ने अपनी पहले की खेती आदि को आजीविका के लिए या कम से कम कुछ आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन के रूप में पाया। 22 ने इसे अपर्याप्त पाया। भूमि अधिग्रहण के बाद 41 ने इसे अपर्याप्त पाया। इसलिए समुदाय की एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है जो अत्यधिक असुरक्षित है और स्थिर आजीविका से वंचित है। न केवल आर्थिक नुकसानों ने उन्हें कमतर आर्थिक स्थिति में ला खडा किया है, बल्कि भूमि, पानी, खेत, बाग, चारे और ईंधन तक पहुंच के नुकसान के माध्यम से स्थायी नुकसान किया है, जो भविष्य के विकास की किसी भी संभावना को प्रभावी रूप से रोकता है। ग्रामीणों ने कहा है कि वे अब पूरी तरह से बाजार की उपज पर निर्भर हैं, जिसके लिए उन्हें नकदी की आवश्यकता होती है, जबकि पहले वे अपनी अधिकांश आवश्यकताओं का उत्पादन करते थे और इसलिए आत्मनिर्भर थे। **हाट के ग्रामीणों की 2014 आजीविका का नुकसान** अनुरोध में हाट की आजीविका नहीं, बल्कि केवल हाटसारी शामिल थी। पेज 69, बिन्दु 255 पर बताया गया है, 'चूंकि हाट गांव में आजीविका के इन मुद्दों को निरीक्षण के अनुरोध में स्पष्ट रूप से नहीं उठाया गया था, इसलिए उन्हें प्रबंधन की प्रतिक्रिया में संबोधित नहीं किया गया है। यह परियोजना–पूर्व आजीविका को बहाल करने के बारे में भी चिंता व्यक्त करता है, जो कि आज ग्रामीण अनुभव कर रहे हैं। पृष्ठ 71, बिन्दु 263 में हाट के बारे में कहा गया है, 'यह एक जोखिम का संकेत देता है कि कमजोर परिवार अपनी परियोजना–पूर्व आजीविका को बहाल करने में सफल नहीं हो सकते हैं।'	शामिल हैं। सत्रांत मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएपी कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 2019 में टीएचडीसी द्वारा कराया गया तृतीय–पक्ष स्वतंत्र अध्ययन) आम तौर पर हाट गांव से विस्थापित परिवारों की बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति पाती है। आधार डेटा सामाजिक प्रभाव आकलन द्वारा प्रदान किया गया था और मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट (2012) और समाप्ति अवधि मूल्यांकन रिपोर्ट (2019) के साथ तुलना की गई थी। आधार डेटा के अनुसार, प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जो समुदाय अभी भी कर रहा हैं। कृषि के बाद सरकारी सेवा और फिर गैर–कृषि श्रम था। इनमें से कोई भी परियोजना के बाद के परिदृश्य में नहीं बदला है। रिपोर्ट में 7 भूमि प्रभावित गांवों में कृषि से प्रति व्यक्ति आय में 37 प्रतिशत, व्यवसाय से 50 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 11 प्रतिशत और श्रम क्षेत्र में 42 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। रिपोर्ट में पाया गया कि एलडाना और दसवाना (पुनर्वास कॉलोनियों) में कृषि से प्रति व्यक्ति आय में 81 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, व्यापार से 50 प्रतिशत की वृद्धि, निजी क्षेत्र के रोजगार में 34 प्रतिशत और श्रम गतिविधियों से 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गौर किया गया कि कृषि से आय प्राप्त करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त वृद्धि, उन्नत कृषि तकनीकों और गैर–सरकारी संगठनों और अधिकारियों के समर्थन के परिणामस्वरूप हुई। *मुआवजा पैकेज :* ऊपर आइटम 7 देखें। *सामुदायिक विकास* परियोजना लाभ–साझाकरण तंत्र का समर्थन करती है, जिसमें स्थानीय विकास निधियों की दो श्रेणियां शामिल हैं। पहले में निर्माण अवधि के दौरान पांच वर्षों में 19 प्रभावित गांवों के लिए उपयोग किए जाने वाले 9 करोड रुपये की समर्पित निधि शामिल है। निवेश योजनाएं समुदायों द्वारा तैयार की जाएंगी। राष्ट्रीय जल नीति द्वारा अनिवार्य, दूसरी श्रेणी की आवश्यकता है कि परियोजना के चालू होने के बाद संयंत्र के लाभ का एक प्रतिशत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित समुदायों सहित व्यापक क्षेत्र में स्थानीय विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध हो। स्थानीय विकास निधि के तहत, मार्च 2022 तक, टीएचडीसी ने अपने स्थानीय लाभ–साझाकरण तंत्र के हिस्से के रूप में सामुदायिक विकास गतिविधियों पर 10.4 करोड़ रुपये व्यय किए थे। इसके अलावा, परियोजना के तहत रोजगार के कई अवसर सृजित होते हैं। उदाहरण के लिए, ठेकेदारों या ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की निगरानी लाभार्थी समुदाय द्वारा की जाती है। इसके अलावा, 200,000 रुपये से

संख्या	छावा	प्रतिक्रिया
		कम लागत वाले मंदिरों के रास्ते, चहारदीवारी और जलापूर्ति कार्यों जैसे छोटे सिविल कार्य के अनुबंध पात्र पीएपी को दिए गए हैं। परियोजना द्वारा नियोजित 551 पीएपी में से, 171 पीएपी को टीएचडीसी ने नियोजित किया है, जिनमें से 18 टीएचडीसी के पेरोल पर और शेष अनुबंध एजेंसियों के माध्यम से नियोजित हैं; एचसीसी ने 218 पीएपी को सीधे और बाकी को वेंडर, किराए पर वाहन लेने, जमीन को पट्टे पर देने, मकान किराए पर देने आदि जैसे अन्य माध्यमों से नियोजित किया है। परियोजना में नियोजित 551 लोगों में से 122 पीएपी हाट से हैं। 122 हाट निवासियों में से 72 टीएचडीसी में और शेष 50 एचसीसी में कार्यरत हैं। चूंकि परियोजना, प्रभावित गांवों में हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती है, इसलिए टीएचडीसी ने क्षेत्र में भूमि आधारित रोजगार के अवसरों को विकसित करने और पीएपी और अन्य समुदाय के सदस्यों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष एजेंसी, मृदा को नियुक्त किया है। इससे परियोजना क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। टीएचडीसी प्रभावित परिवारों को वीपीएचईपी द्वारा बिजली उत्पादन शुरू करने के बाद 10 साल की अवधि के लिए प्रति माह 100 किलो वाट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। टीएचडीसी ने अब तक 3 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है जिससे समुदाय के 175 सदस्य लाभान्वित हुए हैं। टीएचडीसी कॉलोनी की डिस्पेंसरी ने समुदाय के 22,327 सदस्यों का इलाज किया है। इसके अलावा, टीएचडीसी ने आवश्यकता पड़ने पर समुदाय के लिए अपनी एंबुलेंस सेवा का भी विस्तार किया है। 2010 से अब तक 130 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये सभी निःशुल्क हैं और चिकित्सक परामर्श शुल्क, निकटतम स्वास्थ्य सुविधा की यात्रा, दवाओं की लागत आदि के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय का 6,200,000 रुपये से अधिक बचाया है। *आजीविका विकास परियोजनाएं :* 241 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए कुल 104 पायलट कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनमें से 56 हाट से हैं, जो इस प्रकार हैं : - पॉलीहाउस (6 लाभार्थी) : एक ग्रीनहाउस जो कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के साथ उच्च उपज की सुविधा देता है। - डी–हब (30 लाभार्थी) : ऐसा स्थान जहां डिजिटल, ऑनलाइन, बैंकिंग, ई–नागरिक और कौशल विकास सेवाएं हों, जिससे निवासी एक ही स्थान पर सभी सेवाओं का उपयोग कर सकें, पैसे और समय की बचत हो सके। डी–हब डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कौशल विकास और नई डिजिटल तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देता है, और यह कंप्यूटर संचालन सीखने के इच्छुक युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है। - सिलाई और बुनाई (15 लाभार्थी)। - मधुमक्खी पालन (5 लाभार्थी)। *प्रशिक्षण और शिक्षा सहायता :*

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		- व्यावसायिक प्रशिक्षण (हाट से 21 में से 1), औद्योगिक प्रशिक्षुता (हाट से 7 उम्मीदवार), 1400 छात्रों को छात्रवृत्ति। - 2014–2015 में, टीएचडीसी ने होटल प्रबंधन, मोटर मैकेनिक, फिटर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और एक्सकेवेटर ऑपरेटर जैसे क्षेत्रों में 246 युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रायोजित किया। - टीएचडीसी ने कुल 4,773,000 रुपये में 137 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रायोजित किया है। - कार्यान्वयन के लिए समुदाय को 67 छोटे अनुबंध (200,000 रुपये तक) दिए गए हैं। - विधवा पेंशन का लाभ 33 विधवाओं को मिला है। टीएचडीसी ने पुनर्वास कॉलोनियों में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं : - आरसीसी रास्ते; - 79 स्थानांतरित परिवारों के लिए एलदाना और दसवाना को दैनिक आधार पर 64,000 लीटर पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है।[7] इसके अतिरिक्त, मायापुर और डोभी घाट को 40,000 लीटर की आपूर्ति की जाती है, जहां कुछ विस्थापित परिवार बस गए हैं; - सौर स्ट्रीट लाइट्स; - बिजली की आपूर्ति; - विद्यालय भवन; - पंचायत भवन। *ईंधन और चारा पहुंच :* परियोजना ईंधन और चारे के लिए सामुदायिक वन भूमि तक पहुंच के संभावित नुकसान के लिए शमन उपायों को लागू कर रही है; यह मुआवजे के उपाय के रूप में खराब हुए क्षेत्रों में चारा सामग्री और पेड़ों को फिर से लगाने के लिए भी वित्त पोषण कर रहा है। 2012 से, प्रत्येक प्रभावित परिवार को ईंधन और चारे के स्रोतों तक पहुंच के इस नुकसान के लिए नकद वार्षिकी प्रदान की गई है। वार्षिकी 100 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर है और सभी परियोजना प्रभावित गांवों के परिवारों को दी जा रही है। आज तक, टीएचडीसी ने 2,596 परिवारों को 122,786,400 रुपये वितरित किए हैं, जिसमें हाट गांव के 86 परिवार शामिल हैं।[8] यह भत्ता निर्माण अवधि के अंत तक जारी रहेगा। टीएचडीसी प्रभावित व्यक्तियों के लिए वन पंचायत और/या चरागाह भूमि तक पहुंच पथ प्रदान करेगा। पाथवे निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और काम शुरू हो गया है।

[7] बाकी हाट परिवार मायापुर, देहरादून, गोपेश्वर और दिल्ली जैसे अन्य स्थानों पर चले गए हैं, क्योंकि उन सभी के घर हाट के बाहर थे।
[8] जिसमें हटसारी टोला के परिवार भी शामिल हैं।

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		शिकायत निवारण तंत्र में शिकायतों को लाने की क्षमता : वीपीएचईपी शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) 2009 में स्थापित किया गया था और यह कार्यात्मक है क्योंकि शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। जीआरएम के तहत एक स्वतंत्र अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) शामिल है और जो टीएचडीसी के प्रबंधक (सामाजिक) और भूमि प्रभावित गांवों के प्रधान (प्रमुख) द्वारा समर्थित है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के दौरान, जीआरसी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और तब से, कई प्रयासों के बावजूद, कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। भूमि प्रभावित गांवों के जीआरसी सदस्यों ने भी मिलना बंद कर दिया क्योंकि कोई भौतिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, व्यथित व्यक्तियों ने टीएचडीसी कार्यालयों का दौरा करना जारी रखा और शिकायतें लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त होती रहीं और उन्हें टीएचडीसी द्वारा बनाए गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया गया। जीआरएम का प्रबंधन टीएचडीसी स्टाफ (अतिरिक्त महाप्रबंधक, सामाजिक और पर्यावरण; वरिष्ठ प्रबंधक, सामाजिक और सामाजिक संघटक) द्वारा किया जाना जारी है। शिकायतों के समाधान के लिए टीएचडीसी टीम में प्रधान या संबंधित गांव का प्रतिनिधि शामिल होता है। प्राप्त शिकायत टीएचडीसी के नियंत्रण/दायरे से बाहर होने की स्थिति में जिला प्रशासन से संपर्क किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को संकल्प के बारे में या तो पत्र (महामारी के दौरान पसंदीदा तरीका) या व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाता है। स्थापना के बाद से, टीएचडीसी को 330 शिकायतें मिली हैं, जिनमें फरवरी 2021 और जुलाई 2022 के बीच प्राप्त 38 शिकायतें शामिल हैं। नवीनतम शिकायत 26 जुलाई, 2022 को प्राप्त हुई थी। टीएचडीसी भूमि प्रभावित सात गांवों से ग्राम प्रधानों की नियुक्ति कर जीआरसी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। ग्राम प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक सितंबर 2022 के लिए निर्धारित है और जैसे ही ग्राम प्रतिनिधि बोर्ड पर होंगे, जीआरसी अध्यक्ष की स्थिति विज्ञापित की जाएगी। **निरीक्षण पैनल की टिप्पणियां और स्थापनाएं, 20 अप्रैल, 2022:** • जहां अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि "अनुरोध में हाट नहीं, बल्कि केवल हाटसारी की आजीविका शामिल थी", 2014 की जांच रिपोर्ट ने वास्तव में आजीविका के मुद्दे और हाट एवं हाटसारी, दोनों के लिए ओपी/बीपी 4.01 और ओपी/बीपी 4.12 की आवश्यकताओं के साथ बैंक के अनुपालन का आकलन किया था। हाट के लिए, पैनल "हाट पर प्रभाव – *आजीविका* का मुद्दा" खंड *(पैराग्राफ 255)* में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है। *यह विस्तृत आकलन विश्लेषणात्मक खंड "हाटसारी पर प्रभाव – आजीविका का मुद्दा।" (पैराग्राफ 251) से अलग है।*

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		• हाट पर, अपनी 2014 की जांच रिपोर्ट में, "समिति ने टीएचडीसी आर एंड आर नीति के तहत हाट गांव से विस्थापित परिवारों की पुनर्वास आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए परियोजना के तहत उठाए गए पर्याप्त कदमों को नोट किया है।" • इसके अलावा, 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण की सूचना में, पैनल ने कहा कि "2014 की जांच में गांव के पुनर्वास, आजीविका की बहाली और आजीविका पुनर्वास पैकेज के मुद्दों को संबोधित किया गया था।"
1 1।	करीब 70 लोगों ने बताया कि उन्हें रोजाना सिर्फ 0–2 घंटे पानी मिलता है, जबकि 12 लोगों को रोजाना 2–5 घंटे पानी मिलता है। दूसरों के पास अन्य स्रोत थे और वे कहीं और रह रहे थे।	**पानी की आपूर्ति : टीएचडीसी पुनर्वास स्थल की घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रहा है, जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम आपूर्ति से काफी अधिक है। अनुरोध में उठाई गई कथित पानी की कमी पुनर्वास कॉलोनी के अंदर असमान खपत के कारण हुई है। कई परिवारों ने अपने व्यक्तिगत टैंकों में पानी पंप करने के लिए सर्विस डिलीवरी लाइन में टैपिंग पंप स्थापित किए हैं और कुछ रेनफेड सिंचाई को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से अपने घरों के करीब सब्जियों के भूखंडों को पानी देने जैसी सिंचाई गतिविधियों के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने की कोशिश करने के लिए, टीएचडीसी ने हाल ही में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए वितरण पाइपों के व्यास में वृद्धि की है।** **यद्यपियह नीति अनुपालन का मामला नहीं है, प्रबंधन ने सुझाव दिया है कि टीएचडीसी एक समाधान खोजने के लिए समुदाय की सहायता करने की पेशकश करता है जो पुनर्वास कॉलोनी में समान जल वितरण और खपत सुनिश्चित करेगा। हालांकि, पानी के उपयोग से संबंधित अंतर्निहित शासन मुद्दा एक चुनौती बना हुआ है जिसे समुदाय को आंतरिक रूप से, संभवतः एक जल प्रबंधन समिति की स्थापना के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। प्रबंधन ने टीएचडीसी से यह भी कहा है कि अधिक न्यायसंगत खपत स्थापित करने में मदद करने के लिए पूरी पुनर्वास कॉलोनी के लिए पानी की खपत और वितरण को मापने के साधनों पर विचार करें।** पुनर्वास से पहले, हाट गांव के समुदाय अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पास के प्राकृतिक स्रोतों से व्यक्तिगत रूप से पानी लाते थे। पीएपी के मुख्य पुनर्वास कॉलोनियों (एलदाना और दसवाना) में चले जाने के बाद, टीएचडीसी ने सभी घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराया। टीएचडीसी द्वारा स्थापित पंपिंग सुविधा में 24,000 लीटर क्षमता का एक मुख्य टैंक और दो पंप, एलडाना के लिए 10 एचपी का पंप और दसवाना के लिए 12 एचपी का पंप शामिल है। दसवाना में छह–छह हजार लीटर क्षमता के दो टैंक, और एलडाना में 5,000 लीटर क्षमता के चार टैंक हैं। टैंकों की कुल क्षमता 32,000 लीटर है, और पानी को दिन में दो बार पंप किया जाता है, जिससे कुल औसत दो कॉलोनियों में 64,000 लीटर या 810 लीटर/दिन/प्रति घर पानी की आपूर्ति होती है। उत्तराखंड राज्य दिशानिर्देशों के अनुसार,

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में कम से कम 55 लीटर/प्रति व्यक्ति/दिन के प्रावधान की परिकल्पना की जानी चाहिए। टीएचडीसी नियमित रूप से पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता की निगरानी करता है और छह महीने के अंतराल पर टैंकों की सफाई करता है। पिछली बार जून 2022 में निगरानी की गई थी और गुणवत्ता स्वीकार्य पाई गई थी। कई परिवारों ने अपनी निजी पानी की टंकियों को भरने के लिए सर्विस डिलीवरी लाइन में टैपिंग पंप स्थापित किए हैं। अन्य परिवार कृषि सिंचाई के लिए उसी जल आपूर्ति का उपयोग करते हैं। यह पानी के दबाव और उपलब्ध मात्रा को प्रभावित करता है, और इसलिए गांव के सभी घरों में समान पानी की आपूर्ति को प्रभावित करता है, पाइप नेटवर्क के अंतिम छोर पर स्थित घरों पर अधिक बार प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति नेटवर्क को व्यक्तिगत घरेलू जल पंपों के संचालन का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। शिकायतों के जवाब में, टीएचडीसी ने वितरण पाइपों के व्यास को बढ़ाकर अंतिम छोर पर स्थित घरों में पानी की आपूर्ति में वृद्धि की है। प्रबंधन यह भी सुझाव देगा कि टीएचडीसी सभी को समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के भीतर कुछ निगरानी तंत्र को सुगम बनाने का प्रयास करे।
12ए	**बिखरे और अलग–थलग पुनर्वास के माध्यम से हाट गांव के सामाजिक ताने–बाने को तोड़ना** इस प्रकार भले ही शुरुआत में 2009 में तत्कालीन ग्राम प्रधान ने 7–8 ग्रामीणों के साथ कंपनी के साथ किसी तरह का समझौता किया हो, लेकिन आज पूरा गांव अपनी विरासत, सामाजिक समुदाय और परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा है। वास्तव में ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन दबाव में, अपने अधिकारों की अनदेखी और बिना किसी कानूनी सहायता के किए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि जो लोग इस सौदे को स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में कुछ भी नहीं मिलेगा। **2014 – हाट गांव के समुदाय का विनाश** रिपोर्ट में इस मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में यह पेज 70, बिंदु 258 पर बताता है कि ग्रामीणों ने नदी के उस पार अपनी स्वामित्व वाली भूमि को फिर से स्थापित करने के 'अवसर का स्वागत' किया। इस बिखराव के बाद, समुदाय और फटे हुए सामाजिक ताने–बाने का परिणामी नुकसान, जिससे ग्रामीण अब गहराई से प्रभावित और आघातित हैं, पिछले 8 वर्षों में हुए हैं। इसलिए 2014 में इस स्थिति की जांच नहीं की गई। उस समय भी ग्रामीणों को लगा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आज शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि के साथ, और उनकी दुर्दशा का पहला कड़वा अनुभव, और जो कुछ उन्होंने खोया है, उसकी विशालता के साथ, संपूर्ण गांव विरोध में एकजुट हो गया है।	***हाट गांव को 2011 में ओपी 4.10 लागू करते हुए प्रतिष्ठित डोमेन के तहत अधिग्रहित किया गया था। हालांकि परियोजना के लिए मूल रूप से पूरे गांव का अधिग्रहण आवश्यक नहीं था, यह समुदाय के अनुरोध पर किया गया था। स्थानांतरण हुआ; सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और बाजार दरों से काफी अधिक मुआवजे का भुगतान किया गया।*** ***प्रबंधन ने नोट किया कि छह ग्रामीणों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया, जो पुष्टि करता है कि उनके पास यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता थी।*** ***प्रबंधन यह भी नोट करता है कि "सामाजिक ताने–बाने को तोड़ने" के आरोप की जांच नहीं की गई क्योंकि इसे समुदाय द्वारा कभी भी प्रारंभिक परामर्श के दौरान या 2014 के पैनल की जांच के दौरान नहीं उठाया गया था। दरअसल, पूरे हाट गांव ने पुनर्वास का अनुरोध किया था।*** –कृपया अधिक विवरण के लिए ऊपर आइटम 7 देखें। **निरीक्षण पैनल की टिप्पणियां और स्थापनाएं, 20 अप्रैल, 2022 :** 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण की अपनी सूचना में, पैनल ने कहा कि "समुदाय ने अपने चयन के क्षेत्रों में स्व–स्थानांतरण का विकल्प चुना। जांच रिपोर्ट में यह नोट किया गया था, जिसमें पाया गया कि गांव के 92 प्रतिशत परिवारों ने अलकनंदा नदी के दूसरी तरफ स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।[9]"

[9] खंड II "परियोजना पृष्ठभूमि", पृष्ठ 3, प्रबंधन रिपोर्ट और निरीक्षण पैनल जांच रिपोर्ट के जवाब में सिफारिश।

संख्या	छावा	प्रतिक्रिया
	वर्तमान बिगड़ी हुई स्थिति के संबंध में संपूर्ण ग्रामीण समुदाय का दृष्टिकोण। आईपी रिपोर्ट 2014 में कहा गया है कि वह केवल हाटसारी के कुछ लोगों से मिली थी। हाट के ग्रामीणों का दावा है कि उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं किया गया। आज पूरा गांव इस अनुरोध पर, पूरे गांव के एक आधिकारिक संकल्प द्वारा हस्ताक्षर कर रहा है, जैसा कि हमने पहले किया था। साथ ही जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पूरे गांव का संकल्प, उनके मंदिर और गांव की जगह को संरक्षित घोषित करना, एक बिल्कुल नया सबूत और परिस्थितियां हैं, जो सबसे स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पूरा गांव कितना पीड़ित है।	**पृष्ठभूमि, शमन उपाय और वर्तमान स्थिति :** जैसा कि आइटम 6 और 7 में उल्लेख किया गया है, समुदाय ने नदी के बाएं किनारे पर अपनी स्वामित्व वाली भूमि पर स्वयं को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। अधिकांश परिवारों ने नदी के उस पार (हाट से कम से कम 1 किमी) इन आस–पास के गांवों में जाने का विकल्प चुना, जहां उनमें से अधिकांश के पास ज़मीन के स्वामित्व थे, जिसका अर्थ था कि इससे उन्हें अपने सामाजिक ताने–बाने को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन की उपस्थिति में सामूहिक और व्यक्तिगत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। छह परिवारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो यह साबित करता है कि प्रतिबंधों के बिना ऐसा करने का विकल्प था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय के पास पुनर्वास स्थलों पर सांप्रदायिक संपत्ति बनी रहे और उनके सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखा जाए, टीएचडीसी ने सामान्य संपत्ति संसाधनों जैसे ग्राम पंचायत भवन, एक प्राथमिक विद्यालय भवन, रास्ते आदि का निर्माण किया, और घरों को बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रदान की।
13[ए]	**ओपी 4.36, बांधों की सुरक्षा** जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं के बढ़ते खतरों और चरम मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़, उच्च और केंद्रित वर्षा, अचानक बाढ़ आदि का हिसाब नहीं दिया गया है। हाल ही में हाट गांव के पास चमोली (2021) में हुई मानवीय त्रासदी ने दिखाया है कि पूरा क्षेत्र कितना संवेदनशील है। एचईपी सुरक्षित नहीं हैं। नीचे दिए गए बिंदु 12 में विस्तार से बताया गया है कि कैसे विशेषज्ञ अध्ययन अब एचईपी के निर्माण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, न केवल इसमें शामिल मानव आपदा की संभावना के कारण बल्कि इन महंगे एचईपी के बह जाने या खुद को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के बहुत अधिक खतरे के कारण भी देखा जा। **पर्यावरण संबंधी चिंताओं का उल्लंघन :** जून 2013 केदारनाथ बाढ़ के बाद, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बंपर से बंपर जलविद्युत परियोजनाओं के तेजी से बढ़ने पर चिंता व्यक्त की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलकनंदा हाइड्रो पावर बनाम अनुज जोशी व अन्य, 2013 की सिविल अपील 6736 के मामले में इस आपदा का स्वत: संज्ञान लिया और अपने निर्णय दिनांक 13-08-2013 में जल विद्युत परियोजनाओं को आगे कोई मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी पारिस्थितिकी में जलविद्युत परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ निकाय का भी गठन किया। विशेषज्ञ निकाय ने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 07-05-2014 के माध्यम से गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 24 प्रस्तावित भावी परियोजनाओं पर रोक लगा दी। निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं (जिसमें विष्णुगाड–पीपलकोटी परियोजना भी शामिल है) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया जाना बाकी है। एमओईएफएंडसीसी ने भी विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्षों को स्वीकार किया और स्वीकार किया कि मौजूदा और निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं ने हिमालयी पारिस्थितिकी को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई है	***परियोजना बांध की सुरक्षा का आकलन किया गया और ओपी 4.37 के अनुसार इसे साफ किया गया। टीएचडीसी ने बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए – नीति अनुपालन से परे – अतिरिक्त उपाय किए हैं। अपनी 2014 की जांच रिपोर्ट में, पैनल ने परियोजना को ओपी 4.37 के अनुपालन में पाया। पैनल ने पाया कि "ओपी/बीपी 4.37 के अनुपालन में, प्रबंधन ने भूकंप, भूस्खलन और चरम मौसम से संबंधित अनुरोध में उठाए गए जोखिमों को कम करने के लिए परियोजना डिजाइन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन चरणों के दौरान टीएचडीसी द्वारा प्रासंगिक अध्ययनों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए। पैनल परियोजना कार्यान्वयन के दौरान तैयार किए जाने वाले अध्ययनों में अनुरोध में उठाए गए संभावित जोखिमों को ध्यान में रखने और संबोधित करने के महत्व को नोट करता है। पैनल ने अपने 2022 के पंजीकरण के नोटिस में यह भी कहा कि "दूसरे अनुरोध से संबंधित गैर–पंजीकरण के नोटिस में, पैनल ने कहा कि 2014 की जांच ने बांध सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित किया [--] /"*** **पृष्ठभूमि, शमन उपाय और वर्तमान स्थिति :** तैयारी के दौरान निम्नलिखित अध्ययन और विश्लेषण किए गए : • *वीपीएचईपी के लिए डाउनस्ट्रीम प्रभाव विश्लेषण : 2008 में, अलकनंदा नदी के प्रवाह की स्थिति और वीपीएचईपी संपत्तियों के साथ–साथ आसपास के क्षेत्रों (अलकनंदा नदी बेसिन, गंगा नदी डाउनस्ट्रीम, आदि) पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हुए बैंक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।* • *अलकनंदा नदी पर बड़े पैमाने पर जलविद्युत –संचयी प्रभाव आकलन (सीआईए): 2012-2013 में, भारत सरकार ने अलकनंदा बेसिन में जलविद्युत विकास का सीआईए आयोजित किया। अध्ययन का एक हिस्सा वाइल्डलाइफ* इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (जैव विविधता पर ध्यान

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
	और जून 2013 बाढ़ की वृद्धि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। एमओईएफएंडसीसी ने 5-12-2014 के अपने हलफनामे में भी विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्षों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि 'यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि 2013 की बाढ़ की भयावहता में एचईपी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है।' जलशक्ति मंत्रालय (तत्कालीन एमओडब्ल्यूआर एंड जीआर) ने भी 31-05-2016 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसने इन परियोजनाओं के निर्माण और इन क्षेत्रों की सुरक्षा और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प से संबंधित चिंताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा किया। यह निम्नानुसार बताता है: *"18.5 इन परियोजनाओं के आसपास का क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अस्थिर और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। इसलिए, किसी भी आपदा के प्रभाव का लोगों, वनस्पतियों और जीवों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जो अनावश्यक और अनुचित है।* *18.8 व्यापक जनहित में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ–साथ प्राचीन पर्यावरण, जैव विविधता, क्षेत्र के साथ–साथ नदी के अद्वितीय पारिस्थितिक चरित्र और सतत विकास और एहतियाती सिद्धांत की अवधारणा के लिए प्रतिबद्धता (जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा दोहराया गया है), इन परियोजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता है।"* तब से, 2013 में, केदारनाथ बाढ़ के कहर, जिसने देश को हिलाकर रख दिया, को देखने के बाद भी विष्णुगढ़–पीपलकोटी परियोजना ने अपने निर्माण कार्य को छिटपुट और अव्यवस्थित तरीके से शुरू किया, भले ही गंगा–हिमालय में एचईपी का मामला अदालती विचाराधीन था और परियोजनाएं ठंडे बस्ते में थीं। यह परियोजना के समर्थकों की उनकी जुनूनी जल्दबाजी, लालच और ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने की इच्छा में पूरी तरह से गैरजिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25-02-2019 के अपने कार्यवृत्त में कहा है कि 'उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों पर कोई नई जल विद्युत परियोजना शुरू नहीं की जाएगी।... *निर्माणाधीन* परियोजनाओं के संबंध में, *एमओडब्लूआर द्वारा अनुशंसित सात परियोजनाओं, जिनके 50% से अधिक पूर्ण होने की सूचना दी गई है (अनुबंध I में सूचीबद्ध), को आगे के निर्माण के लिए लिया जा सकता है।"* ग्रामीणों का कहना है कि बमुश्किल 30 फीसदी काम ही पूरा हो पाया है। कि, कानून (एमओईएफएंडसीसी अधिसूचना दिनांक 18-03-2021) में यह अनिवार्य है कि यदि किसी परियोजना की भौतिक प्रगति उसकी पर्यावरण मंजूरी की समाप्ति के दौरान 50% से कम है, तो उसे नए सिरे से पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए उचित जन सुनवाई प्रक्रिया से गुजरना होगा। हालांकि, टीएचडीसीआईएल ने	केंद्रित) और अध्ययन का दूसरा हिस्सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)–रुड़की (हाइड्रोलॉजिकल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित) द्वारा आयोजित किया गया था। इस अध्ययन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वीपीएचईपी में पर्यावरण प्रवाह (3 एम3/एस से 15-65 एम3/एस), विस्तृत मत्स्य अध्ययन और पारिस्थितिक निगरानी में वृद्धि हुई है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के 2018 के आदेश के अनुरूप संचालन चरण के दौरान मूल्यों को समायोजित किया जाना है। ***पैनल ने अपनी 2014 की जांच रिपोर्ट में पाया कि "प्रबंधन ने परियोजना के लिए एक संचयी प्रभाव मूल्यांकन की तैयारी सुनिश्चित करके और सांस्कृतिक, धार्मिक और जैव विविधता प्रभावों को कम करने के लिए परियोजना में अनुशंसित न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को शामिल करके ओपी/बीपी 4.01 के प्रावधानों का अनुपालन किया" (पैरा 139) .*** *<u>अध्ययन विशेष रूप से बांध की स्थिरता और सुरक्षा को लक्षित करता है</u>* • *डैम ब्रेक रिपोर्ट (2015)।* • *नदी आकारिकी अध्ययन (उत्तराखंड सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से – उत्तराखंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना), उन महत्वपूर्ण स्थानों की सूची प्रदान करना, जिनके लिए नदी प्रशिक्षण कार्यों की आवश्यकता होती है, और उनके लिए नौ महत्वपूर्ण बिंदुओं और डीपीआर का विस्तृत अध्ययन (2018)। नौ में से पांच नदी रूपात्मक कार्य हाल ही में पूरे किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार आगे क्रियान्वयन की कार्रवाई कर रही है।* *<u>2014 की जांच के दौरान अतिरिक्त अध्ययन निरीक्षण पैनल को सौंपे गए</u>* • *भूवैज्ञानिक आधारभूत अध्ययन– टीएचडीसी डिजाइन विभाग द्वारा।* • *बांध नींव प्रणाली का भूकंपीय विश्लेषण– आईआईटी– रुड़की द्वारा।* • *तलछट से निपटने और अनुकूलन अध्ययन– डीएचआई, डेनमार्क द्वारा।* • *साइट विशिष्ट डिजाइन भूकंप पैरामीटर– आईआईटी– रुड़की द्वारा।* *<u>आपातकालीन संचालन प्रक्रियाएं</u>* आपातकाल की प्रकृति के आधार पर कई आपातकालीन प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। इस तरह की प्रक्रियाएं किसी आपात स्थिति के आकलन से लेकर समाप्ति और अनुवर्ती कार्रवाई तक के पूरे क्रम को कवर करती हैं। वीपीएचईपी से सीधे तौर पर जुड़े बाढ़ जोखिमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। *<u>पूर्व चेतावनी प्रणाली</u>*

संख्या	छावा	प्रतिक्रिया
	मई 2021 में एमओईएफएंडसीसी के सामने झूठा दावा किया कि परियोजना ने 51% भौतिक प्रगति हासिल कर ली है। इस झूठे दावे के आधार पर इसे नई पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई। हालांकि, पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने स्वयं अपनी बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 29-07-2020 में परियोजना की भौतिक प्रगति को 30% से कम दर्ज किया है। यह सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण के प्रति उनकी पूरी तरह से असंबद्धता को दर्शाता है; यह अत्यधिक खतरनाक और अस्थिर वातावरण के प्रति उनके आकस्मिक, अवैज्ञानिक और एकसमान रवैये को प्रकट करता है। यह ग्रामीणों को दिखाता है कि टीएचडीसीआईएल पर किसी भी मामले में ईमानदारी से काम करने के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।	जैसा कि 2016 की आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) में परिभाषित किया गया है, एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसके तहत आपातकाल के प्रकार के आधार पर तीन प्रकार की सूचनाएं जारी की जा सकती हैंरू पूर्व–अलर्ट अधिसूचना, चेतावनी अधिसूचना, चेतावनी अधिसूचना। अधिसूचना और संचार की जिम्मेदारी आंतरिक संचार के लिए बांध नियंत्रण कक्ष और राज्य/जिला प्राधिकरणों के साथ संपर्क के लिए योजना विभाग की है। परियोजना के चालू होने पर एक मजबूत 24/7 संचार प्रणाली लागू की जाएगी (डैम टॉप के स्तर से ऊपर स्थायी नियंत्रण कक्ष; लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन, फैक्स, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के साथ)। *फरवरी 2021 में अलकनंदा में अचानक आई बाढ़ के बाद लागू किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय* • फरवरी 2021 में, अलकनंदा की एक अपस्ट्रीम सहायक नदी (ऋषिगंगा) में एक हिमस्खलन से बड़े पैमाने पर अचानक बाढ़ आ गई। • वीपीएचईपी के अपस्ट्रीम में दो एचईपी को महत्वपूर्ण संरचनात्मक नुकसान हुआ और कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई। • वीपीएचईपी काफी हद तक अप्रभावित रहा, हालांकि कोफर बांध बाढ़ के पानी से भर गया था जो इसकी डिजाइन की गई ऊंचाई से 1–1-5 मीटर अधिक था। • **बाढ़ के बाद, टीएचडीसी ने डिजाइन की समीक्षा की और कोफर बांध की ऊंचाई 1,241 मसल से बढ़ाकर 1,246 मसल कर 5 मीटर कर दी।** • अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण संचार को बढ़ाने के लिए, मानव (श्रमिकों, कर्मचारियों, समुदायों) और अवसंरचनात्मक नुकसान को रोकने के लिए, प्रारंभिक चेतावनी प्रोटोकॉल को और अधिक मजबूत बनाया गया और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की गई: ➢ **डेटा संग्रहण : प्रति घंटा (मानसून); अन्यथा दैनिक** ➢ **डेटा ट्रांसमिशन और कंट्रोल रूम : जीएसएम, वायरलेस या वीएसएटी फोन (बांध स्थल, बिजलीघर, टेलरेस सुरंग और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कक्ष के बीच 24/7 कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना)।** ➢ **डाटा प्रोसेसिंग और बाढ़ पूर्वानुमानरूअन्य अपस्ट्रीम परियोजनाओं और संगठनों (एनटीपीसी, सीडब्ल्यूसी, आदि) के सहयोग से** ➢ **पूर्वानुमान और चेतावनी का प्रसाररूनियंत्रण कक्ष और बांध स्थल पहले मध्य कमान और नियंत्रण स्टेशन द्वारा चेतावनी और साथ–साथ अलर्ट जारी करेगा। सायरन अलार्म तैनात।**

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		 फोटो 6- कॉफर डैम की ऊंचाई बढ़ाई गई (2021 अलकनंदा फ्लैश फ्लड के बाद, टीएचडीसी ने डिजाइन की समीक्षा की और कॉफर डैम की ऊंचाई 1,241 मसल से 1,246 मसल की ऊंचाई तक बढ़ाकर 5 मीटर कर दी) फोटो 6.
14ए	**पर्यावरण (बाढ़/जलवायु परिवर्तन)** **बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि के कारण जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) अब व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं** जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में से एक ग्लेशियरों का सिकुड़ना है। विशेष रूप से हिमालय में ग्लेशियरों के दुनिया में कहीं और के मुकाबले तेजी से घटने की सूचना दी गई है। इसलिए नदी के तल और हिमनदी धाराओं में अत्यधिक बाढ़ आने की आशंका है। अध्ययन इन चरम प्रवाहों के परिमाण में वृद्धि और गंगा बेसिन में बाढ़ की घटना की भविष्यवाणी करते हैं। पिघलने वाले ग्लेशियरों के परिणामस्वरूप हिमनदी झीलें (जीएलओएफ) बनती हैं जो किसी भी समय फट सकती हैं, और नदी के बहाव में बाढ़ का कारण बन सकती हैं। 2013 केदारनाथ आपदा में भी यही हुआ था। इस आपदा में न केवल कई एचईपी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, बल्कि सबसे अधिक नुकसान एचईपी के आसपास के क्षेत्रों में भी पाया गया। 2021 में ऋषिगंगा की हिमाच्छादित धारा में चमोली आपदा में ऋषि–गंगा एचईपी का सफाया हो गया और तपोवन–विष्णुगढ़ एचईपी टनों मलबे के नीचे दब गया। **<u>आईआईएससी अध्ययन दिनांक 30.09.2021</u>** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–कानपुर की रिपोर्ट इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन और बांध बनाने जैसी मानवीय गतिविधियां इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। यह दो महत्वपूर्ण सहायक नदियों, भागीरथी और अलकनंदा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पर्वतीय क्षेत्रों पर पिछली	***जलविद्युत परियोजनाओं के समग्र मूल्य और जोखिम के बारे में अनुरोधकर्ताओं की चर्चा बैंक नीतियों के अनुपालन के प्रश्न से परे है। राज्य में जलविद्युत के विकास का व्यापक मुद्दा भारत सरकार के साथ चर्चा और निर्णय का विषय है। इसलिए, जलविद्युत के बारे में अनुरोधकर्ताओं के विचारों पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में प्रबंधन नहीं है।*** ***जहां तक वीपीएचईपी का संबंध है, प्रबंधन नोट करता है कि यह उत्तराखंड राज्य में सात जलविद्युत परियोजनाओं में से एक थी जिसे भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के बाद निर्माण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, एक निर्णय जो निरीक्षण के लिए अनुरोध के संलग्नक 8 में भी परिलक्षित होता है। (संदर्भ पैरा IIc और अनुबंध I) ।***

संख्या	छावा	प्रतिक्रिया
	मानव गतिविधि के प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसमें कहा गया है, "बदलती जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव अलकनंदा बेसिन में अधिक प्रमुख है। हमारा चरम आवृत्ति विश्लेषण भी अलकनंदा बेसिन में विभिन्न वापसी अवधियों के लिए अत्यधिक प्रवाह के परिमाण में वृद्धि का सुझाव देता है। इसके अलावा, देखे गए रिकॉर्ड यूजीबी (ऊपरी गंगा बेसिन), विशेष रूप से अलकनंदा बेसिन में अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि का संकेत देते हैं। **<u>53 वैज्ञानिक अध्ययन दिनांक 10.06.2021</u>** इसके अलावा, पिछले साल दुनिया भर के 53 क्षेत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा 7 फरवरी की बाढ़ पर एक विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट 10 जून 2021 को एक प्रसिद्ध पत्रिका 'विज्ञान' में प्रकाशित हुई है। यह रिपोर्ट भी निम्नानुसार समाप्त हुई; *"चमोली घटना स्वच्छ ऊर्जा विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा शासन, संरक्षण, पर्यावरण न्याय और हिमालय और अन्य उच्च पर्वतीय वातावरण में सतत विकास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। आपदा ने तेजी से अस्थिर क्षेत्र में जलविद्युत बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार से जुड़े जोखिमों को दुखद रूप से प्रकट किया।"।* **<u>एनडीएमए का अध्ययन दिनांक अप्रैल–2022</u>** और अब इसी तर्ज पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भी 22 अप्रैल की अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को उत्तराखंड से जलविद्युत पर निर्भर रहने के बजाय लंबे समय में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। एनडीएमए की रिपोर्ट निम्नलिखित अनुशंसा करती हैरू ष्लंबे समय में, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि यह क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक प्रतीत होता है। उस पर एक अलग अध्ययन विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा सकता है। **2014 – हाल की आपदाओं और नए अध्ययनों को देखते हुए जलविद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता।** इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है क्योंकि चमोली आपदा (हाट चमोली जिले में स्थित है) 2021 में हुई थी, और संदर्भित अध्ययन सभी नए हैं और वर्तमान स्थिति पर अद्यतन हैं और पनबिजली पर पुनर्विचार करते हैं। यहां तक कि आईपी रिपोर्ट में संदर्भित 2013 की रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट ने भी इन चिंताओं को व्यक्त किया था।	

संख्या	छावा	प्रतिक्रिया
15ए	**पिछले दशक में डाउनस्ट्रीम एचईपी के लिए भारी आर्थिक नुकसान** विष्णुगढ़–पीपलकोटी (444 मेगावॉट) की प्रारंभिक परियोजना लागत 2800 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 4900 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा ईएसी मिनट के अनुसार परियोजना की भौतिक प्रगति 30% से कम है। इसके अलावा, हिमालयी इलाके की कठोर पारिस्थितिक चुनौतियों के कारण परियोजना लागत में और अधिक वृद्धि की उम्मीद है। इसी तरह, तपोवन–विष्णुगढ़ (520 मेगावॉट) परियोजना की शुरुआती लागत विष्णुगढ़–पीपलकोटी में 4200 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जो पिछले साल 13,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी, जब परियोजना 70% पूरी हो गई थी। इसके बाद ऋषि–गंगा की बाढ़ में बैराज और सुरंगें मलबे में दब गईं, इस बाढ़ से करीब 1600 करोड़ रुपये का और नुकसान हुआ। इन परियोजनाओं के सामने आने वाली पारिस्थितिक चुनौतियों का पिछले 15 वर्षों का इतिहास, इस अत्यधिक संवेदनशील हिमालयी इलाके में ऐसी परियोजनाओं की आर्थिक गैर–व्यवहार्यता का प्रमाण है। विष्णुगढ़–पीपलकोटी के ऊपर स्थित ऋषिगंगा एचईपी (13.5 मेगावॉट) पूरी तरह से बह गया, फरवरी 2021 में कुल लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।	*वीपीएचईपी की वास्तविक प्रगति अब 60 प्रतिशत से अधिक है।*[10] *अनुरोध में उल्लिखित संख्या गलत है।* *भारत सरकार ने "अलकनंदा–भागीरथी बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं के संचयी प्रभाव का आकलन" पर कमीशन दिया। विभिन्न चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं के संचयी प्रभावों का आकलन करते हुए, रिपोर्ट अलकनंदा नदी बेसिन में अलग–अलग परियोजनाओं के स्थानीय और संचयी प्रभावों को भी स्पष्ट करती है (तालिका 1ए, पृष्ठ 22)। वीपीएचईपी के लिए, जबकि रिपोर्ट में पर्यावरण पर मध्यम से उच्च संचयी प्रभावों का उल्लेख है (अध्ययन में यह भी आकलन किया गया है कि उपचार संभव है), इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि झरनों, पीने के पानी, पानी की गुणवत्ता, सिंचाई, निर्माण पर प्रभाव स्थानीय हैं और या तो नगण्य या कम हैं . रिपोर्ट में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर नगण्य प्रभावों का आकलन किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, रिपोर्ट ने आकलन किया है कि पर्यटन और सामाजिक–आर्थिक पर परियोजना का प्रभाव सकारात्मक होगा।* *प्रबंधन न तो अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में अनुरोध में किए गए अभ्यावेदन को सत्यापित करने की स्थिति में है, जो बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं, और न ही ये अभ्यावेदन किसी भी तरह से बैंक नीति के साथ परियोजना के अनुपालन के आकलन के लिए प्रासंगिक हैं।*
16ए	**2014 आईपी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए मुद्दे** 2014 की रिपोर्ट में ऊपर रिपोर्ट किए गए मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। वास्तव में कार्यकारी सारांश में ही यह काफी स्पष्ट है जहां 'अनुरोध में मुख्य दावे' की रूपरेखा में कहा गया है– *'प्रमुख मुद्दे हैं: कई बांधों के निर्माण और संचालन से पर्यावरणीय प्रभाव; सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व और अलकनंदा नदी के विशेष गुण और परियोजना बाह्यताओं पर विचार। दावों की दूसरी स्थिति स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक प्रभावों से संबंधित है। विशेष रूप से ये आसपास के गांवों में पानी के नुकसान आदि के मुद्दों, संरचनाओं से संबंधित जोखिम, भूस्खलन और भूकंप, जलीय जीवन के लिए जोखिम और परिवर्तित प्रवाह से पारिस्थितिकी, और तलछट के निकलने के प्रभाव को संदर्भित करते हैं। स्थानीय सामाजिक–आर्थिक प्रभावों में शामिल हैं : पुनर्वास और आजीविका की बहाली, लिंग प्रभाव और स्थानीय लाभ साझा करना।"* 2014 की जांच मुख्य रूप से हाटसारी बस्ती से संबंधित थी न कि हाट गांव से। केवल अलकनंदा नदी के ही सांस्कृतिक महत्व को संबोधित किया गया था।	**निरीक्षण पैनल की टिप्पणियां और स्थापनाएं, 20 अप्रैल, 2022:** 20 अप्रैल, 2022 को निरीक्षण के लिए दूसरे अनुरोध के गैर–पंजीकरण की सूचना में, पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि "इस अनुरोध में उठाई गई चिंताएं – ख्पुनर्वास और आजीविका पुनर्वास, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा की स्थिति, भौतिक और सांस्कृतिक संसाधन, पर्यावरण मंजूरी , डराने–धमकाने और प्रतिशोध के आरोप, – 2014 में पहले से ही जांच किए गए मुद्दों से संबंधित है जब पैनल को पिछला अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसलिए, उन्हें नए साक्ष्य नहीं माना जा सकता है जो कि पूर्व अनुरोध के समय ज्ञात नहीं थे, जैसा कि निरीक्षण पैनल संकल्प के तहत आवश्यक है।
17ए	**पूर्व संपर्क –हां, चिंताओं को विश्व बैंक प्रबंधन को विधिवत सूचित किया गया था**। हमारे असंतोष के बारे में सभी प्रासंगिक	*यह प्रबंधन का विचार है कि अनुरोध में उठाए गए नुकसान/संभावना के सभी परियोजना–विशिष्ट दावों को बैंक नीतियों के अनुरूप शमन और प्रबंधन उपायों के माध्यम से*

[10] बैंक ऋण द्वारा कवर किए गए केवल दो परियोजना घटकों पर विचार करने पर 33 प्रतिशत के अनुरूप।

संख्या	छावा	प्रतिक्रिया
	संचार मार्च 2022 की हमारी पहली शिकायत में पहले ही निरीक्षण पैनल को सूचित कर दिया गया था। जहां तक कार्यवृत्त से पता चलता है, विश्व बैंक की टीम और टीएचडीसीएल के साथ हमारी बैठक बेनतीजा रही है।	***या तो पहले ही निस्तारित किया जा चुका है या वर्तमान में निस्तारित किया जा रहा है।*** टीएचडीसी और टास्क टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के साथ संचार के खुले चौनल भी बनाए रखे हैं कि उनकी चिंताओं को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। टीएचडीसी ने हाट के समुदाय सहित सभी परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ निरंतर आधार पर जुड़ने के विशिष्ट कार्य के साथ दो सामुदायिक सहायकों को नियुक्त किया है। दिसंबर 2021, मार्च 2022 और जुलाई 2022 सहित पहली बार अपनी चिंताओं को उठाए जाने के बाद से टास्क टीम हाट समुदाय के प्रतिनिधियों से कई बार मिल चुकी है। जुलाई 2022 में साइट के दौरे के दौरान, पुनर्वास स्थलों में रहने वाले समुदाय ने कुछ अतिरिक्त चिंताओं को उठाया, जिस पर टीएचडीसी के साथ एक प्रभावी समाधान खोजने के लिए चर्चा की गई। उदाहरण के लिए, समुदाय ने पिछले छोर के घरों के लिए खराब पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठायारू टीएचडीसी ने पाइप के व्यास को बढ़ाकर पानी की आपूर्ति में वृद्धि की। समुदाय की मांग पर पुनर्वास कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति शुरू में 20,000 लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 40,000 लीटर प्रतिदिन कर दी गई है और अब यह 64,000 लीटर प्रतिदिन है। समुदाय ने पुनर्वास कॉलोनियों में क्षतिग्रस्त आंतरिक रास्तों का मामला भी उठाया। टीएचडीसी ने संकेत दिया कि इसने (i) दोनों पुनर्वास कॉलोनियों के आंतरिक मार्गों की मरम्मत के साथ–साथ (ii) सामुदायिक वन तक पहुँचने के लिए एक मार्ग के लिए कार्य आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। टीएचडीसी किसी भी शेष चिंताओं को हल करने के लिए समुदाय और जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में रहने के लिए प्रतिबद्ध है।
18ए	**अतिरिक्त मुद्दे**	**हेलंग गांव** ***जबकि परियोजना या अनुरोध से संबंधित नहीं है, प्रबंधन जुलाई 2022 में हेलंग गांव में हुई एक घटना से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता है, क्योंकि मीडिया के कुछ वर्गों में इसे गलत तरीके से परियोजना से जोड़ा गया है।*** हेलंग गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे वीपीएचईपी बांध से लगभग 2 किमी ऊपर की ओर स्थित है। 30 अप्रैल, 2022 को हेलंग के निवासियों ने जिला प्रशासन से गांव में सार्वजनिक भूमि पर सामुदायिक खेल का मैदान बनाने का अनुरोध किया। जिला प्रशासन ने टीएचडीसी से जमीन को समतल करने में मदद करने के लिए खुदाई की कुछ सामग्री का उपयोग करके खेल के मैदान को विकसित करने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2022 को जिला प्रशासन की उपस्थिति में समतलीकरण एवं फेंसिंग का कार्य प्रारंभ किया गया। प्रबंधन समझता है कि उस दिन काम के दौरान खेल के मैदान के विकास का विरोध करने वाले समुदाय के कुछ सदस्यों का पुलिस से विवाद हो गया था जिन्हें

संख्या	दावा	प्रतिक्रिया
		जिला प्रशासन ने वहां तैनात किया था। राज्य सरकार ने घटना की जांच की घोषणा की है। गौरतनब है कि, घटना किसी बैंक–वित्तपोषित परियोजना कार्य से संबंधित नहीं है, बल्कि जिला अधिकारियों द्वारा अनुरोधित सामुदायिक नागरिक कार्यों से संबंधित है। ग्राउंड लेवलिंग के लिए वीपीएचईपी टनल से निकाली गई सामग्री की आपूर्ति सहित निर्माण के समर्थन में टीएचडीसी की भूमिका पूरी तरह से परियोजना से संबंधित नहीं है। ऐसा कोई भी सुझाव कि टीएचडीसी खेल के मैदान का उपयोग प्रॉक्सी मक–डंपिंग साइट के रूप में कर रहा है, गलत है। परियोजना ने उत्खनित मलबे को सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया है और उस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त स्थान या मलवा प्राप्त करने वालों की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हेलंग कार्य।

अनुलग्नक 2.
उन्नत मंदिर परिसर के निर्माण के बाद भूनिर्माण योजना

अनुलग्नक 3.

गेबियन वॉल सहित मंदिर लैंडस्केप का क्रॉस–सेक्शन

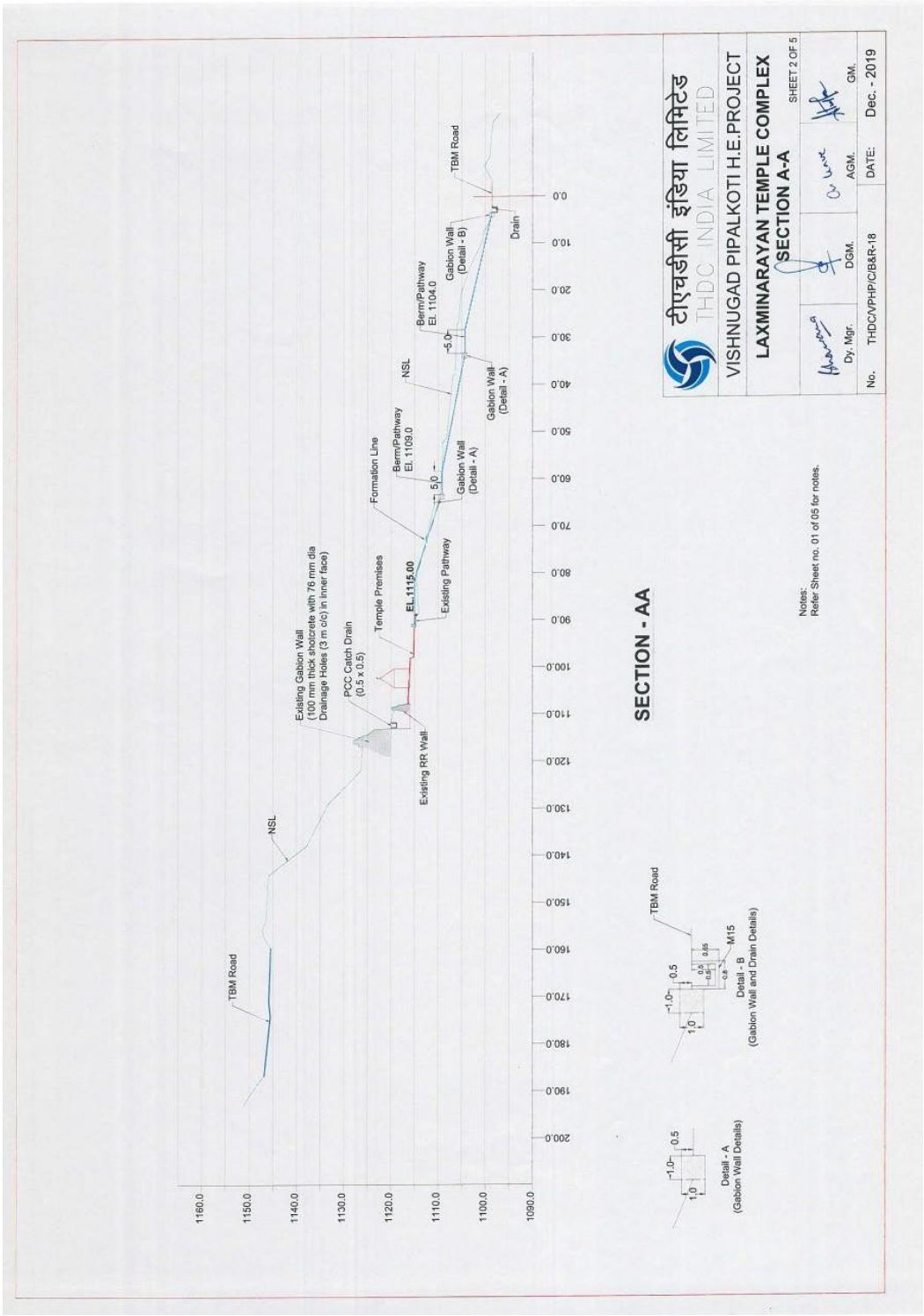

अनुलग्नक 3.

गेबियन वॉल का इंजीनियरिंग डिजाइन

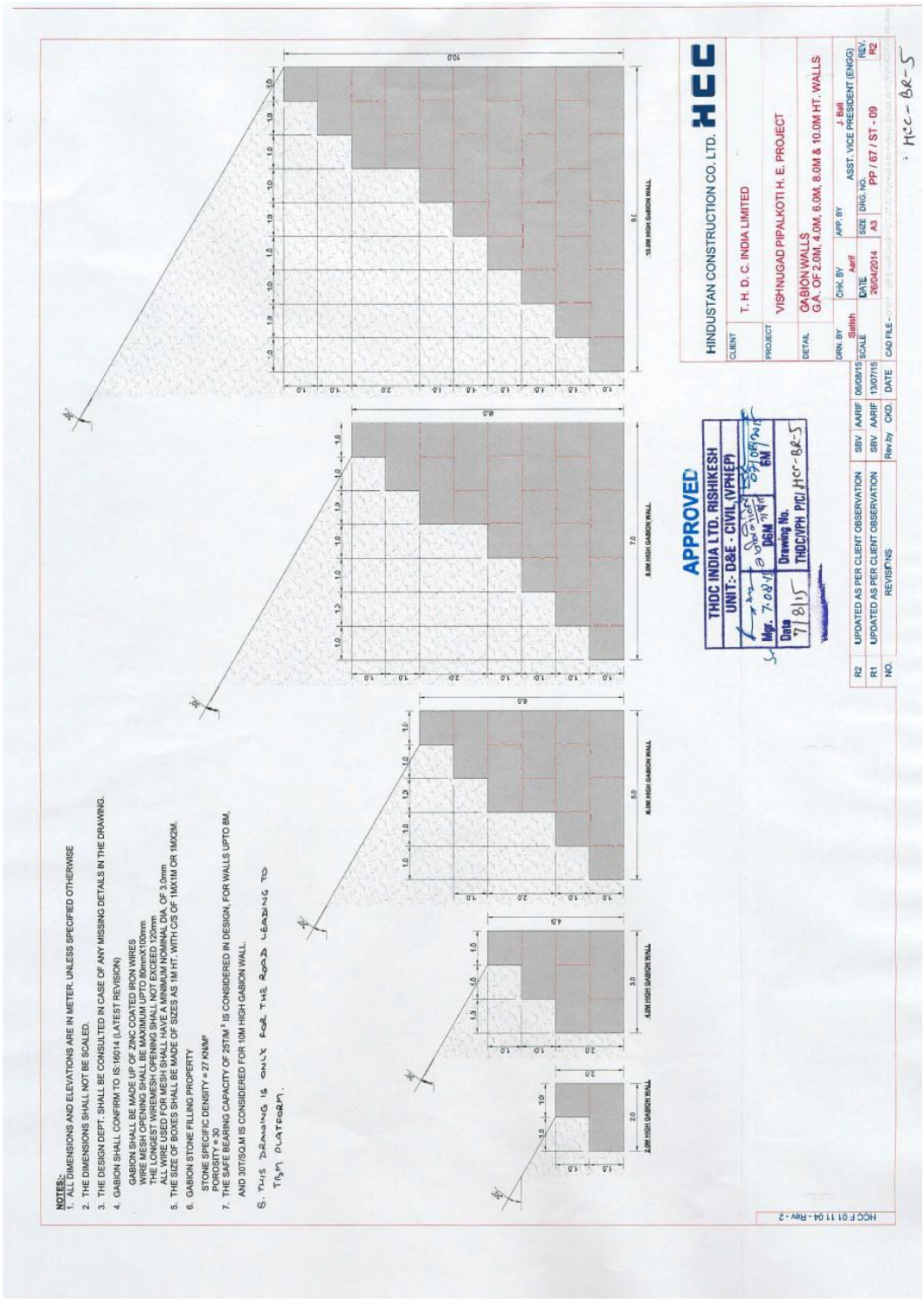

नक्शा

आईबीआरडी

35230

परियोजना : भारत विष्णुगाड–पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (वीपीएचईपी)